ई-मैल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम - दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

शहरों को चाहिए 20 हजार करोड़, पंचायतों ने मांगे अधिकार

15 वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में प्रतिनिधियों ने उठाई मांग, वित्त आयोग के अध्यक्ष ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड के शहरों और गांवों के समान रूप से विकास को लेकर शहरी निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को वित्त आयोग से खासी उम्मीदें हैं। बुधवार को 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में इन प्रतिनिधियों ने राज्य के विकास के एजेंडे पर चर्चा की और इससे जुड़ी मांगों को साझा किया। शहरी क्षेत्रों के विकास और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीधे-सीधे 20039.75 करोड़ रुपये की डिमांड रखी गई। वहीं, पंचायत प्रतिनिधियों ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के तहत समान वित्तीय अधिकारियों की मांग को उठाया। बता दें कि 14 वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2019-20 में समाप्त हो रहा है। 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक का पैसा राज्यों को मिलेगा।

वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने अपनी टीम के साथ पहले नगर निकाय और उसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में एनके सिंह ने बताया कि झारखंड के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त आयोग हर संभव मदद करेगा। कहा, नगर निकाय और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने जो मांगें रखी हैं, उन पर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा संयुक्त रूप से सौंपे गए प्रतिवेदन की चर्चा करते हुए बताया कि ग्राम पंचायत के तीनों स्तर जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्रामसभा के लिए आवश्यकतानुसार समानुपातिक राशि जारी करने का अनुरोध किया गया है। यह अच्छा सुझाव है। शहरी क्षेत्रों के विकास के एजेंडे पर भी मेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत प्रतिनिधियों से बात हुई है। इसमें शहरी क्षेत्रों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वित्तीय मदद बढ़ाए जाने पर बात हुई है। बैठक में वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, वित्त आयोग के सदस्य शशिकांता दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. रमेश सिंह, सचिव अरविंद मेहता आदि थे।

13 वें वित्त आयोग में 60 प्रतिशत वित्तीय अधिकार ग्रामसभा को था

14 वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2019-20 में हो रहा है समाप्त

अप्रैल 2020 से मार्च 2025 तक का पैसा राज्यों को मिलेगा

रांची में बुधवार को 15वें वित्त आयोग की बैठक में शामिल वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह व अन्य अधिकारी • जागरण

आमने-सामने, गांव-शहर

ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आयोग ने 6046 करोड़ किए थे स्वीकृत, अब तक 2707 करोड़ जारी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए 14 वें वित्त आयोग ने 6046.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे। इसमें अब तक 2707.95 करोड़ की स्वीकृति दी गई है जबकि विकास मद की इस राशि से 1865.41 करोड़ रुपये व्यय हुए हैं।

इन सेक्टर पर खर्च होंगे 20 हजार करोड़ रुपये

मद	राशि (करोड़ रु. में)
पेयजलापूर्ति	3742.78
सीवरेज-ड्रेनेज	5551.89
शहरी पथ	2834.23
रिंग रोड	1236.00
सिटी बस	674.85
जेनरल ग्रांट	6000
कुल	20039.75

शहरों के लिए 892 करोड़ स्वीकृत, 699 करोड़ मिले

14 वें वित्त आयोग के पिछले तीन वित्तीय वर्षों के कार्यकाल में बेसिक ग्रांट और परफार्मेंस ग्रांट के मद में कुल 892.17 करोड़ की स्वीकृति मिली। इनमें से 699.42 करोड़ रुपये शहरी निकायों को जारी किए गए।

जनसंख्या और परफार्मेंस को न बनाएं आधार

निकाय के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से पीने के पानी, सड़क, नाली, कचरा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बताया गया कि 14 वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत की गई थी, जो उचित नहीं था। प्रतिनिधियों ने आवश्यकता के आधार पर राशि जारी करने की बात कही। कहा कि झारखंड में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत अभी शैशव अवस्था में है। ऐसे में परफार्मेंस आधारित राशि का निर्धारण नहीं होना चाहिए।

पंचायत के तीनों स्तर को मिले वित्तीय अधिकार

वित्त आयोग के साथ बैठक में पंचायत प्रतिनिधियों ने पंचायतों को समान अधिकार देने की मांग उठाई। जिससे आयोग भी काफी हद तक संतुष्ट नजर आया। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट कहा कि 13 वें वित्त आयोग में 60 प्रतिशत वित्तीय अधिकार ग्रामसभा को था, 20 प्रतिशत जिला परिषद और 20 प्रतिशत पंचायत समिति को था। लेकिन 14 वें वित्त आयोग की रिपोर्ट की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में दो स्तर को वित्तीय अधिकार से मुक्त कर दिया गया। तर्क दिया कि पंचायत समिति और जिला परिषद को वित्तीय अधिकार न होने से उस स्तर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वे अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। जनता मुखिया की तर्ज पर पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्य से विकास कार्यों की उम्मीद रखती है। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मियों की कमी है, जिससे योजनाओं को लागू करने में कठिनाई आ रही है।

शहरी विकास

फैक्ट फाइल

- झारखंड की कुल आबादी का 24.05 फीसद हिस्सा शहरों में निवास करता है।
- झारखंड के शहरों में 2.3 फीसद की दर से बढ़ रही शहरी आबादी।
- कुल 49 स्थानीय शहरी निकायों में 79.33 लाख लोग बसते हैं।
- निकायों को सरकार द्वारा 18 तरह की शक्तियां प्रदान की गई है। इनमें अर्बन प्लानिंग, रोड एवं पुलों का निर्माण, शहरी जलापूर्ति, फायर सर्विस, अर्बन फारेस्ट्री, गरीबी उन्मूलन, बुनियादी सुविधाएं, स्लम विकास, स्वच्छता एवं सफाई आदि।

126 फीसद बढ़ा राजस्व

स्थानीय शहरी निकायों ने अपने आय स्रोत में 14वें वित्त आयोग के अबतक के कार्यकाल में अपने आंतरिक राजस्व स्रोत में 126 फीसद का इजाफा किया है। नगर विकास विभाग की एक अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2015-16 की में कुल 92.14 करोड़ रुपये की राजस्व उगाही हुई थी, जो 2017-18 में 208.53 करोड़ हो गई।

42 फीसद आबादी को पानी

नगर विकास एवं आवास विभाग की रिपोर्ट की बात करें तो बुनियादी सुविधाओं के राष्ट्रीय बेंचमार्क पर झारखंड काफी पीछे चल रहा है। टैप वाटर स्रोत का राष्ट्रीय औसत 70.6 फीसद है, वहीं झारखंड में यह 41.6 फीसद पर सिमटा है। सिवरेज का भी हाल बुरा है।

कृषि की समीक्षा बैठक टली

राब्यू, रांची : मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली बुधवार को प्रस्तावित कृषि की समीक्षा बैठक फिलहाल टाल दी गई है। अब यह बैठक अगले सप्ताह होने की उम्मीद है।

सीएम ने दिया रात्रि भोज

रात्रि भोज में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह का स्वागत करते मुख्यमंत्री रघुवर दास

राज्य ब्यूरो, रांची : वित्त आयोग की टीम को मुख्यमंत्री रघुवर दास की ओर से बुधवार को रात्रि भोज दिया गया। इस भोज में राज्य के कई आला अफसरों ने भी शिरकत की। इससे पूर्व होटल रेडिशन ब्लू में पर्यटन, कला संस्कृति एवं खेलकूद विभाग की ओर से आयोजित संस्कृति संध्या का भी टीम के सदस्यों ने लुत्फ उठाया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष दिनेश उरांव, मंत्री सीपी सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी व कृषि मंत्री रणधीर समेत कई लोग मौजूद थे।

आज सरकार के साथ आयोग करेगा बैठक

राब्यू, रांची : 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ गुरुवार को होने वाली बैठक में राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार 1.75 लाख करोड़ की अनुदान मांगे रख सकती है। पूर्व में 14 वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य सरकार ने 1.42 लाख करोड़ की अनुदान मांगें रखी थी। बता दें कि 14 वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2019-20 को समाप्त हो रहा है। 15 वें वित्त आयोग की सिफारिश पर ही राज्य सरकार को इसके बाद के अगले पांच सालों (2020-25) के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय मदद मिलेगी। आयोग की टीम राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक कर उनका फीडबैक लेगी।

धनबाद मेयर ने की स्पेशल पैकेज की मांग

राज्य ब्यूरो, रांची : धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने 15 वें वित्त आयोग से शहरी निकायों के ढांचे को सुधारने और यहां मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए स्पेशल पैकेज की मांग की है। बुधवार को वित्त आयोग के साथ बैठक में उन्होंने तर्कों के साथ अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट इंडेक्स के मानक से झारखंड साथ फीसद पीछे है। झारखंड में पानी की समस्या का विशेषतौर पर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां लोग दूधिया (अभ्रक मिश्रित), लाल (लौह अयस्क मिश्रित) और काला (कोयला मिश्रित) पानी पीने को मजबूर हैं।

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक भास्कर
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रांची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

15वें वित्त आयोग की 17 सदस्यीय टीम झारखंड दौरे पर, नगर विकास ने तैयार किया शहरों के विकास का रोडमैप

शहरों में इनर सर्कुलर रिंग रोड, सीवरेज-ड्रेनेज बस व जलापूर्ति के लिए 20 हजार करोड़ मांगेगा झारखंड

सिटी रिपोर्टर | रांची

राजधानी रांची सहित राज्य के सभी शहरों में आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए नगर विकास विभाग केन्द्र सरकार से 20 हजार करोड़ रुपए की मांग करेगा। विभाग ने इसके लिए सभी शहरों की जरूरत के हिसाब से असेस्मेंट किया है। 15 वें वित्त आयोग के सदस्यों के समक्ष नगर विकास विभाग के अधिकारी योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। रांची में वाटर सप्लाई योजना, सीवरेज-ड्रेनेज, इनर सर्कुलर रिंग रोड और सिटी बस के लिए फंड की मांग की जाएगी। इसके अलावा धनबाद में रोड, जलापूर्ति सहित अन्य योजनाओं के लिए फंड की मांग की जाएगी। राज्य के सभी 49 नगर निकायों और नए प्रस्तावित 45 निकायों में जलापूर्ति सिस्टम, सीवरेज-ड्रेनेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, रिंग रोड बनाने सहित अन्य योजनाओं के लिए फंड की मांग की जाएगी। विभाग द्वारा तैयार प्रस्ताव में 3742 करोड़ रुपए वाटर सप्लाई के लिए, 5551 करोड़ रुपए फुटपाथ के साथ सीवरेज-ड्रेनेज बनाने, 2834 करोड़ रुपए अर्बन रोड, 1236 करोड़ रुपए इनर सर्कुलर रिंग रोड और रिंग रोड के लिए, 674 करोड़ रुपए सिटी बस की खरीदारी के लिए मांगी जाएगी। इसके अलावा 6 हजार करोड़ रुपए ग्रांट के रूप में मांगा जाएगा, जिसे विभिन्न मद में निकायों को दिया जाएगा।

2.3 प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष बढ़ रही शहरी आबादी

नगर विकास विभाग तेजी से बढ़ती शहरी आबादी का हवाला देते हुए फंड की मांग करेगा। देश में 31.2 प्रतिशत लोग शहर में निवास कर रहे हैं, वहीं झारखंड में करीब 24.5 प्रतिशत लोग शहरों में निवास कर रहे हैं। प्रतिवर्ष 2.3 प्रतिशत की दर से शहरी आबादी बढ़ रही है। फिलहाल शहर में 79.33 लाख लोग निवास कर रहे हैं। इसे देखते हुए 45 नए शहर बनाने का प्रस्ताव है। शहरों में निवास करने वालों के लिए अभी भी मुलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जबकि सबसे अधिक टैक्स शहरी क्षेत्र से सरकार को मिल रहा है। इसलिए आयोग के समक्ष फंड देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके अलावा अन्य कई मांगे रखी जाएंगी।

सीएम, अफसरों और राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक आज

15 वें वित्त आयोग की टीम रांची पहुंची। उनके सम्मान में रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें वित्त आयोग के अध्यक्ष व मुख्यमंत्री एक-दूसरे मिले।

रांची पर सबसे अधिक जोर

- 9 वार्ड में सीवरेज-ड्रेनेज योजना पर काम चल रहा है राजधानी के जोन वन में। शेष 44 वार्ड जोन 2,3 और 4 के अन्तर्गत आते हैं। यहां सीवर लाइन बिछाने के लिए फंड नहीं है।
- 50 किलोमीटर इनर सर्कुलर रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव मास्टर प्लान में है, लेकिन फंड के अभाव में आज तक इसका डीपीआर भी नहीं बना।
- 100 नई सिटी बस खरीदने की योजना है राजधानी के लिए। फिलहाल 96 सिटी बस है नगर निगम के पास। इसमें मात्र 30 बसें चलती है।

शहरी सुधार कार्यक्रम बना आधार

- शहरी विकास के लिए फंड लेने के लिए शहरी सुधार कार्यक्रम को आधार बनाया गया है। सभी निकायों से 92.14 करोड़ रुपए मिलते थे, जो बढ़ कर 208 करोड़ हो गया है। रांची में 6 करोड़ रुपए सालाना से टैक्स बढ़कर 50 करोड़ रुपए हो गया है।
- प्रोपर्टी टैक्स असेस्मेंट रूल्स को रिवाइज्ड करते हुए एरिया बेस्ड सेल्फ असेस्मेंट सिस्टम लाग किया गया। इससे लोगों को अपने प्रॉपर्टी का टैक्स स्वयं तय करने का अधिकार मिला।
- प्रोपर्टी टैक्स और वाटर यूजर चार्ज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया। आउटसोर्स कंपनी के माध्यम से टैक्स लेने के लिए जन सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई।

इधर, निकायों और पंचायतों ने मांगा विशेष पैकेज, आयोग के अध्यक्ष बोले-

जिला परिषदों को भी पंचायतों की तरह मिलेंगे पैसे

रांची | 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि पंचायत समिति और जिला परिषद को भी पंचायतों की तरह राशि मिलेगी। आयोग ग्राम पंचायत के तीनों स्तरों पर अलग-अलग पैसे देने की अनुशंसा करेगा।

बुधवार को तीन दिवसीय दौरे पर रांची आने के बाद एनके सिंह ने कहा कि आयोग के प्रतिनिधिमंडल के साथ नगर निकाय प्रतिनिधियों और पंचायत प्रतिनिधियों की अलग-अलग हुई दोनों बैठकें काफी सकारात्मक रही। इन लोगों ने काफी अच्छे सुझाव दिए। खासकर पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि 14वें वित्त आयोग के पैसे पंचायतों को मिल रहें हैं, पर अन्य दो स्तर पंचायत समिति (प्रखंडों की कमेटी) और जिला परिषद को इससे वंचित रखा गया है। कहा कि 14वें वित्त आयोग के इस फैसले पर आयोग फिर से विचार करेगा। सिंह ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों ने सामूहिक रूप से सुझाव पत्र दिया है।निकाय प्रतिनिधियों मेयर-डिप्टी मेयर आदि ने पानी और सीवरेज पर विशेष पैकेज मांगा। इन विषयों पर गुरुवार को सीएम रघुवर दास से बात होगी।

बैठक में आयोग की ओर से अध्यक्ष, एसके दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. अशोक लाहिड़ी, डॉ. रमेशचंद, अरविंद मेहता, मुखमित सिंह भाटिया, डॉ. रवि कोटा, एटोनी साइरिका, भरत भूषण गर्ग, गोपाल प्रसाद, आयुष्मान मिश्रा, स्वेता सत्या, नीतीश सैनी, संदीप कुमार, हरि दत्त आदि थे। राज्य के विकास आयुक्त अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, वित्त सचिव भी थे।

झारखंड के लोग काले, सफेद और लाल पानी पीने को मजबूर

नगर निकाय प्रतिनिधियों की ओर से धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि झारखंड में जहां कोयला है, वहां काला पानी, जहां अबरख है वहां सफेद पानी और जहां लौह अयस्क है वहां लोग लाल पीने को अभिशप्त हैं। यहां के लोगों को शुद्ध पानी नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या है। चाईबासा नगर परिषद के अध्यक्ष मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि महज 25 प्रतिशत लोगों तक टैप वाटर से पानी पहुंच पाता है। रामगढ़ के विनोद तिवारी ने नगरीय सुविधाओं के विकास की बात उठाई। गिरिडीह के डिप्टी मेयर प्रकाश राम ने जल निकासी की समस्या बताई। इनके अलावा रांची की मेयर आशा लकड़ा, मधुपुर की लतिका मुर्मू, पाकुड़ के सुनील सिन्हा, लातेहार की सीतामणि तिर्की ने भी बैठक के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया।

प्रतिनिधियों ने कहा- शैशवावस्था में हैं झारखंड यहां विकसित राज्यों का फार्मूला न अपनाएं

रांची | प्रदेश के चयनित निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों ने बुधवार को 15वें वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में कहा कि झारखंड के नगर निकाय और पंचायत शैशवावस्था में हैं, ऐसे में यहां पर विकसित राज्यों का फार्मूला न अपनाया जाए। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने उन्हें भरोसा दिलाया कि आयोग मदद करेगा। निकाय प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सड़क, नाली, पीने के पानी की समस्या,शहरी कचड़ा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक के समापन पर नगर विकास सचिव अजय कुमार ने कहा कि टीम ने पेयजल, जलनिकासी और स्वच्छता के क्षेत्र में खर्च बढ़ाने की जरूरत को समझा है। देर रात आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में अधिकारी शामिल हुए।

पंचायत प्रतिनिधियों ने रखी मांग

1. 14वें वित्त आयोग ने जिला परिषद और पंचायत समिति को अनुदान नहीं दिया है। इससे विकास प्रभावित है।
2. जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत को उनके सौंपे गए काम के अनुरूप पर्याप्त संख्या में मानव संसाधन मिले
3. मार्केट कांप्लेक्स, हाट, बस पड़ाव, विवाह मंडप, छोटे-बड़े पर्यटन स्थल का विकास के लिए एक मुश्त राशि मिले
4. बीआरजीएफ की तर्ज पर उग्रवाद प्रभावित जिलों के बुनियादी सुविधाओं के समग्र विकास के लिए राशि दी जाए।
5. प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों को पैसे मिले।
6. 2011 की जनगणना के आधार पर झारखंड की पंचायती राज संस्थाओं को एक निर्धारित अनुपात में राशि दी जाए।
7. कतिपय आदिम जनजातियां विलुप्त के कगार पर हैं, इनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ने के लिए एक विशेष फंड दिया जाए।

आयोग ने पाया पेयजल, जल निकासी व स्वच्छता में खर्च बढ़ाने की जरुरत है : सचिव

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103/

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – हिन्दुस्तान
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

नगर निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ की बैठक, प्रतिनिधियों ने रखीं आवश्यकता के आधार पर राशि देने की मांग

वित्त आयोग ने विकास में मदद का दिया भरोसा

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने झारखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। नगर निकाय और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को होटल रेडिशन ब्लू में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष जो मांगें रखी गई है उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए राशि की आवश्यकता होती है। आयोग का प्रयास रहेगा कि राशि के अभाव में राज्य का विकास बाधित नहीं हो। नगर निकाय और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने आयोग को अपने क्षेत्र की समस्याओं से अवगत कराया।

नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने पेयजल, सड़क, नाली, कचड़ा प्रबंधन, पर्यटन स्थलों की समस्या रखीं। प्रतिनिधियों ने कहा कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत किया गया था, जबकि आवश्यकता के आधार पर राशि मिलनी चाहिए थी।

प्रतिनिधियों का कहना था कि झारखंड में नगर निकाय और ग्राम पंचायत शैशव अवस्था में है, इसलिए यहां विकसित राज्यों की तरह परफॉर्मेंस आधारित राशि निर्गत नहीं होनी चाहिए।

बैठक में सदस्य शक्तिकांत दास, डॉ अनुप सिंह, डॉ अशोक लहरी, डॉ रमेश चंद, सचिव अरविन्द मेहता, संयुक्त सचिव मुखमीत सिंह भाटिया, डॉ रवि कोटा, आर्थिक सलाहकार एंटोनी सेरिएक, निदेशक गोपाल प्रसाद तथा राज्य सरकार की ओर से विकास आयुक्त डीके तिवारी, अपर वित्त सचिव सुखदेव सिंह और वित्त सचिव (व्यय) सतेन्द्र सिंह मौजूद थे।

रेडिसन ब्लू में आयोजित रात्रि भोज में स्पीकर दिनेश उरांव, मंत्री सीपी सिंह, रामचंद्र चंद्रवंशी व रणधीर सिंह मौजूद थे। इसके अलावा मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी समेत विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। मौके पर पर्यटन विभाग की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था।

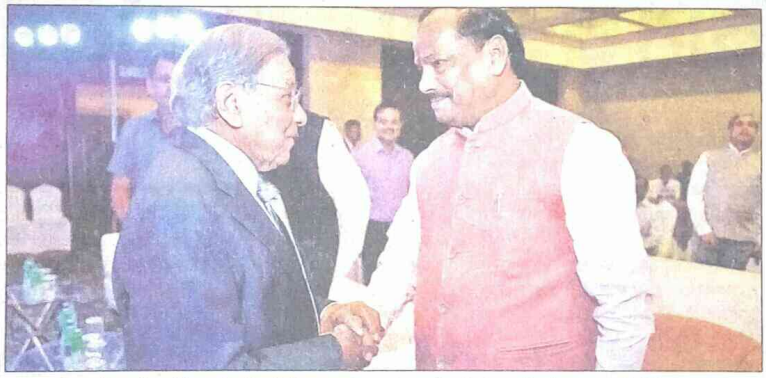

बुधवार को एक होटल में आयोजित रात्रि भोज में सीएम रघुवर दास से हाथ मिलाते वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह।

मुख्यमंत्री ने दिया रात्रि भोज

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों को होटल रेडिसन ब्लू में रात्रि भोज दिया। इससे पहले इनके सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सीएम के साथ बैठक आज

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दो अगस्त को होटल रेडिसन ब्लू में सीएम और मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक 10 बजे शुरू होगी। ढाई बजे से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे।

जमशेदपुर में बैठक कल

तीन अगस्त को जमशेदपुर के एक्सएलआरआई में बैठक रखी गई है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और अधिकारियों के अलावा एक्सएलआरआई के प्रोफेसर आदि शामिल होंगे।

नगर विकास विभाग ने मांगा 20,039 करोड़

रांची। नगर विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग से राज्य के नगर निकायों में जलापूर्ति, सिवरेज-ड्रेनेज, सड़क, रिंग रोड और सिटी बस के लिए अगले पांच वित्तीय वर्षों (2020-25) में 20,039.75 करोड़ रुपये की मांग की है। बुधवार को एक होटल में 15वें वित्त आयोग के साथ नगर निकायों के प्रतिनिधियों की हुई बैठक में विभाग ने यह मांग रखी है।

विभाग ने आयोग से जलापूर्ति के लिए 3742.78 करोड़, सिवरेज-ड्रेनेज के लिए 5551.89 करोड़, सड़क के लिए 2834.23 करोड़, रिंग रोड के लिए 1236 करोड़, सिटी बस के लिए 674.85 करोड़ तथा नगर निकायों के लिए 6000 करोड़ रुपये की मांग की है।

नगर निकायों के प्रतिनिधियों ने आयोग से कहा कि झारखंड के खनिजों से दूसरे राज्यों को विकास हो रहा है, जबकि यहां के लोगों को शुद्ध पेयजल नसीब नहीं है। शहरी क्षेत्रों के लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है। इसी तरह दूसरी बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभा है। सड़क का समुचित प्रबंध नहीं है सिवरेज-ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं है रिंग रोड नहीं होने से शहर होकर ब वाहन गुजरते हैं, जिससे जाम व समस्या उत्पन्न होती है। वित्त आयो राज्य की आबादी के आधार पर ग्रांट दे है, जो उचित नहीं है। आयोग के अध्य ने प्रतिनिधियों की बातों को गंभीरता सुना और उनकी मांगों पर विचार कर का भरोसा दिलाया।

बैठक में रांची की मेयर आश लकड़ा, धनबाद के मेयर चन्द्रशेख अग्रवाल, गिरिडीह के डिप्टी मेयर र प्रकाश राम, चास के मेयर बब पासवान समेत अन्य थे।

मांग

- वित्त आयोग के साथ नगर निका के प्रतिनिधियों की हुई बैठक
- आयोग से जलापूर्ति के लिए 3742.78 करोड़ रुपए की मांग

राज्य सरकार आज रखेगी मांग

रांची। राज्य सरकार 15वें वित्त आयोग के समक्ष 1.75 लाख करोड़ की मांग रख सकती है। सरकार ने चिकित्सा, शिक्षा, सड़क तथा शहरी एवं ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए अगले पांच वित्तीय वर्षों के लिए करीब 1.75 लाख करोड़ का मसौदा तैयार किया है, जिसे गुरुवार को आयोग को सौंपा जाएगा।

15वें वित्त आयोग वित्तीय वर्ष 2020-25 के लिए केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी तय करने से पहले राज्य सरकारों के साथ-साथ रायशुमारी कर रहा है। आयोग की 18 सदस्यीय टीम इसी सिलसिले में बुधवार को झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर आयी है। पहले दिन नगर निकाय और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई। गुरुवार को मुख्यमंत्री, मंत्रियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। शुक्रवार को जमशेदपुर में एक्सएलआरआई के प्रोफेसर तथा अधिकारियों के साथ बैठक करेगी।

आयोग राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए मसौदे को ध्यान में रखकर केन्द्र सरकार से केन्द्रीय करों में झारखंड की हिस्सेदारी की अनुशंसा करेगी। 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2019 में समाप्त हो रहा है।

मसौदा तैयार

- सरकार करीब 1.75 लाख करोड़ का मसौदा किया है तैयार
- आयोग की 18 सदस्यीय टीम झारखंड दौरे पर आयी है

पंचायत प्रतिनिधियों ने रखी अपनी बात

रांची। पंचायत प्रतिनिधियों ने 15वें वित्त आयोग के समक्ष 10 मांगें रखी हैं। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की अध्यक्षता में बुधवार को होटल रेडिसन ब्लू में पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक हुई। प्रतिनिधियों ने 14वें वित्त आयोग द्वारा जिला परिषद और पंचायत समिति की उपेक्षा करने पर आपत्ति जताई। कहा कि 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्र सरकार से सिर्फ ग्राम पंचायत को ही राशि मिल रही है। जिला परिषद और पंचायत समिति को इससे वंचित रखने के कारण विकास पर असर पड़ा है। सभी ने 15वें वित्त आयोग से त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की तीनों इकाइयों को सीधे राशि मुहैया कराने की मांग की।

पंचायत प्रतिनिधियों ने इसके अलावा मानव संसाधन के लिए राशि देने, परिसम्पत्तियों जैसे- मार्के कांप्लेक्स, बस पड़ाव, विवाह मंड आदि के निर्माण के लिए प्रति एकमुश्त अनुदान राशि दे बीआरजीएफ की तर्ज पर उग्र प्रभावित तथा आकांक्षी जिलों के राशि देने, प्राकृतिक आपदाओं निबटने के लिए राशि देने आदि की आयोग के समक्ष रखी हैं। बैठक कोडरमा जिला परिषद की अध शालिनी मुर्मू, साहिबगंज जिला परि की अध्यक्ष रेणुका मुर्मू, संजय सि समेत अन्य ने हिस्सा लिया।

गुहार

- पंचायत प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष 10 मांगें रखी
- त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था को सीधे राशि मुहैया कराने की मांग

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – Hindustan Times
2. समाचार पत्र की भाषा – English
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

Finance commission team holds meeting with representatives of Jharkhand's elected bodies

FIELD WORK The team is in state on a 3-day visit to fathom people's aspirations living in the cities and villages

HT Correspondent
htjharkhand@hindustantimes.com

RANCHI: The 15th finance commission on Wednesday fathomed the aspirations of the local bodies of Jharkhand – both urban and rural besides while meeting the representatives.

The representatives of the elected bodies during the meeting with the chairman and members of the commission demanded more financial aids by the Centre for improving basic amenities concerning civic issues while detailing their future plans.

Several representatives also submitted memorandums demanding strict execution of provisions under the fifth schedule and Panchayati Raj Extension to the Scheduled Areas (PESA) Act.

The commission led by Chairman NK Singh is in Jharkhand on a three-day visit to fathom people's aspirations living in the cities and villages besides understanding the wishes of trade and industries and the state government.

Meeting the representatives of urban local bodies (ULBs) and rural local bodies (RLBs) on Wednesday, the commission gave patient hearing to them.

While some demanded special packages for their respective local bodies, others raised specific issues and pleaded for central grants.

"We demanded special packages for gram panchayats, panchayat samitis and zila parishads for basic amenities and overall growth.

The gram panchayat takes up development works in a particular village or panchayat, the panchayat samiti is responsible for developing areas linking two villages or panchayats and the zila parishad takes care of areas linking two blocks.

Unless funds are separately earmarked for each of these bodies, the real goals of positive growth cannot be achieved," said Koderma zila parishad chairperson Shalini Gupta.

Dhanbad mayor Shekhar Agrawal stressed on clean drinking water for all and adequate supply. He mentioned that that geographical area and population of cities or villages should not be the criteria to fix quantum of financial aids. The Dhanbad mayor demanded Rs 600 crore special package.

He also pointed out that quality life can arrest large scale migration that is frequent in urban areas. Our youths prefer fleeing to metropolitan cities searching jobs than struggling in Jharkhnd cities, he said.

Citing examples, he said that three types of water – milky white, muddy red and black water were now commonly available in Jharkhand. Milky white in mica mining zones, muddy red in iron ore mining zones and black in coal mining areas. Installing adequate numbers of water treatment plants ought to be given priority over sewerage and drainage projects or waste disposal plants.

Ranchi mayor Asha Lakra too pointed out water woes in the state capital and depleting ground water levels. Widening of arterial roads and sanitation projects should be given special attention by the fifteenth finance commission, she said.

"We expect new challenges and thus requested that whatever we could not gain during the tenure of the 14th finance commission should be taken care of by the 15th finance commission," she added.

Potka panchayat mukhiya Sushil Dipankari Saradar through a memorandum demanded strict execution of PESA and provisions meant for areas governed under the fifth scheduled.

The mukhiya also demanded for release of funds in tune with the provisions meant for panchayati raj institutions.

The commission will meet chief minister Raghubar Das and his ministerial colleagues besides representatives of political parties on Thursday before leaving for Jamshedpur where it will listen to the representatives of trade and industries and interact with XLRI students on Friday.

15th finance commission Chairman N K Singh along with the team members presiding over a meeting of the local bodies of the state in Ranchi on Wednesday. DIWAKAR PRASAD/ HT PHOTO

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

दिनांक 02-08-2018

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम - प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

वित्त आयोग की टीम रांची में, अध्यक्ष एनके सिंह बोले

पंचायत के तीनों स्तरों को पैसा देने पर आम सहमति बनेगी

- पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक

प्रमुख संवाददाता ▷ रांची

14 वें वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति के दो स्तरों को पैसा देने की अनुशंसा नहीं की थी. बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में तीनों स्तरों को पैसा देने की मांग उठी. बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आये. इन सभी सुझावों पर आम सहमति बनायी जायेगी. 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने शहरी स्थानीय निकायों व ग्रामीण स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद यह बात कही.

पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण स्थानीय निकाय के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये. ऐसे ही सुझाव अन्य राज्यों से भी आये हैं. ये सुझाव आयोग को आम सहमति बनाने में काफी सकारात्मक हैं. इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव पंचायत के तीनों स्तरों को धन देने का था. 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषद व पंचायत समिति को अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं मिल रही थी. बैठक में शहरी स्थानीय निकाय के अनुरूप ही ग्रामीण निकायों को भी अनुदान देने की मांग की गयी. श्री सिंह ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही. ग्रामीण निकायों के जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल किया जायेगा.

• बाकी पेज 15 पर

रांची एयरपोर्ट पर वित्त आयोग के सदस्यों का स्वागत करते पदाधिकारी.

राज्य वित्त आयोग का डिफंक्ट होना, अपराध

अंदर की बात

रांची. 15 वें वित्त आयोग के साथ ग्रामीण स्थानीय निकाय के जन प्रतिनिधियों की हुई बैठक के दौरान यह बात सामने आयी कि यहां राज्य वित्त आयोग डिफंक्ट है. उसका गठन तो हुआ है, लेकिन काम ठीक से नहीं कर रहा. आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने जन प्रतिनिधियों से पूछा कि आपको जो अधिकार व राशि मिली हैं, उसके संबंध में वित्त आयोग के साथ बैठक होती है या नहीं, इस पर प्रतिनिधियों ने उन्हें बताया कि यहां राज्य वित्त आयोग निष्क्रिय है. उन्हें पूरी बात बतायी गयी. इस पर अध्यक्ष ने कहा कि यह संविधान के मुताबिक अपराध है. उन्होंने प्रतिनिधियों से कहा कि वे खुल कर अपनी बातें रखें. अपनी परेशानी कहने में जरा भी नहीं हिचकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि टीम यहां पर आपलोगों से बात करने आयी हैं, अफसरों से नहीं. आपकी बातें सुनना चाहती है. इसके बाद प्रतिनिधियों ने खुल कर अपनी बातें रखीं.

पंचायत के तीनों स्तरों...

उनका सुझाव काफी अच्छा है. इस पर पुनर्विचार किया जायेगा. इन्होंने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन भी दिया है. इस पर विचार किया जायेगा. उन्होंने कहा कि आयोग इस पर राज्य सरकार से कल बात करेगी. नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि जल का अभाव, जल निकासी व जल की गुणवत्ता के बारे में जन प्रतिनिधियों ने बातें रखी है. खास कर गंदे पानी की निकासी के बारे में समस्या का हल हो, इसकी बहुत आवश्यकता है. इसकी राशि की जो आवश्यकता है, इस पर भी जन प्रतिनिधियो ने अपनी बातें रखी है.

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम - The Pioneer
2. समाचार पत्र की भाषा - अँग्रेजी
3. प्रकाशित दिनांक - 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

ULB members press for special packages

From Page 1

2017-18," said the Secretary.

The Chairman during the presentation enquired about tenure of the existing office bearers who have been elected for the next five years in 2018 itself. NK Singh expressing satisfaction over fairly long spell left with them; listened to their problem areas and demands for more funds.

"I stressed over allocating fund based on development deficit for the ULBs and not based on their population or area. It means the funds should come as per the need of that specific city.

This apart, I dragged their attention towards situation of drinking water, sewerage system which most of the ULBs in the State are still fighting for.

If they want to come at par with other developed cities of the country there is strong need for special package otherwise they need another 60-70 years to improve," Dhanbad Mayor Chandra Shekhar Agarwal said.

The coal capital of the country after fairing badly on sanitation in 2016 and tagged as the most dirtiest city on Swachh Bharat survey, has improved its tally and ranked 109th on cleanliness one year later.

Similar were the sentiments of Ranchi Mayor Asha Lakra who stressed more over situation of drinking water and also raised demand for special treatment given to the capital city.

"Ranchi is not any other city of the State. Being the capital city of Jharkhand, Ranchi needs special attention for its overall development. Its needs can be fulfilled only through additional package.

We have a lot to do on the front of basic amenities like drinking water, sanitation and drains," said Asha Lakra.

Later the Commission sat with rural representatives representing gram panchayats, zila parisads etc. Rural elected body members expressed concern over limited fund allocation being done to them which is hampering works at village level.

"We need more autonomy and funds should directly be credited to us from the Finance Commission.

If we are given financial powers true picture of development can be seen right at the grass root level," said a gram sabha representative of Kanke.

Although every possible care and caution has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this publication damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to the exclusive jurisdiction of competent co responding to any contents published in this newspaper. The printer, publisher, editor and any employee of the Pioneer Group's will not be held responsible for any kind of claim made by the

Printed and published by Anupam Sheshank for and on behalf of CMYK Printech Ltd., and published at CMYK Printech Ltd., 304, Radha Kunj, Behind Reliance Mar Ranchi (Jharkhand) Editor: Chandan Mitra, Resident Editor: Anupam Sheshank, RNI Regn. JHAENG/2008/22930, REGD. No. RN-142/2008. AIR SURCHARGE of Re. 1 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002, Phone: 011-40110455, Communication Office: ...

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाप :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम - खबर मंत्र
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

15वें वित्त आयोग की टीम के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक

विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए स्पेशल पैकेज की मांग

खबर मन्त्र वरीय संवाददाता

रांची। राज्य के विशेष क्षेत्रों के विकास के लिए वित्त आयोग से स्पेशल पैकेज की मांग की गयी है। झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर आयी 15 वें वित्त आयोग की टीम के सामने स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने यह मांग रखी। पंचायत प्रतिनिधियों में से ज्यादातर का कहना था कि अनुच्छेद 244 की धारा 1 के तहत पेसा खास कर आदिवासी बहुल राज्यों के लिए केंद्र की ओर से स्पेशल पैकेज दिया जाना चाहिए। वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह के नेतृत्व में दौरे के पहले दिन बुधवार को होटल रेडिशन ब्लू में आयोग के दल ने पंचायत-ग्रामीण विकास और शहरी व नगर विकास विभाग के अधिकारियों व निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर राज्य में चल रही योजना की प्रगत्ति की जानकारी ली। इस दौरान भविष्य की प्लानिंग को लेकर राज्य की ओर से आयोग के सामने प्रेजेंटेशन दिया गया। शहरी स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाओं सहित अन्य मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। अर्बन एरिया व रूरल एरिया से ग्यारह जनप्रतिनिधियों के दो अलग-अलग समूहों ने आयोग के साथ चर्चा की। बैठक के समापन पर नगर विकास सचिव ने कहा कि आयोग के साथ बेहद सौहार्द्रपूर्ण माहौल में वार्ता हुई। टीम ने पेयजल, स्वच्छता के क्षेत्र में गति बनाये रखने के लिए खर्च बढ़ाने की आवश्यकता को समझा है। जनप्रतिनिधियों की ओर से साझा मेमोरेंडम सौंपा गया है। बैठक में आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के नेतृत्व में सदस्य शक्तिकांत दास, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, रमेश चंद तथा सचिव अरविंद मेहता सहित अन्य अधिकारियों के अलावा शहरी निकाय व पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल थे।

बैठक में उपस्थित वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह व अन्य।

आज होगी आला अधिकारियों के साथ बैठक

झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर आयी 15 वें वित्त आयोग की टीम के साथ गुरुवार को राज्य के आला अधिकारियों की बैठक होगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास राज्य की स्थिति पर वित्त आयोग की टीम को अवगत करायेंगे। सामाजिक क्षेत्रों के विकास के साथ-साथ राज्य की आधारभूत संरचनाओं जिनमें सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर मांगपत्र रखेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे राज्य के संवाददाताओं के साथ आयोग की टीम का साक्षात्कार होगा। शुक्रवार को टीम जमशेदपुर रवाना हो जायेगी, जहां वह एक्सएलआरआइ सहित औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ परिचर्चा में शामिल होंगे।

जनसंख्या नहीं डेफिसिट (घाटे के आधार पर तैयार अर्थव्यवस्था) के आधार पर पैसा उपलब्ध कराये केंद्र

राज्य में चल रही योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – आज
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

शहरी व ग्रामीण विकास के लिए वित्त आयोग हरसंभव मदद करेगा : एनके सिंह

पंचायत व स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों से कई अच्छे सुझाव आये

रांची। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा कि झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्त आयोग हर संभव मद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो मांगे रखी गई है उनपर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु राशि कि आवश्यकता होती है आयोग की ओर से प्रयास रहेगा कि राशि के अभाव में राज्य का विकास बाधित न हो। वे आज रांची में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत केप्रतिनिधियों के साथ 15वें वित्त आयोग की बैठक कर रहे थे। बैठक में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से आयोग को अवगत कराया।

इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह 18सदस्यीय दल के साथ आज रांची पहुंचे। तीन दिवसीय दौरे के क्रम में आयोग की टीम ने पहले दिन आज स्थानीय निकायों और पंचायत प्रति. निधियों से बातचीत की।

आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने पत्रकारों से बातचीत 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कई अच्छे सुझाव आये। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के सुझाव आये है और आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग देशस्तर पर आम सहमति बनाने

सभी छाया : राजकुमार

के प्रयास में जुटा है।

स्थानीय निकाय और पंचायत प्रति. निधियों द्वारा विशेष पैकेज की मांग के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इन्हें विशेष पैकेज देना या जल निकासी, पेयजल सुविधा व अन्य आधारभूत सुविधाओं पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्यसरकार के अधिकारियों से कल बात होगी। इससे पहले वित्त आयोग के समक्ष नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सड़क, नाली, पीने के पानी की समस्या,शहरी कचड़ा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत किया गया था जिसपर प्रतिनिधियों ने आवश्यकता के आधार पर राशि निर्गत कराने की बात कही। प्रति. निधियों ने कहा कि चूंकि झारखण्ड में अभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत शैश्व अवस्था में है अतः यहां विकसित राज्यों की तरह परफॉर्मेंश आधारित राशि का निर्धारण नहीं होना चाहिये। प्रतिनिधियों ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं की अभी भी कमी है। इसपर आयोग के सदस्य अशोक लाहिरी ने कहा कि सकुशल कार्य निशपादन के आधार पर राशि का आवंटन एक आधारभूत व्यवस्था है जिसका अनुपालन सभी प्रतिनिधियों पर देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागु करना चाहिये। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बैठक में संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन दिया जिसमें मुख्य रूप से आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के तीनों स्तर (जिला परिषद, ग्राम समिति एवं ग्राम पंचायत) में आवश्यकतानुसार राशि निर्गतकरने एवं उनके व्यय हेतु उचित दिशा निर्देश लागु किये जाये। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मियों की कमी है जिससे योजनाओं को लागु करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्रामीण के स्वास्थ्य हेतु सहायता राशि, ग्राम प्रतिनिधियों को कार्य के निषपादन करने हेतु वाहन की भी मद मांगी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने उचित नियमावली के अभाव में अपने क्षेत्रों में कर आरोपण व्यवस्था लागू करने एवं इसके द्वारा राजस्व उपार्जन क्षमता में असमर्थता व्यक्त की। इस अवसर पर राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के सभी जन प्रतिनिधि एवं 15वें वित्त आयोग के सदस्य शिक्तकांता दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे। इधर, आयोग से मुलाकात के बाद रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि उन्होंने आयोग के समक्ष शहरी निकाय क्षेत्रों में सिवरेज और ड्रेनेज की समस्या के निदान के लिए सहयोग का आग्रह किया। आयोग राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर कल मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर भी चर्चा करेगा। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कल आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इसदौरानराज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति समत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। टीम के सदस्य तीन अगस्त को जमशेदपुर में ट्रेड और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक्सएलआरआई के छात्रों से बातचीत के बाद टीम रांची लौट आएगी और उसी दिन शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – आजाद सिपाही
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रांची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

15वें वित्त आयोग की टीम के समक्ष निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों ने रखा पक्ष

शहरी विकास के लिए 20 हजार करोड़ की डिमांड

झारखंड को उसके हक से वंचित नहीं किया जायेगा : एनके सिंह

- शौचालय, पेयजल और कचरा निष्पादन के लिए मांगा विशेष पैकेज
- जिला परिषद और पंचायत समिति को भी मिले विकास का फंड
- अभी सिर्फ ग्राम पंचायत को मिलती है विकास की राशि

होटल रेडिशन ब्लू में बैठक करते 15वें वित्त आयोग की टीम के सदस्य।

संवाददाता

रांची। 15वें वित्त आयोग की टीम बुधवार को रांची पहुंची। होटल रेडिशन ब्लू में निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठक की। निकाय प्रतिनिधियों ने शहरी विकास के लिए 20 हजार करोड़ की डिमांड रखी। वहीं शौचालय, पेयजल और कचरा निष्पादन के लिए विशेष पैकेज मांगा। विभिन्न निकायों के प्रतिनिधियों ने झारखंड में पेयजल की समस्याओं को उठाते हुए कहा कि इसके लिए अलग से 600 करोड़ रुपये दिये जायें। कारण यहां की भौगोलिक स्थिति दूसरे राज्यों से अलग है। पेयजल की समस्या से आमजन को हर रोज दो-चार होना पड़ रहा है। इधर, पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मांग उठी कि विकास की राशि तीनों स्तर पर जारी की जाये। अभी सिर्फ ग्राम पंचायत को ही विकास की राशि मिल रही है। 14वें वित्त आयोग ने यह व्यवस्था की थी। नतीजतन जिला परिषद और पंचायत समिति को विकास का फंड नहीं मिल रहा था। इस व्यवस्था को खत्म कर तीनों स्तर पर विकास की राशि निर्गत करने की व्यवस्था की जाये। इस प्रस्ताव की वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने सराहना की। साथ ही त्रिस्तरीय व्यवस्था को फिर से चालू करने का संकेत भी दिया। बैठक के बाद वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो सुझाव दिये गये हैं, वह बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस पर वित्त आयोग विचार करेगा।

निकाय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में एक बात उंभर कर सामने आयी कि यहां पेयजल की समस्या गंभीर है। इसे लेकर विशेष पैकेज की भी मांग की गयी है। इधर, एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि सकारात्मक विचार के साथ रांची आये हैं। झारखंड को उसके वाजिब हक से वंचित नहीं किया जायेगा। तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे एनके सिंह ने कहा कि वह शुक्रवार तक राज्य के लोगों से मुलाकात करेंगे और राज्य हित में जो कुछ होगा, वह किया जायेगा।

आज और कल का कार्यक्रम

गुरुवार को मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट सहयोगी के अलावे अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होनी है। वहीं, शुक्रवार को टीम की मुलाकात जमशेदपुर में उद्योग जगत के लोगों के अलावा एक्सएलआरआइ के छात्रों के साथ होनी है।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

दिनांक 02-08-2018

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – देशप्राण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

रिपोर्ट

झारखंड को उसके हक से वंचित नहीं किया जाएगा : एनके सिंह

सकारात्मक सोच से आया है झारखंड

विशेष संवाददाता

रांची, 1 अगस्त : 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और पूर्व सांसद एनके सिंह ने कहा है कि सकारात्मक सोच के साथ वह झारखंड आए है और इस राज्य को उसके हक से वंचित नहीं किया जाएगा। श्री सिंह अपने तीन दिवसीय झारखंड दौरे पर अपनी टीम के साथ रांची पहुंचे वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री सिंह ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह झारखंड सरकार से बात करने के बाद ही कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ सकारात्मक है। आयोग की टीम सकारात्म दृष्टिकोण से ही काम कर रही है। राज्य के विकास आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि राज्य को केंद्र से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता

होटल रेडिसन ब्लू में वित आयोग की बैठक।

मिले, इसके लिए वित्त आयोग की टीम ने राज्य के शहरी निकाय और ग्रामीण निकाय के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी समस्या आज सुनी है। आयोग से मुलाकात के बाद रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि आयोग के समक्ष शहरी निकाय क्षेत्रों में सिवरेज और ड्रेनेज की समस्या के निदान के लिए सहयोग का आग्रह किया है। आयोग की टीम गुरुवार को मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी के अलावे अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। जमशेदपुर में उद्योग जगत के लोगों के अलावे एक्सएलआरआई के छात्रों से आयोग की टीम शुक्रवार को मिलेगी।

विकास आयुक्त ने कहा कि मुख्यमंत्री रघुवर दास कल की बैठक को भी संबोधित करेंगे। झारखंड राज्य में वनभूमि और माइनिंग को लेकर समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं। इसमें हमें राष्ट्रीय स्तर से कहीं ऊपर जाना है। इसी पर गुरुवार को चर्चा होगी। श्री सिंह के साथ आयोग के सदस्य शशिकांत दास, अनूप सिंह, अशोक लाहिरी, रमेश चांद और सचिव अरविंद मेहता के अलावा अन्य पदाधिकारी झारखण्ड दौरे पर आये हैं। यह टीम कुल 18 सदस्यीय है।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – सन्मार्ग
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

पंचायत प्रतिनिधियों ने मांगीं आधारभूत सुविधाएं

सीएम के साथ 15वें वित्त आयोग टीम की बैठक आज

संवाददाता

रांची: 15वें वित्त आयोग के अधिकारियों से ग्राम पंचायत, जिला परिषद् और पंचायत समिति के प्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए राशि देने की मांग की। इसके अलावा आपदा से निबटने और जरूरी मानव संसाधन के लिए भी जरूरी राशि की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आयोग के सदस्यों को रात्रि भोज पर आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ आयोग के अधिकारियों की बैठक गुरुवार को होगी।

लोगों को शुद्ध पेयजल मयस्सर नहीं : धनबाद मेयर : बैठक में पहुंचे धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल ने कहा कि राज्य के लोगों को शुद्ध पेयजल मयस्सर नहीं है। यहां के लोग प्रदूषित पानी पीने को विवश हैं। सीवर के बारे में गुजरात जैसे विकसित राज्यों के लोग ही जानते हैं। उन्होंने कहा कि अर्बन डेवलपमेंट इंडेक्स के मामले में झारखंड काफी नीचे है। इसलिए समुचित विकास के लिए स्पेशल पैकेज कही जरूरत है।

मास्टर प्लान के तहत सड़कें दुरुस्त हों : ठाकुर : चाईबासा के मेयर मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सड़कों का निर्माण मास्टर प्लान बनाकर होनी चाहिए। 15वां वित्त आयोग 14वें वित्त आयोग की ओर से की गई उपेक्षा की भरपाई करे। राज्य में 60 फीसदी से अधिक लोगों को नल से पानी की आपूर्ति नहीं होती है।

स्थानीय प्रतिनिधियों ने आयोग के समक्ष रखी ये मांगें

- 15वां वित्त आयोग जिला परिषद्, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतों को सीधे तौर पर राशि उपलब्ध कराए।
- तीनों शासन व्यवस्था में मानव संसाधन के लिए राशि उपलब्ध कराया जाए।
- आय उत्पादक परिसंपत्ति अर्जित करने के लिए (मार्केट कांपलेक्स, हाट, बस, विवाह मंडप) के लिए एक मुश्त राशि प्रति वर्ष अनुदान के रूप में मिले।
- सभी जिलों के सभी ग्राम सभाओं को बुनियादी सुविधाओं सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए पैसा उपलब्ध कराया जाए।
- बीआरजीएफ के तर्ज पर उग्रवाद प्रभावित और अन्य जरूरतमंद जिलों को राशि मिले।
- प्राकृतिक आपदाओं से निबटने के लिए आयोग राशि उपलब्ध कराए।
- राज्य के कुछ वर्ग असुरक्षित श्रेणी में आते हैं, जिनके जीवन स्तर को ठीक करने के लिए एक निश्चित राशि मिले।
- ग्राम पंचायतों को मिलनेवाली राशि का उपयोग सिर्फ मुख्य सेवाओं के तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए। आधारभूत संरचना के साथ अन्य विकास कार्यक्रमों के लिए राशि मिले।
- नगर निकायों के तर्ज पर त्रिस्तरीय निकायों को भी आवश्यकता के अनुसार राशि मिले।

आयोग को इन सभी बातों पर गौर करनी चाहिए।

15वें वित्त आयोग की टीम संग पंचायत प्रतिनिधियों की बैठक

नगर विकास विभाग ने मांगा 20 हजार करोड़

संवाददाता

रांची: राज्य दौरे पर पहुंची 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज निकायों के प्रतिनिधियों की बैठक बुधवार को होटल रेडीशन ब्लू में हुई। बैठक में नगर विकास विभाग ने अगले पांच वर्षों में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के लिए आयोग से 20 हजार करोड़ रुपए की राशि की मांग की, जिसपर आयोग ने विचार करने का आश्वासन दिया है। वहीं 15वें वित्त आयोग के अधिकारियों से जन प्रतिनिधियों द्वारा शुद्ध पेयजल, जल निकासी और कूड़ा निस्तारण के लिए भी अलग से राशि की मांग की गई। बैठक में कई जिलों के जिला परिषद् और पंचायत समितियों के प्रतिनिधियों ने कहा कि 14वें वित्त आयोग ने

शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को ले मांगी राशि

पेयजल, जल निकासी व कूड़ा निस्तारण के लिए भी अलग से मांगी राशि

ग्राम पंचायतों के अलावा जिला परिषद व पंचायत समितियों को भी मिले पैसा

जिससे उनके अधिकारों में कटौती हो रही है और विकास भी प्रभावित हो रही है। इसे लेकर स्थानीय प्रतिनिधियों ने आयोग को संयुक्त रूप से ज्ञापन भी सौंपा। बैठक के बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि स्थानीय प्रतिनिधियों के साथ दो बैठकें हुई

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम - राँची एक्सप्रेस
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

नगर निकाय व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ पंद्रहवें वित्त आयोग की टीम ने की बैठक

झारखंड के विकास के लिए हरसंभव मदद करेंगे : एनके

▶ **नगर निकाय व ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने जो मांगें रखी है उनपर गंभीरता से विचार करेगा वित्त आयोग : अध्यक्ष**

रांची में बुधवार को नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ करते एनके सिंह व अन्य।

रांची (संवाददाता): पंद्रहवें वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह ने बुधवार को कहा कि झारखंड के शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्त आयोग हर संभव मदद करेगा।

श्री सिंह ने नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ वित्त आयोग की बैठक के दौरान कहा कि झारखंड के शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्त आयोग हर संभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो मांगें रखी गई हैं उनपर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए राशि कि आवश्यकता होती है। आयोग की ओर से प्रयास रहेगा कि राशि के अभाव में राज्य का विकास बाधित न हो। बैठक में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से आयोग को अवगत कराया। नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सड़क, नाली, पीने के पानी की समस्या, शहरी कचरा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत की गई थी जिसपर प्रतिनिधियों ने आवश्यकता के आधार पर राशि निर्गत कराने की बात कही। प्रतिनिधियों ने कहा कि झारखंड में अभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत शैश्व अवस्था में है। इसलिए, यहां विकसित राज्यों की तरह प्रदर्शन आधारित राशि का निर्धारण नहीं होना चाहिये। उन्होंने कहा कि आधारभूत संरचनाओं की अभी भी कमी है। इसपर आयोग के सदस्य श्री अशोक लाहिरी ने कहा कि सकुशल कार्य निष्पादन के आधार पर राशि का आवंटन एक आधारभूत व्यवस्था है जिसका अनुपालन सभी प्रतिनिधियों पर देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू करना चाहिये।

ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बैठक में संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें कहा गया कि मुख्य रूप से आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के तीनों स्तर (जिला परिषद, ग्राम समिति एवं ग्राम पंचायत) में आवशचकता के अनुसार राशि निर्गत करने एवं उनके व्यय के लिए उचित दिशा निर्देश लागू किये जायें। प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मियों की कमी है जिससे योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्रामीण के स्वास्थ्य के लिए सहायता राशि, ग्राम प्रतिनिधियों को कार्य के निष्पादन करने के लिए वाहन की भी मदद मांगी। उन्होंने उचित नियमावली के अभाव में अपने क्षेत्रों में कर आरोपण व्यवस्था लागू करने एवं इसके द्वारा राजस्व उपार्जन करने में असमर्थता व्यक्त की। इस अवसर पर राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के सभी जन प्रतिनिधि एवं 15वें वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. रमेश चंद और सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे।

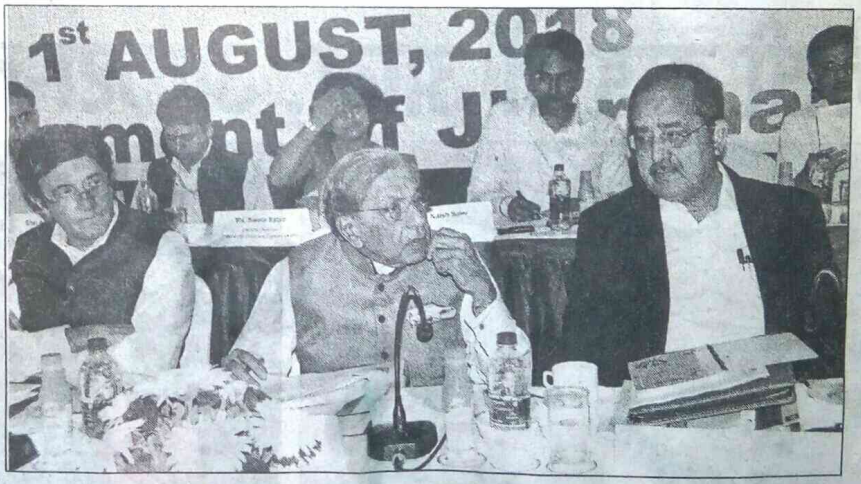

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

दिनांक 02-08-2018

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – राष्ट्रीय नवीन मेल
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

झारखंड को उसके हक से वंचित नहीं किया जायेगा : एनके सिंह

शहरी और ग्रामीण विकास के लिए हरसंभव मदद मिलेगी, प्रतिनिधियों के अच्छे सुझाव आये

रांची (मे.सं)। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त आयोग हर संभव मद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो मांगे रखी गयी हैं, उन पर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु राशि कि आवश्यकता होती है आयोग की ओर से प्रयास रहेगा कि राशि के अभाव में राज्य का विकास बाधित न हो। वह बुधवार को रांची में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ 15वें वित्त आयोग की बैठक कर रहे थे। बैठक में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से आयोग को अवगत कराया। इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह 18सदस्यीय दल के साथ बुधवार को रांची पहुंचे। तीन दिवसीय दौरे के क्रम में आयोग की टीम ने पहले दिन आज स्थानीय निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने पत्रकारों से बातचीत 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कई अच्छे सुझाव आये। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के सुझाव आये है और आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग देशस्तर पर आम सहमति बनाने के प्रयास में जुटा है। स्थानीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विशेष पैकेज की मांग के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इन्हें विशेष पैकेज देना या जल निकासी, पेयजल सुविधा व अन्य आधारभूत सुविधाओं पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारियों से कल बात होगी। उन्होंने कहा कि झारखंड का उसके वाजिब हक से ▸▸शेष पृष्ठ 11 पर

झारखंड को उसके हक से...

वंचित नहीं किया जायेगा। इससे पहले वित्त आयोग के समक्ष नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सड़क, नाली, पीने के पानी की समस्या,शहरी कचड़ा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत किया गया था, जिस पर प्रतिनिधियों ने आवश्यकता के आधार पर राशि निर्गत कराने की बात कही। प्रतिनिधियों ने कहा कि चूंकि झारखंड में अभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत शैश्व अवस्था में है, अतः यहां विकसित राज्यों की तरह परफॉर्मेंश आधारित राशि का निर्धारण नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधियों ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं की अभी भी कमी है। इसपर आयोग के सदस्य अशोक लाहिरी ने कहा कि सकुशल कार्य निशपादन के आधार पर राशि का आवंटन एक आधारभूत व्यवस्था है, जिसका अनुपालन सभी प्रतिनिधियों पर देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू करना चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बैठक में संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन दिया, जिसमें मुख्य रूप से आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के तीनों स्तर (जिला परिषद, ग्राम समिति एवं ग्राम पंचायत) में आवश्यकतानुसार राशि निर्गत करने एवं उनके व्यय हेतु उचित दिशा-निर्देश लागू किये जायें। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मियों की कमी है, जिससे योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्रामीण के स्वास्थ्य हेतु सहायता राशि, ग्राम प्रतिनिधियों को कार्य के निष्पादन करने हेतु वाहन की भी मदद मांगी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने उचित नियमावली के अभाव में अपने क्षेत्रों में कर आरोपण व्यवस्था लागू करने एवं इसके द्वारा राजस्व उपार्जन क्षमता में असमर्थता व्यक्त की। इस अवसर पर राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के सभी जन प्रतिनिधि एवं 15वें वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास, डॉ. अनूप सिंह, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे। इधर, आयोग से मुलाकात के बाद रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि उन्होंने आयोग के समक्ष शहरी निकाय क्षेत्रों में सिवरेज और ड्रेनेज की समस्या के निदान के लिए सहयोग का आग्रह किया। आयोग राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर भी चर्चा करेगा। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कल आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इस दौरान राज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति समत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। टीम के सदस्य तीन अगस्त को जमशेदपुर में ट्रेड और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – राष्ट्रीय सागर
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

विकास के लिए वित्त आयोग हरसंभव मदद करेगा

संवाददाता

रांची। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह ने कहा कि झारखण्ड के शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्त आयोग हर संभव मद्द करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो मांगे रखी गई है उनपर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास हेतु राशि कि आवश्यकता होती है आयोग की ओर से प्रयास रहेगा कि राशि के अभाव में राज्य का विकास बाधित न हो। वे आज़ रांची में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ 15वें वित्त आयोग की बैठक कर रहे थे। बैठक में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से आयोग को अवगत कराया।

इससे पहले 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह 18सदस्यीय दल के साथ आज रांची पहुंचे। तीन दिवसीय दौरे के क्रम में आयोग की टीम ने पहले दिन आज स्थानीय निकायों और पंचायत प्रतिनिधियों से बातचीत की। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने पत्रकारों से बातचीत 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि पंचायत और स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में कई अच्छे सुझाव आये। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों में भी इस तरह के सुझाव आये है और आयोग राष्ट्रीय स्तर पर सहमति बनाने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग देशस्तर पर आम सहमति बनाने के प्रयास में जुटा है। स्थानीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विशेष पैकेज की मांग के संबंध में पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इन्हें विशेष पैकेज देना या जल निकासी, पेयजल सुविधा व अन्य आधारभूत सुविधाओं पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के अधिकारियों से कल बात होगी। इससे पहले वित्त आयोग के समक्ष नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सड़क, नाली, पीने के पानी की समस्या, शहरी कचड़ा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत किया गया था जिसपर प्रतिनिधियों ने आवश्यकता के आधार पर राशि निर्गत कराने की बात कही। प्रतिनिधियों ने कहा कि चूंकि झारखण्ड में अभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत शैश्व अवस्था में है अतः यहां विकसित राज्यों की तरह परफॉर्मेंश आधारित राशि का निर्धारण नहीं होना चाहिये। प्रतिनिधियों ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं की अभी भी कमी है। इसपर आयोग के सदस्य अशोक लाहिरी ने कहा कि सकुशल कार्य निशपादन के आधार पर राशि का आवंटन एक आधारभूत व्यवस्था है जिसका अनुपालन सभी प्रतिनिधियों पर देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागु करना चाहिये। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बैठक में संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन दिया जिसमें मुख्य रूप से आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के तीनों स्तर (जिला परिषद, ग्राम समिति एवं ग्राम पंचायत) में आवश्यकतानुसार राशि निर्गत करने एवं उनके व्यय हेतु उचित दिशा निर्देश लागु किये जाये। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्मियों की कमी है जिससे योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्रामीण के स्वास्थ्य हेतु सहायता राशि, ग्राम प्रतिनिधियों को कार्य के निषपादन करने हेतु वाहन की भी मद मांगी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने उचित नियमावली के अभाव में अपने क्षेत्रों में कर आरोपण व्यवस्था लागू करने एवं इसके द्वारा राजस्व उपार्जन क्षमता में असमर्थता व्यक्त की। इस अवसर पर राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के सभी जन प्रतिनिधि एवं 15वें वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास, डॉ. अनुप सिंह, डॉ. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे।

इधर, आयोग से मुलाकात के बाद रांची नगर निगम की मेयर आशा लकड़ा ने बताया कि उन्होंने आयोग के समक्ष शहरी निकाय क्षेत्रों में सिवरेज और ड्रेनेज की समस्या के निदान के लिए सहयोग का आग्रह किया।

आयोग राज्य के विकास के मुद्दे को लेकर कल मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं पर भी चर्चा करेगा। वहीं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी कल आयोग के समक्ष अपनी बात रखेंगे। इस दौरानराज्य की आर्थिक सामाजिक स्थिति समत अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। टीम के सदस्य तीन अगस्त को जमशेदपुर में ट्रेड और इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद एक्सएलआरआई के छात्रों से बातचीत के बाद टीम रांची लौट आएगी और उसी दिन शाम को दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – The Pioneer
2. समाचार पत्र की भाषा – अंग्रेजी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

FINANCE COMMISSION VISIT

ULB members press for special packages

Panchayat representatives seek greater support

SANTOSH NARAYAN ■ RANCHI

In their first interaction with the team of 15th Finance Commission presently on a tour of Jharkhand, the Urban Local Bodies (ULBs) presented their performance in terms of financial management to seek more support in return.

The team headed by retired bureaucrat and parliamentarian Nand Kishore Singh had a close door meeting with Mayors and chairpersons of Nagar Parishads on the first day of its three-day trip on Wednesday and exchanged ideas.

Urban Development Secretary Ajoy Kumar Singh briefed the Commission members and officials present in good number highlighting the good works done by the ULBs acting on the suggestions of the previous 14th Finance Commission.

"The Government has divulged 19 subjects to the municipal corporations and Nagar Parishads, on which they are free to take their own decisions and act accordingly. Some works are still to be done on this front. Most importantly, performing excellently on the front of revenue generation from their own resources which was one of the suggestions made by the 14th Finance Commission the ULBs of the State have registered commendable 126 per cent jump from Rs 92 crore in 2015-16 to Rs 208 crore during

Continued on Page 2

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

दिनांक 02-08-2018

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – उलगुलान मेल
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रांची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

झारखंड को उसका हक मिलेगा: एनके सिंह

रांची: 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा है कि वो साकारात्मक विचार के साथ रांची आए हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड को उसके बाजिब हक से वंचित नहीं किया जाएगा. तीन दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे एनके सिंह ने कहा कि वो तीन दिनों तक राज्य के लोगों से मुलाकात करेंगे और राज्य हित में जो कुछ होगा वो किया जाएगा. एनके सिंह ने कहा कि वह राज्य सरकार से बात करने के पूर्व कुछ नहीं कहना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि सबकुछ सकारात्मक हैं. सकारात्म दृष्टिकोण से ही आयोग काम कर रहा है. वहीं विकास आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि किसी भी राज्य में पांच वर्षों के बाद वित्त आयोग की टीम आती है. हम सभी बहुत हर्षित हैं कि

वित्त आयोग की टीम आई है. हमलोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है. डीके तिवारी ने कहा कि राज्य को केंद्र से अधिक से अधिक आर्थिक सहायता मिले इसके लिए गुरुवार और शुक्रवार को बैठक की जाएगी. साथ ही क्षेत्रों का भ्रमण भी किया जाएगा. मुख्यमंत्री संबोधित भी करेंगे. उन्होंने आगे कहा कि झारखंड राज्य में वनभूमि और माइनिंग को लेकर समस्याएं उत्पन्न होते रहती हैं. स्वास्थ्य और शिक्षा में हम थोड़े पिछड़े हुए हैं.

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – नया इंडिया
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के साथ नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों की हुई बैठक, अध्यक्ष ने कहा

झारखंड के विकास के लिए वित्त आयोग हरसंभव मदद करेगा

रांची ■ नया इंडिया

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि झारखंड के शहरी एवं ग्रामीण विकास के लिए वित्त आयोग हरसंभव मदद करेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों द्वारा जो मांगे रखी गई है उनपर आयोग गंभीरता से विचार करेगा। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए राशि कि आवश्यकता होती है। आयोग की ओर से प्रयास रहेगा कि राशि के अभाव में राज्य का विकास बाधित न हो। वे बुधवार को होटल रेडिशन ब्लू में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ 15वें वित्त आयोग की बैठक कर रहे थे। बैठक में नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्रों की समस्याओं से आयोग को अवगत कराया। नगर निकाय के प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से सड़क, नाली, पीने के पानी की समस्या, शहरी कचड़ा प्रबंधन, पर्यटन के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि 14वें वित्त आयोग द्वारा जनसंख्या और क्षेत्रफल के आधार पर राशि निर्गत किया गया था,

जिसपर प्रतिनिधियों ने आवश्यकता के आधार पर राशि निर्गत कराने की बात कही। प्रतिनिधियों ने कहा कि चूंकि झारखंड में अभी नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत शैश्व अवस्था में है, अतः यहां विकसित राज्यों की तरह परफॉर्मेंश आधारित राशि का निर्धारण नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधियों ने कहा कि आधारभूत संरचनाओं की अभी भी कमी है। इसपर आयोग के सदस्य अशोक लाहिरी ने कहा कि सकुशल कार्य निष्पादन के आधार पर राशि का आवंटन एक आधारभूत व्यवस्था है, जिसका अनुपालन सभी प्रतिनिधियों पर देश के सभी हिस्सों में समान रूप से लागू करना चाहिए। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने बैठक में संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन दिया। जिसमें मुख्यरूप से आयोग द्वारा ग्राम पंचायत के तीनों स्तर 'जिला परिषद, ग्राम समिति एवं ग्राम पंचायत' में आवश्यकतानुसार राशि निर्गत करने एवं उनके व्यय के लिए उचित दिशा निर्देश लागू किए जाए। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर कर्मियों की कमी है, जिससे योजनाओं को लागू करने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने आपदा प्रबंधन, ग्रामीण के स्वास्थ्य के लिए सहायता राशि, ग्राम प्रतिनिधियों को कार्य के निषपादन करने के लिए वाहन की भी मदद मांगी। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों ने उचित नियमावली के अभाव में अपने क्षेत्रों में कर आरोपण व्यवस्था लागू करने एवं इसके द्वारा राजस्व उपार्जन क्षमता में असमर्थता व्यक्त की। इस अवसर पर राज्य के नगर निकाय एवं ग्राम पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि एवं 15वें वित्त आयोग के सदस्य शक्तिकांता दास, डा. अनुप सिंह, डा. रमेश चंद, सचिव अरविंद मेहता उपस्थित थे।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर.के.मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉंची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. **समाचार पत्र का नाम –** एकबर एक्सप्रेस उर्दू दैनिक
2. **समाचार पत्र की भाषा –** उर्दू
3. **प्रकाशित दिनांक –** 02-08-2018
4. **प्रकाशन शहर –** रांची
5. **प्रकाशन की अवधि –** दैनिक

3 دن تک چلے گا ملاقاتوں کا دور

رانچی، یکم اگست (نمائندہ) بدھ کو 15 ویں فنانس کمیشن کے صدر این کے سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ رانچی پہنچے۔ ان کے ساتھ کمیشن کے رکن ششی کانت داس، انوپ سنگھ، اشوک لاہری، رمیش چاند اور سیکرٹری اروند مہتا کے علاوہ افسران بھی جھارکھنڈ دورے پر آئے ہیں۔ کمیشن کی ٹیم کے تین روزہ دورہ کے دوران ان کی ملاقات وزیر اعلی رگھوور داس سمیت ان کی کابینہ کے ساتھیوں سے بھی ہوگی۔ ساتھ ہی ٹیم ریاست کے اعلی افسران کے ساتھ علیحدہ ملاقات کرے گی۔ اس کے علاوہ تین اگست تک کے اس دورہ کے دوران کمیشن کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کریں گے۔

رانچی، یکم اگست (فیروز عالم) 15 ویں فنانس کمیشن کے صدر مسٹر این کے سنگھ نے کہا کہ جھارکھنڈ کے شہری اور دیہی ترقی کے لئے مالیاتی کمیشن ہر ممکن مدد کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے بلدیاتی اور گرام پنچایت کے نمائندوں کی طرف سے جو مانگے رکھی گئی ہے ان

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – सियासी उफुक
2. समाचार पत्र की भाषा – ~~हिंदी~~ उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

مالی کمیشن کے سامنے مقامی اور پنچایتی بلدیہ کے نمائندوں نے رکھی اپنی بات

رانچی، 1 اگست (نمائندہ) 15 ویں مالی کمیشن کے صدر این کے سنگھ 18 رکنی ٹیم کے ساتھ آج رانچی پہنچے۔ تین روزہ دورے کے لئے کمیشن کی ٹیم نے پہلے دن آج مقامی اداروں اور پنچایت نمائندوں سے بات چیت کی۔ کمیشن سے ملاقات کے بعد رانچی میونسپل کے میئر آشا لکڑا نے بتایا کہ انہوں نے کمیشن کے سامنے شہری بلدیہ علاقوں میں سوریج اور نکاسی کا مسئلہ کی تشخیص کے لئے تعاون کی اپیل کی۔ کمیشن ریاست کی ترقی کے معاملے کو لے کر کل وزیر اعلی، وزراء اور حکام کے ساتھ ترقیاتی اسکیموں پر بھی گفتگو کرے گا۔ وہیں سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بھی کل کمیشن کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ اس دوران ریاست کی اقتصادی سماجی سمت دیگر معاملات پر بات چیت ہوگی۔ ٹیم کے رکن تین اگست کو جمشید پور میں ٹریڈ اور انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد ایکس ایل آر آئی کے طالب علموں سے بات چیت کے بعد ٹیم رانچی لوٹ آئے گی اور اسی دن شام کو دہلی کے لئے روانہ ہو جائے گی۔

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – कौमी तंजीम
2. समाचार पत्र की भाषा – उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

مالیاتی کمیشن کے سامنے مقامی و پنچایتی اکائی کے نمائندوں نے رکھی اپنی بات

رانچی، یکم راگست (تنویر مرزا) 15 ویں مالیاتی کمیشن کے صدر این کے سنگھ 18 رکنی کمیشن کے ساتھ آج رانچی پہنچے۔ تین روزہ دورے کے دوران میں کمیشن کی ٹیم نے پہلے دن آج مقامی اکائیوں اور پنچایت نمائندوں سے بات چیت کی۔ کمیشن سے ملاقات کے بعد رانچی میونسپل کارپوریشن کی میئر آشا لکڑا نے کہا کہ انہوں نے کمیشن کے سامنے شہری اکائی حلقوں میں سیوریج اور ڈرینیج کے مسئلہ کے حل کیلئے مدد کی اپیل کی۔ کمیشن ریاست کی ترقی کے مدّعے پر کل وزیراعلیٰ، وزراء اور افسروں کے ساتھ ترقیاتی منصوبوں پر بھی چرچہ کرے گی۔ وہیں سیاسی پارٹیوں کے نمائندے بھی کل کمیشن کے سامنے اپنی بات رکھیں گے۔ اس دوران ریاست کی اقتصادی، سماجی حالت سمیت دیگر مدّعوں پر ٹیم کے ممبر آئندہ 3راگست کو جمشید پور میں ٹریڈ اور انڈسٹریز ایسوسی ایشن کے لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد ایکس ایل آر آئی کے طلبہ سے بات چیت کے بعد ٹیم رانچی لوٹ آئے گی اور اسی روز دہلی کیلئے روانہ ہوگی۔

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 02-08-2018

1. समाचार पत्र का नाम – जम्हूरियत टाईम्स उर्दू
2. समाचार पत्र की भाषा – उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक – 02-08-2018
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

جھارکھنڈ پہنچے فنانس کمیشن کے صدر این کے سنگھ

رانچی بدھ کو 15 ویں فنانس کمیشن کے صدر این کے سنگھ اپنی ٹیم کے ساتھ رانچی پہنچے. ان کے ساتھ کمیشن کے رکن ششی کانت داس، انوپ سنگھ، اشوک لاہری، رمیش چاند اور سیکرٹری اروند مہتا کے علاوہ افسران بھی جھارکھنڈ دورے پر آئے ہیں. کمیشن کی ٹیم کے تین روزہ دورہ کے دوران ان کی ملاقات وزیر اعلی رگھوور داس سمیت ان کی کابینہ کے ساتھیوں سے بھی ہوگی. ساتھ ہی ٹیم ریاست کے پسندیدہ افسران کے ساتھ علیحدہ ملاقات کرے گی. اس کے علاوہ تین اگست تک کے اس دورہ کے دوران کمیشن کے لوگ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی بات کریں گے. اس بابت ریاست کی ترقی کمشنر ڈی کے تیواری نے کہا کہ جھارکھنڈ کو اس دورے سے ضرور فائدہ ملے گا. انہوں نے کہا کہ کمیشن کے صدر سنگھ ایک بہت ہی مثبت عہدیدار رہے اور ایک علامات ارجنٹ فگر ہے. ساتھ ساتھ وہ ایک اچھے اکانومسٹ بھی ہیں. ایک سوال کے جواب میں ترقی کمشنر نے کہا کہ ریاست کے ڈیمانڈ کا حساب اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ مرکزی ٹیکس شیئر کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ اس کا فارمولہ ریاست کے مفاد میں ہونا چاہئے اس کی پوری کوشش کی جائے گی. طے شدہ پروگرام کے مطابق بدھ کو فنانس کمیشن کی ٹیم کی ملاقات ریاست کے شہری باڈی اور دیہی باڈی کے نمائندوں کے ساتھ ہوگی. اگلے دن یعنی کی جمعرات کو وزیر اعلی اور ان کی کابینہ ساتھی کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات ہونی ہے. وہیں، جمعہ کو اور آخری دن ٹیم کی ملاقات جمشید پور میں انڈسٹری کے لوگوں کے علاوہ ایکس ایل آر آئی کے طالب علموں کے ساتھ ہونی ہے.

ممتا کی سونیا سے ملاقات، این آر سی اور انتخابی تال میل پر بات چیت

نئی دہلی، یکم اگست (یو این آئی) ترنمول کانگریس کی صدر اور مغربی بنگال کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے آج کانگریس کے صدر راہل گاندھی اور ترقی پسند اتحاد (یو پی اے) کی کنوینر سونیا گاندھی سے ملاقات کے دوران آسام میں قومی شہریت رجسٹر (این آر سی) اور مستقبل میں انتخابی تال میل پر بات چیت کی۔ بدھ کو محترمہ گاندھی کی رہائش گاہ دس جن پتھ پر ہوئی اس ملاقات کے بعد محترمہ بنرجی نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ میٹنگ میں این آر سی، موجودہ سیاسی حالات اور انتخابی تال میل کے امکانات پر بات چیت کی گئی۔

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर.के मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉंची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण। **दिनांक** 02-08-2018

1. **समाचार पत्र का नाम –** Sokale Sokale
2. **समाचार पत्र की भाषा –** उर्दू
3. **प्रकाशित दिनांक –** 02-08-2018
4. **प्रकाशन शहर –** रॉंची
5. **प्रकाशन की अवधि –** दैनिक

এন.কে সিং এর সাথে নগর বিভাগ এবং গ্রাম পঞ্চায়েত প্রতিনিধিদের বৈঠক

সংবাদদাতা।

রাঁচি। ১৫ তম অর্থ কমিশনের সভাপতি এন.কে. সিং বলেন যে ঝাড়খন্ডের শহরী ও গ্রামীন বিকাসের জন্য অর্থ কমিসন যে কোনো রকমের সাহায্য করবে। তিনি বলেন যে রাজ্যের নগর বিভাগ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি দ্বারা যে দাবী রাখা হয় তাঁর উপর কমিশন গম্ভীর ভাবে বিচার করবে। তিনি বলেন যে কোনো এলাকার উন্নতির জন্য রাশির প্রয়োজন হয়, কমিশনের দিক থেকে প্রচেষ্টা থাকবে যে রাশির অভাবে রাজ্যের উন্নতি যেন বাধিত না হয়। তিনি বুধবারে হোটেল রেডিসেন ব্লু তে নগর বিভাগ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন। বৈঠকে নগর বিভাগ এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা নিজের এলাকার সমস্যা থেকে কমিশনকে অবগত করায়। নগর বিভাগের প্রতিনিধিরা মুখ্য রুপে সড়ক, নালি, পানীয় জলের সমস্যা, শহরে আবর্জনা প্রবন্ধন, পর্যটনের উন্নতিতে সম্বোন্ধিত বিষয়ে চর্চা করেন। বৈঠকে বলা হয় যে ১৪ তম অর্থ কমিশন দ্বারা জনসংখ্যা ও ক্ষেত্রফলের ভিত্তিতে রাশি নির্গত করা হয়েছিল, যাতে

প্রতিনিধিরা অবশ্যকতার ভিত্তিতে রাশি নির্গত করার কথা বলেন। প্রতিনিধিরা বলেন যে ঝাড়খন্ডে এখন নগর বিভাগ ও গ্রাম পঞ্চায়েত শৈশব অবস্থাতে রয়েছে। এখানে বিকশিত রাজ্যের ভিত্তিতে পারফামেন্স আধারিত রাশির অবন্টন এক আধারভুত ব্যবস্থা যার অনুপালন সমস্ত প্রতিনিধির উপর দেশের প্রত্যেক ভাগে সমান ভাবে লাগু করা যেন হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা বৈঠকে সংযুক্ত ভাবে এক প্রতিবেদন দেয় যাতে মুখ্য ভাবে কমীশন দ্বারা গ্রাম পঞ্চায়েতের তিন স্তর (জেলা পরিষদ, গ্রাম সমিতি এবং গ্রাম পঞ্চায়েত) প্রয়োজন অনুসারে রাশি নির্গত করতে এবং তাঁদের ব্যক্ত হেতু উচিত দিশা নির্দেশ লাগু করা। তিনি বলেন যে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে কর্মীর সহায়তা রাশি, গ্রাম প্রতিনিধিদের কাজের নিস্পাদন করার জন্য বাহনেরও সাহায্য চায়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা উচিত নিয়মাবলীর অভাবে নিজের এলাকাতে আদায় আরোপণ ব্যবস্থা লাগু করে এবং এর দ্বারা রাজস্ব উপার্জণ ক্ষমতাতে অসমর্থতা ব্যক্ত করেন।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक 03.08.2018

1. समाचार पत्र का नाम – झारखण्ड जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आई: सीएम

वरीय संवाददाता

रांची: 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। श्री दास ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

►► शेष पेज 2 पर

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष - 0651-2551102
फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - फ्रीडम फाईटर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आई : रघुवर दास

संवाददाता

रांची : 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं। वे 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को लाभूकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हम लोगों तक पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हमने डिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आयी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी आयेगी। हमारे 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्षों के बाद भी हमारे यहां विधान सभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। हमारी सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया, ये 2019 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। इसी तरह हम न्यू कैपिटल के निर्माण भी करा रहे हैं। इन सभी चीजों के लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा कर हम झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे। कार्यक्रम में राज्य सरकार की ओर से प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

बैठक में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, श्रम मंत्री राज पलिवार, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास, रमेश चंद्र, अनूप सिंह, अशोक लहरी समेत राज्य सरकार के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - नया इंडिया
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

15वें वित्त आयोग की बैठक खत्म, वित्त आयोग के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा

रांची ■ नया इंडिया

राजधानी रांची में 15वें वित्त आयोग की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। वहीं राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री रघुवर दास, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, शिक्षा मंत्री नीरा यादव और खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय के अलावा मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी समेत तमाम विभागों के सचिव मौजूद रहे। वित्त आयोग के सामने सरकार ने अपना पक्ष रखा। राज्य सरकार का कहना है कि झारखंड के खनिज का लाभ पूरे देश को मिलता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम सिर्फ राज्य को झेलना पड़ता है। लिहाजा इसको लेकर मुआवजा का प्रावधान होना चाहिए। सरकार की कोशिश है कि उसे सहायता अनुदान मिले। बैठक के दौरान सरकार की ओर से आदिवासी क्षेत्रों में कुपोषण, अशिक्षा और आधारभूत संरचना के विकास को लेकर अतिरिक्त राशि की जरूरत से अवगत कराया जा रहा है। बैठक में राज्य सरकार की ओर से आर्थिक मामलों के कई विशेषज्ञ भी मौजूद रहे।

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आई: मुख्यमंत्री

15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक

समृद्ध राज्य है, लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आई है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है।

पिछड़े राज्य विकसित होंगेए तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आए। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जाएगा। रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गई है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लेगशीप योजनाओं को लाभूकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हमलोगों तक पाइप लाइन के माध्मय से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हमने ड्रिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आयी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी आएगी। हमारे 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्षों के बाद भी हमारे यहां विधानसभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। हमारी सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया, ये 2019 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। इसी तरह हम न्यू कैपिटल के निर्माण भी करा रहे हैं।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची–834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – सन्मार्ग
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03·08·18
4. प्रकाशन शहर – रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

भौगोलिक, सामाजिक व आर्थिक सूचकांक ध्यान में रखा जाये : हेमंत

वरीय संवाददाता

रांची : वित्त आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक में नेता प्रतिपक्ष सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने अपनी बात रखी और ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने केंद्रीय राजस्व बंटवारे के लिए कोई भी फॉर्मूला तय करने से पहले झारखंड के भौगोलिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक सूचकांक को ध्यान में रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि यहां की जल जंगल और जमीन को ध्यान में रखकर ही कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। यहां वन कानूनों के प्रावधानों को भी राज्य की स्थिति को ध्यान में रखकर ही लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यहां आदिवासियों और जनजातियों की बड़ी आबादी वनों पर निर्भर है। लोकलुभावन योजनाओं की जगह जनकल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया जाये। यहां खनन कंपनियों के मालिक बिसलरी का और खनन क्षेत्र के आदिवासी मिट्टी युक्त लाल पानी पीने को मजबूर हैं। यहां के कोयले से देश रोशन होता है लेकिन यहां बच्चे लालटेन या डिबरी की रोशनी में पढ़ाई करते हैं। यह झारखंड के साथ अन्याय है। वित्त आयोग की निष्पक्षता को केंद्र सरकार ने बांधने की कोशिश की है। केंद्रीय योजनाओं को लागू करने का दबाव है। इससे संवैधानिक संस्था की मर्यादा व नैतिकता प्रभावित हुई है। योजनाओं के खर्च में कटौती की जा रही है। सिर्फ लोक लुभावनी योजनाओं पर खर्च पर ही केंद्र ज्यादा राशि देगा। यह गलत है। जिन राज्यों का प्रजनन दर कम है केंद्र सिर्फ उन्हीं राज्यों को राजस्व आवंटन में प्रोत्साहन देगा। झारखंड में गरीब ज्यादा हैं। ऐसे में यहां प्रजनन दर कम करने के लिए प्रयास करना होगा और अधिक संसाधन की जरूरत है। यहां अदिवासियों की आबादी घटना चिंता का विषय है।

इसलिए केंद्र का निर्णय यहां के लिए विनाशकारी है। जीएसटी लागू होने से राज्यों को कर लगाने की शक्ति समाप्त हो गयी है। जून 2018 तक राज्य के राजस्व में करीब 2500 करोड़ की कमी आयी है। 2022 तक भरपायी केंद्र करेगी लेकिन उसके बाद क्या होगा। 2025 तक सरकार को लगभग 1300 करोड़ का नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में वित्त आयोग को बेहतर उपाय की अनुशंसा करनी चाहिए।

राज्य के प्रति व्यक्ति आवंटन में हो बढ़ोतरी : माकपा

रांची: 15वें वित्त आयोग के सदस्यों से माकपा के सचिवमंडल के सदस्यों ने भी ज्ञापन सौंपकर राज्य के विकास पर पार्टी की दृष्टिकोण को रखा। पार्टी की ओर से कहा गया कि बिहार से अलग होने के बाद से ही झारखंड प्रति व्यक्ति निम्न आवंटन की परम्परा को ढो रहा है। पूर्व की उपेक्षाओं को देखने पर ऐसा लगता है कि झारखंड को प्रति व्यक्ति आवंटन में बढ़ोतरी मिलनी चाहिए। पार्टी ने कहा कि केंद्र प्रयोजित कार्यक्रमों में संदर्भित शर्तों में पूर्वाग्रह दिखता है, जबकि बहुत से केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों का उद्देश्य राज्य के अंतर्गत आता है। पार्टी ने कहा कि केंद्र के भुगतान नहीं करने से राज्य प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर मनरेगा के मामले में 42 प्रतिशत राजस्व का आवंटन राज्यों की ओर से किया जाता है (14वें वित्त आयोग के अनुसार)। इसे राज्यों को शक्ति प्रदान करने के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है।

झारखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा : भाकपा

रांची: 15वें वित्त आयोग के सदस्यों से भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने मिलकर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। राज्य सचिव ने कहा कि राज्य विशेष दर्जे की सभी अर्हताओं को पूरा करता है। इसलिए आयोग इसपर विचार करे। उन्होंने कहा कि यहां खनिज संपदा से भरपूर है। इसके बाबजूद सबसे ज्यादा भूखमरी, पलायन और बेरोजगारी तथा शिक्षा का अभाव यहां है। यहां के जिला मुख्यालय सहित प्रखंडों में सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों की संख्या नगण्य है। इसलिए आयोग राज्य सरकार को प्रखंड से लेकर जिला मुख्यालयों में सरकारी अस्पताल खोलने के लिए राशि उपलब्ध कराए।

पिछड़ी आबादी के विकास पर ध्यान दे आयोग : आजसू

रांची: 15वें वित्त आयोग के सदस्यों से आजसू ने ज्ञापन देकर राज्य के एसटी, एससी और ओबीसी की 80 फीसदी आबादी के समुचित विकास पर ध्यान देने का आग्रह किया है। पार्टी ने कहा कि राज्य की 'जनसंख्या' प्रमुख मानदंडों में से एक है और इसे संघ और राज्यों के बीच के विभाजन में महत्वपूर्ण भार दिया जाता है। हम आयोग को न केवल आबादी के आकार पर विचार करना चाहते हैं। हमारे राज्य झारखंड के मामले में, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा (80 प्रतिशत से अकि) एसटी, एससी और पिछड़ा वर्ग से संबंधित देशज लोगों पर आधारित है। जिन्हें भेदभाव, उपेक्षा और पिछड़ेपन का लंबा इतिहास का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने कहा कि राज्यों में ऐसी आबादी की पिछड़ेपन पर विचार करे और उनके उत्थान के लिए राशि आवंटन में अतिरिक्त मानदंड निर्धारित करे। साथ ही कहा गया कि आयोग इस राज्य के जीएसडीपी का पुनर्मूल्यांकन करे और इस संबंध में राज्य के लोगों को उनके वास्तविक लाभ दे। इससे राज्य के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और स्वच्छता बुनियादी ढांचे के सुधार के लिए संसाधनों के न्यायिक आवंटन में मदद मिलेगी।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – सन्मार्ग
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

झारखंड को दिया जाये विशेष राज्य का दर्जा : कांग्रेस

वरीय संवाददाता

रांची : वित्त आयोग के साथ राजनीतिक दलों की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने अपनी बात रखी और ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाये। यह मांग लंबे समय से चली आ रही है। यह हमारा अधिकार है क्योंकि देश के खनिज संपदा की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत हमारी है। इस देश की विकास में सबसे बड़ा योगदान झारखंड का रहा है। इसलिए झारखंड को उसका हक मिलना ही चाहिए। विशेष राज्य का दर्जा का सबसे बड़ा आधार आदिवासी बहुल इलकों में जनसंख्या का घनत्व होता है। खनिज संपदा के कारण लोगों को विस्थापन एवं पलायन के रूप में झेलना पड़ता है। 40 लाख लोग विस्थापन के शिकार है। इसलिए जल्द से जल्द विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जाए। केंद्र पर्यटन, फिल्म उद्योग, कपड़ा, हैंडलूम जैसे क्षेत्रों में समर्थन करे तो राज्य आसानी से कई अन्य राज्यों को पीछे छोड़ सकता है। झारखंड को अनुभव और पिछली गलतियों से सीख लेनी चाहिए, अगर झारखंड के सभी जिलों में 05 स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जाए तो अगले 05 वर्षों में झारखंड देश का सबसे लोकप्रिय पयर्टन स्थल बन जाएगा। राज्यों को दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान की समीक्षा हो रही है कि इसे चालू रखा जाये या बंद किया जाये। यह सहायता राशि उन योजनाओं के लिए होती है जो आदिवासी समुदाय के कल्याण में बढ़ोत्तरी करती हो या फिर अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन स्तर को उसी राज्य के शेष क्षेत्रों के स्तर तक उठाने के लिए ली गयी कोई योजना हो। इसकी स्वीकृति संसद से होती है। 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर 11 राज्यों को 1 लाख 95 हजार करोड़ रूपये के सहायता अनुदान राशि दी गयी है। झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है और यहाँ अनुसूचित क्षेत्र भी हैं। ऐसे में इसे बंद कर दिये जाने से न सिर्फ झारखंड के आदिवासी हितों की अनदेखी होगी अपितु यह संविधान प्रदत्त प्रावधानों की भावनाओं का घोर उल्लंघन होगा। इसलिए इस पर विचार होना चाहिए। 14वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को मिलने वाली टैक्स हिस्सेदारी में की गयी बढ़ोत्तरी जो 32 से 42 प्रतिशत की गयी थी, इसमें कटौती नहीं की जाये।

जीएसटी केन्द्र ने राज्यों से वादा किया था कि इसके लागू होने से राज्यों को होने वाले किसी भी तरह के राजस्व नुकसान की भरपायी केंद्र अगले पांच वर्ष तक 14 प्रतिशत सालाना ग्रोथ दर के आधार के साथ करेगी। लेकिन केंद्र इससे मुकरने के रास्ते तलाश रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्व हिस्सेदारी तय करने में आयोग 2011 की जनगणना को आधार वर्ष मानेगा। जबकि इसके पहले तक 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना जाता रहा है। सिर्फ 14वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगंणना को आंशिक महत्व दिया था। यह एक नकारात्मक प्रोत्साहन है जो राज्यों को परफार्म करने से हतोत्साहित करेगा। इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है।

राज्य सरकार ने इन मदों में मांगी राशि

मद/विभाग	राशि (करोड़ में)
कृषि	3,447.00
वन एवं पर्यावरण	4,011.00
सिंचाई	30,000.00
पेयजल	5,140.02
स्वास्थ्य	10,345.44
पोषण	475.00
महिला एवं बाल विकास	428.00
स्कूली शिक्षा	1,237.95
उच्च,तकनीकी शिक्षा	4,515.00
कोर कैपिटल सिटी	5000.00
भवन निर्माण	2900.00
सड़क	22,208.00
ग्रामीण सड़क	16,094.00
परिवहन	4,217.00
शहरी विकास	20899.66
ऊर्जा	4,835.00
उद्योग	11,500.00
पर्यटन इंफ्रास्ट्रक्चर	546.00
गृह (सुरक्षा)	545.25
भू-राजस्व प्रशासन	516.00
पंचायती राज	937.66
सूचना तकनीक	34.75
वाणिज्य कर	170.00
कुल	1,50,002.73

राज्यपाल ने वित्त आयोग के सम्मान में दिया रात्रि भोज

रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 15 वें वित्त आयोग की टीम के सम्मान में गुरुवार को राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया। इसमें आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह के अलावा सभी सदस्य, मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, डीजीपी डीके पांडेय सहित कई अधिकारी शामिल हुए।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - सन्मार्ग
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

आलाधिकारियो ने प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से मांगी राशि

वरीय संवाददाता

रांची : 15 वें वित्त आयोग के साथ हुई बैठक में राज्य के आलाधिकारियों ने कहा कि झारखंड में जितने प्राकृतिक संसाधन हैं, केंद्र सरकार उस हिसाब से पैसा दे। यह झारखंड का हक है। राज्य का यह हक पहले भी बिहार ने मारा था। लेकिन राज्य बनने के बाद हम आगे बढ़े हैं। यह एक एसटी बहुल राज्य है। इसलिए यहां उन्हें डबल पैसा मिलना चाहिए। आमदनी और खर्च में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। इससे विकास प्रभावित होता है। अधिकारियों ने कहा कि यहां माइनिंग है, फॉरेस्ट है और ट्राइबल भी हैं। माइनिंग में बड़ी-बड़ी गाड़ियां चलती हैं। पोल्यूशन होता है जिससे पर्यावरण पर असर पड़ता है। भारी गाड़ियों के चलने से सड़कें भी खराब होती हैं। इसे ठीक करने में काफी पैसा खर्च होता है। माइनिंग से जो राजस्व मिलता है, वह इन्हीं सभी चीजों को दुरुस्त करने में खर्च हो जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि माइनिंग में किस राज्य का कितना योगदान है, यह तय होना चाहिए। झारखंड सबसे ज्यादा खनिज दे रहा है तो उसके बदले उसे उसी हिसाब से ज्यादा मुआवजा भी मिलना चाहिए क्योंकि यह देश के लिए काम आ रहा है। अधिकारियों ने कहा कि झारखंड की आबादी को भी मद्देनजर रखते हुए राशि दी जानी चाहिए। यहां की ज्यादा आबादी जंगलों और उसके आसपास रहती है। यहां के आदिवासियों का कहना है कि हम तो देश लिए ऑक्सीजन पैदा करते हैं लेकिन क्या हम लंगोट पहनकर रहें। यहां की भौगोलिक स्थिति भी अलग है। डेवलपमेंट करके रेशियो बढ़ाने के बात कही जा रही है लेकिन इस राज्य की स्थिति अन्य राज्यों से अलग है। इसलिए राज्य को कम से कम 1.50 लाख करोड़ रूपये का ग्रांट दिया जाये।

भाजपा ने राज्य के विकास के लिए मांगा सहयोग

संवाददाता

रांची: राज्य दौरे पर आई 15वें वित्त आयोग की टीम से प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों ने मिलकर राज्य के विकास के सहयोग करने का आग्रह किया है। पार्टी की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा और महामंत्री दीपक प्रकाश ने ज्ञापन देकर कहा कि झारखंड विकास की ओर अग्रसर है। असीम संभावनावाले इस राज्य में खनिज संपदा का दोहन होता रहा है, उस अनुपात में राज्य में मूलभूत सुविधाओं के विकास का कार्य नहीं हो सका है। इसलिए आयोग से अपेक्षित सहयोग की जरूरत है। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्ष 2014 से राजनीतिक स्थिरता आई है, जिससे प्रगति तेज हुई है। प्रगति में आयोग से सहयोग की जरुरत है, ताकि राज्य का और तेजी से विकास हो सके। साथ ही कहा गया है कि यहां 30 फीसदी से अधिक वन भूमि है और देश के पर्यावरण संतुलन में राज्य की महती भूमिका है। आयोग से अनुरोध है कि हमारे राज्य में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को सरल करते हुए विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता पर समुचित ध्यान दिया जाए। राज्य में 27 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना जरूरी है। आयोग को राज्य की इस विशेष स्थिति पर ध्यान देते हुए सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन राज्य को उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए।

राज्य प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है तथा यहां के खनिज का उपभोग पूरा देश करता है। इसलिए केंद्र को पुर्नवास के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करे। खनिजों के उत्खनन से होनेवाली बीमारियों से निबटने में आयोग सहयोग करे। यहां मात्र 20-25 प्रतिशत खेती योग्य भूमि ही सिंचित है। इसलिए उम्मीद है कि वित्त आयोग सिंचाई के क्षेत्र में पर्याप्त सहयोग राज्य सरकार को करेगा। राज्य में एथनॉल की प्रचुर उपलब्धता से व्यावसायिक उपयोग के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए भी हम वित्त आयोग मदद करे। उग्रवाद को लेकर राज्य की पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त तथा तकनीकी रूप से सक्षम एवं साधन सम्पन्न बनाने के लिए भी संसाधन की जरूरत है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची
***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - सन्मार्ग
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

वित्त आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा

विकास हुआ लेकिन अब भी बहुत कुछ बाकी

वरीय संवाददाता

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि झारखंड में पिछले तीन-चार साल में विकास हुआ है, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ होटल रेडिशन ब्लू में हुई बैठक में ये बातें कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। प्रधानमंत्री के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन, हमारे आदिवासी भाइयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल, झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाने

का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। केंद्र की सात फ्लैगशिप योजनाओं को

स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समूचित

कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं।

इससे कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं। बचाव के लिए लोगों तक पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए जिला खनन कोष में आयी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं। झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां

के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। विदेशी करेंसी भी आयेगी। 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्ष के बाद भी हमारे यहां विधान सभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे।

सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया। ये 2019 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। न्यू कैपिटल का निर्माण भी हो रहा है। इन सभी के लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा कर हम झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे। बैठक में राज्य सरकार की ओर से प्रजेंटेशन भी दिया गया। बैठक में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, मंत्री सरयू राय, रामचंद्र चंद्रवंशी, नीरा यादव व राज पलिवार, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास, डॉ रमेश चंद्र, डॉ अनूप सिंह, डॉ अशोक लहरी समेत राज्य सरकार के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - खबर एक्सप्रेस
2. समाचार पत्र की भाषा - उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

مستحکم حکومت آنے کے بعد سے ترقیاتی کاموں میں رفتار آئی

ریاست کی ترقی کے لئے قوت، وسائل اور اتفاق تینوں چیزیں ضروری ہیں: وزیر اعلی

رانچی 2 اگست (فیروز عالم) 14 سال سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جھارکھنڈ تعمیر کا مقصد پورا نہیں ہوسکا۔ 2014 میں ریاست میں مستحکم حکومت آنے کے بعد سے ترقیاتی کاموں نے رفتار پکڑی۔ ریاست کی ترقی کے لئے قوت، وسائل اور اتفاق آج تینوں چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی ضروریات کے میدان میں تیزی سے کام ہورہا ہے۔ قدرتی وسائل ہو یا انسانی قوت جھارکھنڈ ایک خوشحال ریاست ہے۔ لیکن لوگ فقدان کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لیکن پسماندہ ریاست ہونے کی وجہ سے اب بھی یہاں بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ جھارکھنڈ جیسی ریاستوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کافی رقم کی ضرورت ہے۔ مذکورہ باتیں وزیر اعلی مسٹر رگھوور داس نے کہیں۔ وہ 15 ویں مالیاتی کمیشن کی ٹیم کے ساتھ ملاقات میں بول رہے تھے۔ وزیر اعلی نے کہا کہ فنانس کمیشن کو پسماندہ ریاستوں پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔ پسماندہ ریاست تیار ہوں گے، تبھی بھارت بھی مکمل طور پر

(باقی صفحہ ۶ پر)۔

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - फारूकी तंजीम
2. समाचार पत्र की भाषा - उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.2018
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

وزیراعلیٰ نے مالیاتی کمیشن کے سامنے رکھی مانگ

کمیشن نے ہر ممکن مدد کا دلایا بھروسہ

رانچی (اسٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ رگھوورداس نے جمعرات کو رانچی میں 15 ویں مالیاتی کمیشن کے سامنے ریاست کی موجودہ صورت حال اور سماج کے حالات کا حوالہ دیتے ہوئے جھارکھنڈ جیسے نام نہاد ریاستوں کی ترقی کیلئے خصوصی دھیان دینے کی ضرورت بتائی۔ وزیراعلیٰ رگھوورداس کی موجودگی میں وزراء اور سینئر افسران کی ٹیم نے 15 ویں مالیاتی کمیشن کے سامنے پریزینٹیشن کے ذریعہ سے انفرااسٹکچر کے فروغ، تعلیم، صحت، سڑک، پینے کا پانی اور سینچائی کی سہولت کی ترقی کے علاوہ نئی راجدھانی وشہری سہولتوں کی تفصیل کیلئے مرکزی حکومت سے مالی مدد کی مانگ کی۔15 مالیاتی کمیشن کے ساتھ نشست کو خطاب کرتے ہوئے وزیراعلیٰ رگھوورداس نے کہا کہ اگر گاؤں میں بجلی اور سڑک پہنچادیں گے تو ہر گاؤں میں ترقی کے دروازہ کھلے گی۔ یہاں کلچرل وسیاحت پر زور دے رہے ہیں۔ ٹوریزم سے روزگار، معیشت کو بڑی مدد ملے گی۔ اس میں مالیاتی کمیشن ریاستی حکومت کو مدد کریں۔ انہوں نے کہا کہ سرکار ہر گاؤں میں بجلی پہنچا چکی ہے۔ دسمبر 2018 تک گھر گھر بجلی پہنچانے کا مقصد ہے۔ قبائلی ذات کثیر 3312 گاؤں میں وزیراعظم کے ذریعہ شروع کی گئی سات فلیگ شپ منصوبوں کو پہنچانے کا کام کیا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی جنگ ہو یا ریاست کی تشکیل، آدیواسی سماج کا اس میں سب سے بڑا ہاتھ ہے۔ سرکار آدیواسیوں کے آل راؤنڈ ترقی کے لئے کوشاں ہیں۔ سینچائی، روڈ اور بجلی کے حلقوں میں مالیاتی کمیشن کی مدد سے ترقیاتی کام میں تیزی ملے گی۔ وزیراعلیٰ نے کہا کہ جھارکھنڈ 19 ضلع میں شامل ہے۔ ان کی ترقی کے لئے حکومت پابند عہد ہے۔ بڑی تعداد میں مرکزی گرانٹ پر ریاستی حکومت منحصر ہے، لیکن 14 سال کی سیاسی اٹھاپٹک کی وجہ سے ریاست کی ترقی نہیں ہوپائی ہے۔ عوام نے ریاستی حکومت کو ذمہ داری سونپی ہے، حکومت ہر سیکٹر میں تیزی سے ترقی کے کاموں کو انجام دے رہی ہے۔ انہوں نے 15 ویں مالیاتی کمیشن سے اپیل کی ہے کہ جھارکھنڈ کی ترقی پر زیادہ زور دیں، چھوٹے ریاستوں کی ترقی، ملک کی ترقی کو طاقت فراہم کرے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کا بھی یہی مقصد ہے۔ سرکار کی کوشش ہے کہ عوام الناس تک ترقی کی روشنی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار صاف پینے کا پانی کے پائپ لائن کا نیٹ ورک پورے ریاست میں کر رہی ہے۔ مالیاتی کمیشن کے ممبر جھارکھنڈ کی ضرورتوں سے آگاہ ہیں۔ اس ریاست میں پل رہی غریبی کو ختم کرنے میں مالیاتی کمیشن کی اہم کردار ہوگی۔ اس سے پہلے بدھ کو دیر شام کو شہری اور دیہی حلقوں کے عوامی نمائندوں کے ساتھ نشست کرنے کے بعد 15 ویں مالیاتی کمیشن کے صدر این کے سنگھ نے کہا ہے کہ جھارکھنڈ کے دیہی اور شہری ترقی کیلئے کمیشن ہر ممکن مدد کرے گی۔ اس نشست میں بلدیاتی عوامی نمائندوں نے مالیاتی کمیشن کے سامنے سڑک، پینے کے پانی، سیوریج۔ ڈرینج، کچڑا وغیرہ سے متعلق مدد کا تجویز رکھا۔ دیہی پنچایت کے نمائندوں نے مالیاتی کمیشن کے سامنے مشترکہ طور پر اپنی بات رکھی۔

وزیراعلیٰ نے سود شرح کیلئے شکریہ ادا کیا

رانچی (اسٹاف رپورٹر) وزیراعلیٰ رگھوورداس نے مرکزی کابینہ کے ذریعہ سندری فرٹیلائزر یونیٹ کیلئے 415.77 کروڑ روپے سود سے پاک لون دینے کے تجویز کی منظوری ملنے پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے وزیراعظم نریندر مودی کے تئیں شکر ادا کرتے ہوئے کہا کہ سالوں سے بند پڑے سندری کارخانہ کو دوبارہ شروع کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا اور اسے پورا کرنے کی سمت میں یہ اہم قدم ہے۔

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉची–834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – राँष्ट्रीय ख़बर हमारी नज़र
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद वित्त आयोग अध्यक्ष ने कहा

पंचायत को तीनों स्तरों पर पैसा देने पर बनेगी सहमति

संवाददाता

रांची : वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति के दो स्तरों को पैसा देने की अनुशंसा नहीं की थी। बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में तीनों स्तरों को पैसा देने की मांग उठी। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आये। इन सभी सुझावों पर आम सहमति बनायी जायेगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने शहरी स्थानीय निकायों व ग्रामीण स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद यह बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण स्थानीय निकाय के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये।

ऐसे ही सुझाव अन्य राज्यों से भी आये हैं। ये सुझाव आयोग को आम सहमति बनाने में काफी सकारात्मक हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव पंचायत के तीनों स्तरों को धन देने का था।

14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषद व पंचायत समिति को अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं मिल रही थी। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय के अनुरूप ही ग्रामीण निकायों को भी अनुदान देने की मांग की गयी। श्री सिंह ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। ग्रामीण निकायों के जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल किया जायेगा।

उनका सुझाव काफी अच्छा है। इस पर पुनर्विचार किया जायेगा। इन्होंने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन भी दिया है। इस पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयोग इस पर राज्य सरकार से कल बात करेगी। नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि जल का अभाव, जल निकासी व जल की गुणवत्ता के बारे में जन प्रतिनिधियों ने बातें रखी है। खास कर गंदे पानी की निकासी के बारे में समस्या का हल हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसकी राशि की जो आवश्यकता है, इस पर भी जन प्रतिनिधियो ने अपनी बातें रखी है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर.के मिशन आश्रम
मोराबादी,राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - राष्ट्रीय खबर हमारी नज़र
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

बैठक 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोले मुख्यमंत्री रघुवर दास

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आयी

- 14 वर्ष के बाद तो काम में तेजी आयी
- अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे आयोग
- दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली

संवाददाता

रांची : 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहीं। वे 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। श्री दास ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को लाभूकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हम लोगों तक पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हमने ड्रिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आयी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी आयेगी। हमारे 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्षों के बाद भी हमारे यहां विधान सभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। हमारी सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया, ये 2019 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। इसी तरह हम न्यू कैपिटल के निर्माण भी करा रहे हैं।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - तनीम न्यूज
2. समाचार पत्र की भाषा - उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

مستحکم حکومت سازی کے بعد ہی ترقیاتی کاموں کو ملی رفتار

15ویں مالیاتی کمیشن کے ساتھ منعقدہ نشست میں وزیر اعلیٰ کا اظہار خیال

رانچی، (اسٹاف رپورٹر) وزیر اعلیٰ رگھوور داس نے جمعرات کو رانچی میں 15ویں مالیاتی کمیشن کے سامنے ریاست کی موجودہ اقتصادی وسماجی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے جھارکھنڈ جیسے پسماندہ ریاستوں کی ترقی کے لئے خصوصی توجہ کی ضرورت بتائی. وزیر اعلیٰ رگھوور داس کی قیادت میں وزراء اور سینئر حکام کی ٹیم نے 15ویں مالیاتی کمیشن کے سامنے پریزینٹیشنز کے ذریعے بنیادی ڈھانچہ کی ترقی، تعلیم، صحت، سڑک، پینے کے پانی اور آب پاشی کی سہولت کی ترقی کے علاوہ نئی راجدھانی اور شہری سہولیات کی توسیع کے لئے مرکزی حکومت سے مالی امداد کا مطالبہ کیا. 15ویں مالیاتی کمیشن کے ساتھ ملاقات سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ رگھوور داس نے کہا کہ اگر گاؤں میں بجلی اور سڑک پہنچا دیں گے، تو ہر گاؤں میں ترقی کا دروازہ کھل جائے گا. یہاں ثقافتی اور سیاحت پر زور دے رہے ہیں. ٹورازم سے روزگار، معیشت کو بڑی مدد ملے گی. اس میں مالیاتی کمیشن ریاستی حکومت کو مدد کرے. انہوں نے کہا کہ حکومت ہر گاؤں میں بجلی پہنچا چکی ہے، دسمبر 2018 تک گھر گھر بجلی پہنچانے کا مقصد ہے. شیڈولڈ کاسٹ اکثریتی 3312 گاؤں میں وزیر اعظم کے ذریعہ شروع کی گئی سات فلیگ شپ منصوبوں کو پہنچانے کا کام کیا جارہا ہے. انہوں نے کہا کہ آزادی کی جنگ ہو یا ریاست کی تشکیل، آدیباسی سماج کا اس میں سب سے بڑی شراکت ہے، حکومت آدیباسیوں کی ہمہ جہت ترقی کے لئے پابند عہد ہے. آبپاشی، روڈ اور بجلی کے علاقے میں مالیاتی کمیشن کی مدد سے ترقیاتی کام میں تیزی ملے گی. وزیر اعلی نے کہا کہ جھارکھنڈ کے 19 ضلع بہترین اضلاع میں شامل ہیں، ان کی ترقی کے لئے حکومت پرعزم ہے، بڑی مقدار میں مرکزی گرانٹ پر ریاستی حکومت منحصر ہے، لہذا ریاست کی ترقی میں مالیاتی کمیشن کی شراکت اہم ہے. رگھوور داس نے کہا کہ جھارکھنڈ ایک جوان ریاست ہے، لیکن 14 سال کی سیاسی عدم استحکام سے ریاست کی مکمل ترقی نہیں ہو پائی، عوام نے ریاستی حکومت کو ذمہ داری سونپی ہے، حکومت ہر سیکٹر میں تیز رفتار ترقی کے کاموں کو انجام دے رہی ہے. انہوں نے 15ویں مالیاتی کمیشن سے اپیل کی کہ جھارکھنڈ کی ترقی پر زیادہ زور دیں، چھوٹی ریاستوں کی ترقی، ملک کی ترقی کو تقویت دے گا، وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی یہی مقصد ہے. حکومت کی کوشش ہے کہ عوام تک ترقی کی کرن پہنچے. انہوں نے کہا کہ حکومت پینے کے صاف پانی پائپ لائن نیٹ ورک پوری ریاست میں بچھانے پر کام کر رہی ہے. فنانس کمیشن کے رکن جھارکھنڈ کی ضرورتوں سے اچھی طرح واقف ہیں، اس امیر ریاست میں پل رہی غریبی کو ختم کرنے میں مالیاتی کمیشن کا بڑا کردار ہوگا. اس سے پہلے بدھ کی دیر شام کو شہری اور دیہی علاقوں کے عوامی نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد 15ویں فنانس کمیشن کے صدر این کے سنگھ نے کہا ہے کہ جھارکھنڈ کے دیہی اور شہری ترقی کے لئے کمیشن ہر ممکن مدد کرے گا. اس اجلاس میں مقامی عوامی نمائندوں نے فنانس کمیشن کے سامنے سڑک، پینے کے پانی، سیوریج - ڈرینیج، ویسٹ مینجمنٹ سے متعلق مدد کی تجویز پیش کی. گرام پنچایت کے نمائندوں نے فنانس کمیشن کے سامنے مشترکہ طور پر اپنی مانگیں رکھیں۔

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – Sokale Sokale
2. समाचार पत्र की भाषा – Urdu
3. प्रकाशित दिनांक – 03·08·18
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

রাজ্যে সঠিক সরকার গঠনের পরেই উন্নতি ক্রমবর্ধমানঃ রঘুবর

বিশেষ সংবাদদাতা।

রাঁচি। চোদ্দ বছরের রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনেই ঝাড়খণ্ড রাজ্য গঠনের উদ্দেশ্যটি সফল হতে পারেনি। রাজ্যতে সঠিক সরকার গঠনের পরেই উন্নয়নমূলক কার্যতে গতি ধরে। রাজ্যের উন্নতির জন্য সামর্থ, সম্পদ এবং সম্পর্ক এই তিনটি জিনিষকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই কারনেই পরিকাঠামোগত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে কাজ চলছে। প্রাকৃতিক সম্পদ আর মানব শক্তির দিক থেকে ঝাড়খণ্ড একটি সমৃদ্ধ রাজ্য বলেই মনে করা হয়। উন্নয়ন হচ্ছে কিন্তু পিছিয়ে থাকা রাজ্যের কারনে এখনও এখানে কিছু উন্নয়নের প্রয়োজন আছে। ঝা।খণ্ডের মোট রাজ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে। মানুষের প্রয়োজন পুরো করার জন্য যথেষ্ট রাশিরও দরকার। এই কথাগুলি মুখ্যমন্ত্রী রঘুবর দাস বললেন। তিনি ১৫ তম অর্থ আয়োগের দলের সাথে বৈঠকে বলছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে অর্থ আয়োগকে যেসব রাজ্যের উন্নয়ন হচ্ছে না সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়ার প্রয়োজন আছে, আর এভাবেই ভারতের সম্পূর্ন উন্নয়ন হবে। আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের স্বপ্নই এইযে সকল রাজ্যের উন্নয়ন। মুখ্যমন্ত্রীর বললেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অথবা আলাদা রাজ্যের আন্দোলনে এখানের আদিবাসী ভাইসব নিজেদের রক্ত ঘাম অনেক ঝরিয়েছে। তাই আমাদেরও কর্তব্য তাদের জীবনে পরিবর্তন আনা। গ্রামে গ্রামে বিদ্যুতের সুবন্দোবস্ত। ভালো রাস্তাঘাট আর শুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ বিষয়ে দ্রুততার সাথে কাজ চলছে। রঘুবর দাস বললেন রাজ্যের সকল গ্রামেতে বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে। এখন চলছে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সরবরাহের অভিযান। ২০১৮ বর্ষের ডিসেম্বর মাস অবধি রাজ্যের সকল ঘরকে আলোকিত করার লক্ষ্য নিয়েই কাজ চলছে। মুখ্যমন্ত্রী জানালেন কেন্দ্রীয় সরকারের সাত ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পগুলির সুবিধা মানুষ পাচ্ছে। গ্রাম স্বরাজ অভিযানের দ্বিতীয় চরমে রাজ্যের ৬৫১২ গ্রামেতে এই প্রকল্প থেকে ১৫ই আগস্ট অবধি সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যটি রাখা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যের ১০০০ থেকেও অধিক তফসিলি

উপজাতি জনসংখ্যা বিশিষ্ট ৩৩১২ টি গ্রাম সবে এই প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যটি আছে। তাঁর মতে কৃষি ক্ষেত্রে রোজগারের অনেক পথ আছে। কিন্তু এখানে সেচের ঠিকমত ব্যাবস্থা না থাকার কারনে চাষ ঠিকমত হচ্ছে না। খনি অঞ্চলে মানুষজন দুষিত জল খেয়ে বিভিন্ন অসুখের কবলে পড়ছে। আর এইদিক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষের কাছে শুদ্ধ জল পৌঁছাবার জন্য ডিস্ট্রিক্ট মাইনিং ফান্ডে আশা রাশির ব্যাবহার হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বললেন ঝাড়খণ্ড রাজ্যে পর্যটনের ক্ষেত্রেও অনেক সম্ভাবনাগুলি আছে। একটি বিশ্বমানের পর্যটন স্থল। পর্যটনের উন্নয়নের ফলে রোজগারের পথও খুলবে। ফলে বিদেশী মুদ্রাও আসবে। এখানের ২৪ টি জেলার মধ্যে ১৯ টি জেলা আকাঙ্ক্ষিত জেলার সূচিতে আছে। রাজ্য গঠনের ১৪ বর্ষ পরেও এখানে বিধানসভা, হাইকোর্ট ছাড়াও অন্যান্য প্রমুখ সব ভবন নেই। এই সরকার এইগুলিকে তৈরির প্রকল্প রেখেছে আর সেগুলি ২০১৯ বর্ষ অবধি তৈরিও হয়ে যাবে। এইভাবে সরকার নিউ ক্যাপিটালের গঠনও করছে। বৈঠকে অর্থ আয়োগের চেয়ারম্যান এন কে সিংহ, খাদ্য সরবরাহ মন্ত্রী সরযু রায়, স্বাস্থ্য মন্ত্রী রামচন্দ্র চন্দ্রবংশী , শিক্ষা মন্ত্রী নীরা যাদব, শ্রম মন্ত্রী রাজ পরিবার, মুখ্য সচিব সুধীর ত্রিপাঠি, উন্নয়ন কমিশনার ডিকে তেওয়ারি, বিভাগের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুখদেব সিংহ ছাড়াও রাজ্য সরকারের বরিষ্ঠ আধিকারিকেরা উপস্থিত ছিলেন।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - उत्कल मेल
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आई : रघुवर दास

रांचीः 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहीं। वे 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। श्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को लाभूकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – क़ौमी तंज़ीम
2. समाचार पत्र की भाषा – उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

مستحکم حکومت کے قیام سے ترقیاتی کاموں میں آئی تیزی

جھارکھنڈ کو مالیات کمیشن کے تعاون کی ضرورت: وزیر اعلیٰ

رانچی، 02 اگست (ت ن س) وزیر اعلیٰ رگھوور داس نے آج رانچی میں 15 ویں مالیاتی کمیشن کے سامنے ریاست کی موجودہ اقتصادی وسماجی حالات کا حوالہ دیتے ہوئے جھارکھنڈ جیسے غیر ترقی یافتہ ریاستوں کی ترقی کیلئے خصوصی دھیان دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ رگھوور داس کی قیادت میں وزراء وسینئر افسروں کی ٹیم نے 15 ویں مالیاتی کمیشن کے سامنے پیشکش کے ذریعہ بنیادی انفراسٹرکچر کے فروغ، ایجوکیشن، ہیلتھ، سڑک، پینے کا پانی اور سینچائی کی سہولت کے علاوہ نئی راجدھانی وشہری سہولیات کی توسیع کیلئے مرکزی حکومت سے مالی مدد کی مانگ کی۔ 15 ویں مالیاتی کمیشن کے ساتھ میٹنگ کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ

فلیگ شپ منصوبوں کو پہنچانے کا کام کیا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی جنگ ہو یا سرکار کی تشکیل، آدیباسی سماجی کا اس میں سب سے بڑی قربانی ہے۔ سرکار آدیباسیوں کی ہمہ جہت ترقی کیلئے پابند عہد ہے۔ سینچائی، روڈ اور بجلی کے شعبہ میں مالیاتی کمیشن کی مدد سے ترقیاتی کام میں تیزی ملے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ جھارکھنڈ کے 19 اضلاع مطلوبہ اضلاع میں شامل ہے۔ اس کی ترقی کیلئے سرکار پابند عہد ہے۔ بڑی مقدار میں مرکزی گرانٹ پر ریاستی حکومت منحصر ہے۔ اس لئے ریاست کی ترقی میں مالیاتی کمیشن کا تعاون اہم ہے۔ رگھوور داس نے کہا کہ جھارکھنڈ ایک نوجوان ریاست ہے۔ لیکن 14 سال کی ... عدم استحکام ...

صوبوں کی ترقی ملک کی ترقی کو زور دے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کا بھی یہی نشانہ ہے۔ سرکار کی کوشش ہے کہ عوام الناس تک ترقی کی روشنی پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ سرکار صاف پینے کا پانی کے پائپ لائن کا نیٹ ورک پوری ریاست میں بچھانے پر کام کر رہی ہے۔ مالیاتی کمیشن کے ارکان جھارکھنڈ کے ضرورتوں سے پوری طرح واقف ہیں۔ اس خوشحال ریاست میں پل رہی غریبی کو ختم کرنے میں مالیاتی کمیشن کا رول اہم ہوگا۔ اس سے قبل بدھ کی دیر شام کو شہری ودیہی حلقوں کے عوامی نمائندوں کے ساتھ بیٹھک کرنے کے بعد 15 ویں مالیاتی کمیشن کے چیئرمین این کے سنگھ نے کہا ہے کہ جھارکھنڈ کے دیہی وشہری ترقی کیلئے کمیشن ہر ممکن مدد کرے گی ...

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - सियासी उफ़ुक
2. समाचार पत्र की भाषा - उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

15ویں مالیاتی کمیشن سے ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپئے گرانٹ کا مطالبہ

جھارکھنڈ حکومت کی جانب سے کمیشن کو سونپا گیا تفصیلی رپورٹ

رانچی، 2 اگست (نمائندہ) پندرہویں مالیاتی کمیشن سے جھارکھنڈ حکومت نے تقریبا ڈیڑھ لاکھ کروڑ روپے کے گرانٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ جھارکھنڈ کے وزیراعلی رگھوور داس نے آج رانچی میں اس سے متعلق ایک میمورنڈم مالی کمیشن کے صدر این کے سنگھ کو سونپا۔ این سنگھ کمیشن کے ارکان کے ساتھ جھارکھنڈ کے تین روزہ دورے پر ہیں۔ وزیراعلی رگھوور داس نے جو میمورنڈم کمیشن کو تفویض کیا اس میں چودہویں مالیاتی کمیشن کے کئی نکات پر تبدیلی کرنے کا مشورہ دیا ہے تاکہ جھارکھنڈ جیسے پسماندہ ریاستوں کو فائدہ ہو۔ جھارکھنڈ حکومت کی جانب سے 42598 کروڑ روپے کا گرانٹ زراعت، ون اور آب پاشی کے لئے مانگی گئی ہے، جس سے 3447 کروڑ روپے زراعت، 4011 جنگلات و ماحولیات، 30000 آبپاشی اور 5140 کروڑ روپے پینے کے پانی کے لئے فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ وہیں سماجی علاقے کی ترقی کے لئے 17001 کروڑ روپے فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا، اس رقم سے 10345 کروڑ روپے صحت اور 1237 کروڑ روپے خواتین اور اطفال کی ترقی پر خرچ کئے جانے کی تجویز ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے بنیادی ڈھانچہ کی ترقی کے لئے سب سے زیادہ 88199 کروڑ روپے فراہم کرنے کی اپیل کی گئی ہے، ان میں کور کیپٹل ایریا کے پلاننگ اور ڈیزائن کے لئے 5000 کروڑ، تعمیراتی کے لئے 2900 کروڑ، سڑک کے لئے 22208 کروڑ، دیہی ترقی کے لئے 16094 کروڑ، نقل وحمل کے لئے 4217 کروڑ، شہری ترقی کے لئے 20899 کروڑ، توانائی کے لئے 4835 کروڑ، صنعت کے لئے 11500 کروڑ، سیاحت کی ترقی کے لئے 546 کروڑ روپے خرچ کئے جانے کی تجویز ہے۔

مستحکم حکومت آنے کے بعد سے ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی: وزیراعلی

رانچی، 2 اگست۔ وزیراعلی رگھوور داس نے کہا کہ 14 سال سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جھارکھنڈ تعمیر کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ 2014 میں ریاست میں مستحکم حکومت آنے کے

بعد سے ترقیاتی کاموں نے رفتار پکڑی۔ ریاست کی ترقی کے لئے قوت، وسائل اور اتفاق آج تینوں چیزیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بنیادی ضرورتوں کے شعبے میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ قدرتی وسائل ہو یا انسانی قوت جھارکھنڈ ایک خوشحال ریاست ہے۔ لیکن لوگ فقدان کی زندگی جینے پر مجبور تھے۔ ترقیاتی کام ہوئے ہیں، لیکن پسماندہ ریاست ہونے کی وجہ سے اب بھی یہاں بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ جھارکھنڈ جیسی ریاستوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لاکھوں ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کافی رقم کی ضرورت ہے۔ وہ آج 15ویں مالیاتی کمیشن کی ٹیم کے ساتھ نشست میں خطاب کر رہے تھے۔ بقیہ صفحہ 2 پر

کچھ سال اچھے کام ہوئے، پر جھارکھنڈ کی کچھ اہم مسائل: این کے سنگھ

کئی چیلنج، قبائلیوں کی ترقی پر خصوصی توجہ کی ضرورت

رانچی، 2 اگست (نمائندہ) 15ویں مالی کمیشن کے صدر این سنگھ نے کہا ہے کہ جھارکھنڈ میں حالیہ کچھ سالوں میں انسانی وسائل کی ترقی سمیت دیگر علاقوں میں بہتر کام ہوا ہے، لیکن اب بھی جھارکھنڈ جیسی ریاستوں کے سامنے کئی چیلنج ہیں، اس کے حل کے لئے ٹھوس قدم اٹھائے جانے کی ضرورت ہے۔ بقیہ صفحہ 2 پر

ई-मेल / सी-ड्राफ्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष – 0651–2551102
फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन तल
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – राष्ट्रीय सागर
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में आई तेजी :मुख्यमंत्री

संवाददाता

रांची। 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। उक्त बातें मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहीं। वे 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।

केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को लाभूकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है। हमारे यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इससे कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हम लोगों तक पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हमने जिला माइनिंग फंड में आयी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी आयेगी। 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्षों के बाद भी हमारे यहां विधान सभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। हमारी सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया, ये 2019 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। इसी तरह हम न्यू कैपिटल के निर्माण भी करा रहे हैं। इन सभी चीजों के लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा कर हम झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे। राज्य सरकार की ओर से प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

बैठक में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, श्रम मंत्री राज पलिवार, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास, डॉ रमेश चंद्र, डॉ अनूप सिंह, डॉ अशोक लहरी समेत राज्य सरकार के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - राष्ट्रीय नवीन मेल
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए : रघुवर

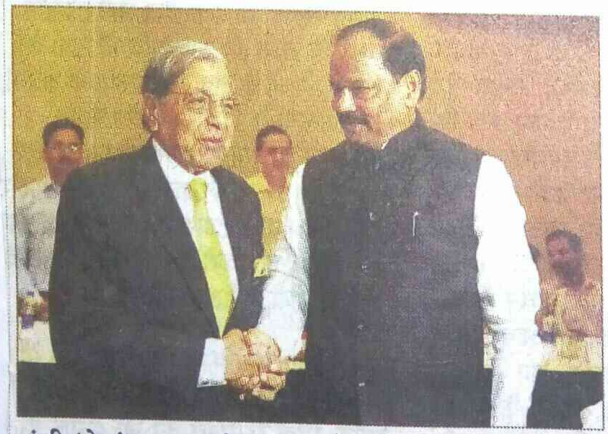

रांची (मे.सं)। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। मुख्यमंत्री गुरुवार को 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोल रहे थे। टीम के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। ▸▸ शेष पृष्ठ 11 पर

झारखंड में विकास की अच्छी संभावनाएं : एनके सिंह

रांची (मे.सं)। झारखंड में विकास की अच्छी संभावनाएं हैं। यहां विकास कार्य गंभीरता से चलाने होंगे। यह कहना है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह का। वह गुरुवार को प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बात कर रहे थे। वित्त आयोग की टीम अपने तीन दिवसीय यात्रा पर राज्य में आयी हुई है। श्री सिंह ने कहा कि गुरुवार को मुख्यमंत्री के साथ वित्त आयोग की टीम की बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्य की मांगों को प्रमुखता से रखा। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में विकास के कार्य किस प्रकार चल रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आयोग से राज्य के लिए पिछली बार की तुलना में अधिक राशि की मांग की है। सीएम ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन में बदलाव की जरूरत है। माइनिंग स्टेट होने के कारण झारखंड को केन्द्र से अधिक सहयोग मिलना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से एक मेमोरेंडम भी आयोग को सौंपा गया है। श्री सिंह ने बताया कि आयोग की टीम देश के सभी राज्यों का दौरा करेगी। वहां की सरकार से बात करके उनका पक्ष जानेगी। झारखंड सातवां राज्य है, जहां आयोग की टीम पहुंची है। श्री सिंह ने बताया कि बुधवार को स्थानीय निकाय के प्रतिनिधियों से वार्ता हुई। सभी पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से आयोग को ▸▸ शेष पृष्ठ 11 पर

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - राँची एक्सप्रेस
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

स्थिर सरकार से विकास में तेजी

झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत : मुख्यमंत्री

रेडिशन ब्लू में वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से बात करते मुख्यमंत्री रघुवर दास। साथ में मुख्य सचिव भी

रांची (संवाददाता) : राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में स्थिर सरकार का गठन होने के बाद से प्रदेश के विकास कार्यों ने गति पकड़ी है। श्री दास ने यहां 15वें वित्त आयोग के साथ बैठक के दौरान कहा कि अलग राज्य का गठन होने के बाद से 14 वर्ष तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने कहा कि झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। श्री दास ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी देश का भी पूर्ण रूप से विकास हो सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन झारखंड के आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा दायित्व है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। इससे लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। सरकार दिसंबर 2018 तक राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रही है। श्री दास ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आवामी न्यूज़
2. समाचार पत्र की भाषा – उर्दू
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

مستحکم حکومت آنے کے بعد ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی

مالی کمیشن کی نشست سے وزیر اعلیٰ کا خطاب

رانچی (اسٹاف رپورٹر) 14 سال تک مستحکم حکومت کے نہ بننے کی وجہ سے جھارکھنڈ میں تعمیری کام کا مقصد پورا نہیں ہو سکا۔ 2014 میں مستحکم حکومت کے بننے کے بعد ترقیاتی کاموں میں تیزی آئی ہے۔ ریاست کی ترقی کیلئے صلاحیت، وسائل اور قابلیت، اتفاق آج تینوں چیزیں ہیں یہی وجہ ہے کہ بنیادی ضرورتوں پر تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور جھارکھنڈ خوشحال ہو رہا ہے۔ ترقی کے کام ہوئے لیکن پچھڑا ریاست ہونے کی وجہ کر یہاں ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ اس میں خصوصی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کافی رقم کی ضرورت ہے۔ مذکورہ باتیں وزیر اعلیٰ رگھوور اس نے کہی۔ 15 ویں مالیاتی کمیشن کی ٹیم کے ساتھ نشست کر رہے تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مالیاتی کمیشن کو ان ڈیولپ ریاستوں پر زیادہ غور و خوض کرنا چاہیے۔ پچھڑی ریاست ڈیولپ ہوں گے تبھی بھارت بھی پوری طرح ڈیولپ ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے سپنے بھارت کا خواب بھی یہی کہ ساری ریاست ڈیولپ ہوں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آزادی کی لڑائی ہو یا الگ ریاست کی مانگ ہو۔ اس تحریک میں ہمارے آدیواسی بھائیوں نے خوب خون پسینا بہایا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ان کی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ گاؤں۔ گاؤں تک اچھی سڑک بنیں، بجلی اور پینے کا پانی پہنچانے کا کام تیزی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریست کے سبھی گاؤں میں بجلی پہونچا دی گئی ہے۔ اب گھر۔ گھر بجلی پہونچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دسمبر 2018 تک ہم ریاست کے ہر گھروں کو روشن کرنے کا ہدف لے کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مرکزی حکومت کی سات فلیگ شپ منصوبوں کو مستفدین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ گرام سوراج مہم کے دوسرے مرحلے میں ریاست کے 6512 گاؤں تک ان منصوبوں کا فائدہ 15 اگست تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے 1000 سے زیادہ شیڈول ٹرائب کی آبادی والے 3212 گاؤں تک ان مصنوعات کو پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت میں سب سے زیادہ روزگار ہے لیکن یہاں کھیتی کی سہولیت نہیں ہونے کی وجہ کر کھیتی کا کام پوری طرح سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ کان کنی علاقوں کے لوگ آلودہ پانی پینے کو مجبور ہیں اس سے کئی طرح کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ اس کے لئے پائپ لائن کے ذریعہ پانی پہونچانے کیلئے ہم نے ڈسٹرکٹ مائننگ فنڈ میں آئی رقم کا استعمال کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہاں ٹورازم کے کافی امکانات ہیں۔ یہاں بین الاقوامی ٹورسٹ پلیس ہیں اس سے کافی روزگار پیدا ہوں گے۔ اس سے کافی رقم آئے گی۔ اس میں 24 میں سے 19 ضلع شامل ہیں۔ ریاست کی تعمیر کے 14 سال بعد بھی ہمارے یہاں ودھان سبھا، ہائی کورٹ سمیت دیگر خاص بلڈنگ نہیں تھے۔ ہماری حکومت نے انھیں بنانے کا کام کیا ہے۔ اسی طرح نیو کیپیٹل کے بنانے کا بھی کام کر رہے ہیں۔ نشست میں مالیاتی کمیشن کے چیئرمین این کے سنگھ، وزیر سریو رائے، وزیر صحت رام چندر چندرونشی و دیگر لوگ موجود تھے۔

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची
***

दूरभाष – 0651-2551102
फैक्स – 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आज़ाद सिपाही
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा: झारखंड विकास की राह पर

रघुवर ने मांगा डेढ़ लाख करोड़ का पैकेज

वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से हाथ मिलाते मुख्यमंत्री रघुवर दास।

20899.66
करोड़ रुपये शहरी विकास के लिए मांगा

10345.44
करोड़ रुपये स्वास्थ्य संरचनाओं के लिए मांगा

संवाददाता

रांची। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह की टीम ने गुरुवार को झारखंड सरकार के मंत्रियों और विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों संग बैठक की। इस मौके पर वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने झारखंड को तेजी से विकास की राह पर बढ़ता राज्य बताया। उन्होंने कहा कि गरीबी उन्मूलन और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना राज्य के लिए चुनौती है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी करनी होगी। उनके मुताबिक, अर्थव्यवस्था को गति देना भी आवश्यक है।

इस दौरान राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से 150002.73 करोड़ रुपये के विशेष अनुदान की मांग की। सरकार ने सबसे अधिक 20899.66 करोड़ रुपये की राशि शहरी विकास के लिए मांगी है। स्वास्थ्य संरचनाओं के लिए 10345.44 करोड़ रुपये की मांग की गयी है। सरकार ने आपदाओं के लिए विशेष मांग की है। इनमें झरिया की जमीन में लगी आग, हाथियों से होनेवाले नुकसान और वज्रपात शामिल हैं। दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने वित्त आयोग से झारखंड को विशेष दर्जा देने की मांग की है। राज्य सरकार ने वित्त आयोग से अनुशंसित अनुदानों को राज्य को ट्रांसफर किये जाने की निगरानी के लिए स्वतंत्र नियामक के गठन का भी सुझाव दिया। अभी तक इस तरह का कोई रेगुलेटर नहीं है। एनके सिंह ने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा देने में आयोग सक्षम भी नहीं है। अध्यक्ष एनके सिंह ने झारखंड के वित्तीय अनुशासन पर चिंता जाहिर की है। इधर, विपक्षी दलों के साथ बैठक के दौरान कहा गया कि झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए।

गरीबी खत्म करने में वित्त आयोग की अहम भूमिका होगी : मुख्यमंत्री

इस मौके पर सीएम रघुवर दास ने कहा कि हमारी सरकार स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन का नेटवर्क पूरे राज्य में बिछाने पर काम कर रही है। वित्त आयोग के सदस्य झारखंड की जरूरतों से भली-भांति परिचित हैं। इस समृद्ध राज्य में पल रही गरीबी को खत्म करने में वित्त आयोग की बड़ी भूमिका होगी। गांव में बिजली और सड़क पहुंचा देंगे, तो हर गांव में विकास का द्वार खुलेगा। यहां सांस्कृतिक पर्यटन पर जोर दे रहे हैं। टूरिज्म से रोजगार, अर्थव्यवस्था को बड़ी मदद मिलेगी। इसमें वित्त आयोग राज्य सरकार की मदद करे।

ई–पेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आज़ाद सिपाही
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

ट्राइबल बहुल क्षेत्रों के लिए किया विशेष अनुदान का आग्रह

बैठक में शामिल विपक्ष के नेता हेमंत सोरेन, डॉ अजय कुमार, प्रदीप यादव, भाजपा के दीपक प्रकाश और अन्य।

वरीय संवाददाता

रांची। 15वें वित्त आयोग ने झारखंड के विकासात्मक कार्यों के जारी रहने का भरोसा दिलाया है। आयोग की टीम ने संवाददाताओं को बताया कि आर्थिक वृद्धि दर और सरकार के प्रयासों को दखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी योजजाओं को लागू करने के मामले में राज्य की प्रगति अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे चुनौतियों के बारे में पता है। इसके पहले आयोग के समक्ष झारखंड सरकार की ओर से 2020-25 के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये की मांग को समग्र तौर पर रखा। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, शहरी और ग्रामीण विकास की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से इस राशि की मांग की गयी है। वित्त आयोग ने कहा कि डेमोग्राफिक मैनेजमेंट में बेहतर करनेवाले राज्यों को बढ़ावा देने के आधार पर आर्थिक नीतियां तय की जानी है। राज्य सरकार के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। ट्राइबल डेवलपमेंट, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, आधारभूत संरचना और लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। एक सवाल पर आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि अगर यही हाल रहा, तो राज्य को फिर से अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। आयोग की टीम में अध्यक्ष एनके सिंह के साथ, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ अनूप सिंह, डॉ अशोक लाहिड़ी, डॉ रमेश चंद्र, डॉ अरविंद मेहता, भारत भूषण गर्ग, डॉ रवि कोटा, मुखमित सिंह भाटिया, गोपाल प्रसाद के अलावा राज्य सरकार के तमाम मंत्री और वरीय अधिकारी शामिल थे।

बड़ा कर्ज और भुगतान पर जतायी चिंता : वित्त आयोग ने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किये गये कार्य, केंद्र के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने पर संतोष जताया है, जबकि अधिक कर्ज और पूंजीगत खर्च पर चिंता जतायी। फिजिकल डेफिसिएट यानी आमदनी और खर्चे के गैप की भी भरपायी करने को कहा है।

आज जमशेदपुर में उद्योग प्रतिनिधियों के साथ बैठक : वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और उनकी टीम शुक्रवार को जमशेदपुर में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। आयोग द्वारा एक्सएलआरआइ जमशेदपुर के शिक्षकों और विद्यार्थियों के साथ भी संवाद का कार्यक्रम है।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर.के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आज़ाद सिपाही
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

विशेष राज्य का दर्जा हमारा अधिकार है : डॉ अजय

15 वित्त आयोग के समक्ष कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कहा कि राज्य कि विशेष राज्य की दर्जा की मांग लंबे समय से चलते आ रही है। और यह हमारा अधिकार भी है। खनिज संपदा में राज्य की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। यह वरदान के साथ साथ अभिशाप भी साबित हो रहा है। पलायन के रूप में यह डांस झेलना पद रहा है इसलिए विशेष दर्जा के साथ विशेष अनुदान की जरूरत है। इसके साथ विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जाये।

वन सरंक्षण कानूनों के प्रावधानों का सरलीकरण हो : दीपक प्रकाश

भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में 2014 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ। इसके बाद राजनीतिक स्थिरता आने से विकास में तेजी आयी। पार्टी ने वन संरक्षण कानूनों के प्रावधानों के सरलीकरण करने का सुझाव दिया। आदिवासी बहुल राज्य होने तथा खनिज उद्योगों के कारण विस्थापन होने के कारण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन राज्य को उपलब्ध कराने तथा लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की।

दक्षिणी-पूर्वी रेलवे का मुख्यालय झारखंड में बने : देवशरण भगत

आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत ने वित्त आयोग से कहा कि रेलवे को सबसे. अधिक रेवेन्यू झारखंड से मिलता है, लेकिन इस अनुपात में न तो यहां रेल की सेवा मिल रही है न ही यात्रियों को सुविधाएं। पार्टी ने दक्षिणी-पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के बदले झारखंड में बनाने की अनुशंसा करने की मांग की। पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के अनुदान की राशि बढ़ाने की भी मांग की।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष - 0651-2551102
फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - आज़ाद सिपाही
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

राजनीतिक दलों ने विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की

संवाददाता

रांची। 15वें वित आयोग की टीम ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। राजनीतिक दलों ने झारखंड के पिछड़े होने का हवाला देते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके लिए सभी मानक पूरा करने की बात कही। यह भी कहा कि यहां के खनिज से देश का विकास हो रहा है, उस अनुपात में केंद्र से राज्य को अनुदान नहीं मिल रहा। इससे न केवल यहां के किसान-गरीब विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि विकास से भी वंचित हैं।

संसाधन आवंटन में आदिवासी आबादी मापदंड बने : हेमंत सोरेन

रांची। झारखंड जैसे प्रदेश में संसाधन आवंटन में आदिवासी आबादी को मापदंड बनाया जाना चाहिए। किसी भी क्षेत्र का विकास वहां के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के आधार पर ही संभव है। यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहीं। हेमंत ने ... काउंसिल का प्रतिनिधित्व भी हो। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल जो कमायेगा, उसे बांटने का फार्मूला वित्त आयोग को तय करना है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि दोनों में समन्वय रहे। जीएसटी से 2,500 करोड़ के राजस्व की हुई कमी हेमंत ने 15 वें वित्त आयोग के सामने जीएसटी के कारन प्रदेश को राजस्व में हो रहे नुकसान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बदले हुए कर प्रणाली से सबसे ज्यादा प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जून 2018 तक लगभग 2,500 करोड़ की कमी राजस्व में हुई है। 2022 तक केंद्र सरकार इसकी भरपाई करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा। जीएसटी लागू होने के बाद राज्यों से कर लगाने की शक्तियां ...

समस्या के समाधान के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता : प्रदीप यादव

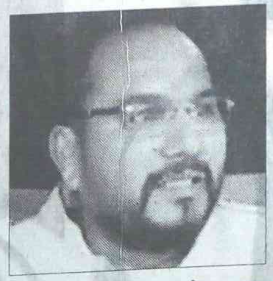

झारखंड विकास मोर्चा के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने 15वें वित्त आयोग के समक्ष अपने सुझाव देते हुए कहा किस राज्य की आवश्यकताएं ऊर्जा के क्षेत्र में शिक्षा के क्षेत्र में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आदिवासियों के विकास एवं विस्थापन की समस्या के समाधान के लिए बड़ी राशि की आवश्यकता है। हम ... खनिज संपदा पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, बल्कि सिर्फ बाल्टी लेकर हम चुप हो जाते हैं। खनिज उत्खनन का दंश झारखंड की जनता जल रही है उसका नाम के कारण विस्थापन की जमीन की बर्बादी भूतल जल का गायब होना पर्यावरण का प्रदूषण और सबसे अधिक हानि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो पीढ़ी-दर-पीढ़ी बढ़ती जा रही है। इसका कोई उपाय नहीं है। उन्होंने सुझाव देते हुए कहा कि बंटवारे के विचारणीय बिंदु जिसमें राज्य का क्षेत्रफल को भी शेयर ऑफ टैक्स इसका फैक्ट्री से जोड़ा जाये, और खनिज रॉयल्टी नहीं, लेकिन लाभ में हिस्सेदारी यानी रॉयल्टी के साथ कंपनियों के मुनाफे में भी राज्य की हिस्सेदारी हो। उन्होंने कहा कि तब जाकर हमारी जिम्मेदारी हिस्सेदारी आयोग की अनुशंसा से बढ़ पायेगी।

विशेष राज्य का दर्जा मिले : भुनेश्वर मेहता

भाकपा के राज्य सचिव सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद मेहता ने वित्त आयोग से मांग की कि विशेष राज्य लिए राज्य सभी अर्हताएं पूरी करता है। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा भुखमरी, पलायन, बेरोजगारी झारखंड में है। शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में झारखंड सबसे पीछे है। झारखंड आदिवासी राज्य है, परंतु आदिवासियों की आबादी लगातार घट रही है। राज्य बनने के समय इनकी आबादी 32%थी, परंतु अभी 27%रह गयी है। अभी तक हजारों गांव पीने के पानी से महरूम हैं। रोजगार नहीं रहने के कारण इनके घरों में दो शाम का चूल्हा नहीं जलता है। इसके कारण रोजगार के लिए पलायन को मजबूर हैं। युवक के साथ साथ युवतियों भी पलायन को मजबूर हैं। जहां उन्हें मानसिक प्रताड़ना के साथ शारीरिक शोषण भी झेलना पड़ता है। किसानों की हालात और भी बदतर है। कोई भी सिचाई योजना अभी तक पूरी नहीं हुई है। कनहर हो अन्य योजनाएं पूरा हो और नयी योजना बने इसके लिए वित्त आयोग पूरा फंड सरकार को उपलब्ध कराये, ताकि सभी सभी योजनाएं पूरा हो और किसानों को सिचाई की व्यवस्था हो।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची
***

दूरभाष – 0651–2551102
फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – खबर मंत्र
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

वित्त आयोग को झारखंड ने समझायी अपनी पीड़ा, कहा

अभिशाप बना खनिज बहुल राज्य का तमगा

खबर मन्त्र, वरीय संवाददाता

रांची। बेतहाशा खनन व इससे उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव के चलते झारखंड बर्बाद हो रहा है। देश के कुल खनन क्षेत्र का लगभग 40 प्रतिशत खनिज अकेले झारखंड में है, इसके बावजूद यहां के लोगों का समुचित विकास नहीं हो सका है। 15 वें वित्त आयोग की टीम के सामने झारखंड की ओर से यह बातें अपने प्रजेंटेशन के दौरान कही गयी। बैठक में शामिल सरकार के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि राज्य के अंदर माईनिंग की वजह से घाटा बढ़ा है, सड़क, कृषि, उपज, सिंचाई और पेयजल योजनाओं पर सरकार की एक बड़ी धनराशि खर्च हो जा रही है।

उन्होंने कहा कि खनिजों की ढुलाई में बड़े वाहनों के आवगमन के चलते रोड समय से पहले खराब हो रहे हैं, प्रदूषण से खेती, उपज व पेयजल की बहुलता घटती जा रही है। हमने आयोग को कहा कि राज्य के वन क्षेत्रों में रहने वाले लोग इन हालातों में कहते हैं कि हम देश के लिए आक्सीजन पैदा करें और बदले में लंगोट पहने रहें। वित्त आयोग से सरकार ने कहा कि वन क्षेत्रों के कठोर कानून के चलते हम जंगलों के आस-पास रहने वाले स्थानीय आबादी को सिंचाई व पेयजल जैसी मुलभूत सुविधाओं तक से वंचित रखना पड़ रहा है।

आयोग को सरकार का सूझाव

वित्त आयोग के सदस्यों को सरकार ने राजस्व के आवंटन को लेकर कई सूझाव दिये। झारखंड सरकार के द्वारा सौंपे गये ज्ञापन में कहा गया कि माईनिंग के चलते होने वाले घाटे को कम करने के लिए जीएसडीएपी के आधार पर राशि तय हो। यानि केंद्र को खनिज संपदा से होनेवाली केद्र की आय में झारखंड के प्रतिशत (अंशदान) के आधार पर फंड की उपलब्धता कराने का सूझाव दिया गया।

वित्त आयोग की टीम के साथ मुख्यमंत्री।

सीएम ने मांगा ज्यादा सहयोग, बतायी पीड़ा

आयोग को किए अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर है, इसके चलते वे कई तरह की बीमारियों व स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से ग्रसित हो रहे हैं। लोगों तक पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए सरकार डिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आयी राशि का इस्तेमाल कर रही है।

झारखंड की आर्थिक प्रगति पर आयोग संतुष्ट

झारखंड ने जीएडीएपी के तहत केंद्र व राज्य की 30-30 प्रतिशत हिस्सेदारी की रखी मांग

खबर मंत्र, वरीय संवाददाता

रांची। वित्त आयोग की टीम ने 2014-15 में राजस्व घाटा के कारणों तथा तीन प्रतिशत के वित्तीय घाटे की सीमा को बखूबी समझा। आयोग ने पाया कि जीएसडीएपी अनुपात में बकाए ऋण में वृद्धि हुई है, साथ ही माना कि सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार और अधिक रोजगार सृजन तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए पूंजी व्यय बढ़ाने की आवश्यकता है। बैठक के दौरान झारखंड सरकार ने फिजिकल डिफिसिएट के आधार पर यानि आमदनी-खर्चे में गैप के आधार पर वित्तीय मदद की मांग रखी।

वकास आयुक्त डीके तिवारी ने कहा कि जीएडीएपी का 60 प्रतिशत तक कर्ज लिया जा सकता है। इस मामले में केंद्र व राज्य की 30-30 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो सकती है। आपको बता दें कि फिलहाल झारखंड को लोन एमाउंट का 26 प्रतिशत तक की हिस्सेदारी दी जा रही है। हालांकि, झारखंड सरकार इस अंशदान को यूपी व अन्य राज्यों की तर्ज पर 30 प्रतिशत तक चाहती है। सरकार का कहना है कि अगर आयोग उनकी बात पर गौर करती है तो इससे झारखंड को एक बड़ी धनराशि की प्राप्ति होगी।

सरकार ने किया बड़ी राशि का डिमांड

झारखंड सरकार ने 15 वें वित्त आयोग से 150,002.73 करोड़ की डिमांड की है। सरकार ने 15 वें वित्त आयोग के पास जो डिमांड रखी है उसमें कृषि, वन और पेयजल के लिए 42598.02 करोड़, सोशल सेक्टर के लिए 17001.39 करोड़, आधारभूत संरचना पर 88199.66 करोड़, वित्त और सामान्य प्रशासन के लिए 2203.66 करोड़ की डीमांड की है। गौरतलब हो कि 14 वें वित्त आयोग ने झारखंड को 4778.5 करोड़ आवंटित किया था, जिसमें 4279.8 ही झारखंड को मिल सका था। यह पूरे बजट का 89.6 फीसदी राशि है।

वित्त आयोग की सिफारिशों का महत्व

आयोग राज्य का दौरा कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा। यह रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाएगी। केंद्र सरकार को आर्थिक मामलों में अहम सुझाव देने वाली इसी टीम की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकारों को वित्तीय मदद मिलती है। केंद्रीय राजस्व का राज्यों के बीच बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर होता है। इसके लिए जरूरी है कि राज्यों की जरूरतों का ठीक-ठीक आकलन हो और उनके बीच राजस्व का बंटवारा बराबरी के आधार पर किया जाए।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – खबर मंत्र
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

वित्त आयोग से सरकार ने 1.50 लाख करोड़ मांगा

ट्राइबल बहुल क्षेत्रों के लिए किया विशेष अनुदान का आग्रह

खबर मन्त्र वरीय संवाददाता

रांची। 15 वें वित्त आयोग ने झारखंड के विकासात्मक कार्यों के जारी रहने का भरोसा दिलाया है। आयोग की टीम ने संवाददाताओं को बताया कि आर्थिक वृद्धि दर व सरकार के प्रयासों को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि यह तेजी से बढ़नेवाली अर्थव्यवस्था है। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा व कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के मामले में राज्य की प्रगति अच्छी है और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे चुनौतियों के बारे में पता है। इसके पहले आयोग के समक्ष झारखंड सरकार की ओर से 2020-25 के लिए 1.50 लाख करोड़ रुपये की मांग को समग्र तौर पर रखा गया। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, परिवहन, शहरी और ग्रामीण विकास की विभिन्न आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से इस राशि की मांग की गयी है। वित्त आयोग ने कहा कि डेमोग्राफिक मैनेजमेंट में बेहतर करनेवाले राज्यों को बढ़ावा देने के आधार पर आर्थिक नीतियां तय की जानी हैं। राज्य सरकार के द्वारा ज्ञापन सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। ट्राइबल डेवलपमेंट, बिजली, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा व आधारभूत संरचना

वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से हाथ मिलाते मुख्यमंत्री रघुवर दास।

व लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। आयोग ने झारखंड के उदय बांड लागू करने के मॉडल पर असंतोष जताया साथ ही कहा कि अगर यही हाल रहा तो राज्य को फिर से अतिरिक्त राशि की जरूरत होगी। आयोग की टीम में अध्यक्ष एनके सिंह के साथ, आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉ अनूप सिंह, डॉ अशोक लाहिड़ी, डॉ रमेश चंद्र, डॉ अरविंद मेहता, भारत भूषण गर्ग, डॉ रवि कोटा, मुखमीत सिंह भाटिया, गोपाल प्रसाद के अलावा राज्य सरकार के मंत्री व अन्य अधिकारी शामिल थे। आयोग की टीम ने गुरुवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की।

बड़े कर्ज व भुगतान पर चिंता : वित्त आयोग ने राज्य सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किये गये कार्य और केंद्र के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से लागू करने पर संतोष जताया है, जबकि अधिक कर्ज व पूंजीगत खर्च पर चिंता जतायी। फिस्कल डेफिसिट यानी आमदनी व खर्चे के गैप की भी भरपायी करने को कहा गया है।

आज जमशेदपुर में उद्योगपतियों के साथ बैठक : आयोग का दल शुक्रवार को जमशेदपुर में व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – AKHBAR-E-MASHRIQ
2. समाचार पत्र की भाषा – Urdu
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

مستحکم حکومت کے سبب ترقیاتی کاموں میں آئی تیزی: وزیر اعلی

گرام سوراج مہم کے تحت 6512 گاؤں تک منصوبوں کا فائدہ پہنچانے کا ہدف

رانچی، 2/اگست: چودہ سال سیاسی عدم استقلال ہونے کی وجہ سے جھارکھنڈ تعمیر کا مقصد پورا نہیں ہوسکا۔ ریاست میں مستقل حکومت آنے کے بعد سے ترقیاتی کاموں نے رفتار پکڑی۔ ریاست کی ترقی کے لئے وسائل بہت ضروری ہے۔ یہ وجہ ہے کہ بنیادی ضرورتوں کے حلقہ میں تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ قدرتی وسائل ہو یاہ انسانی طاقت جھارکھنڈ ایک مستحکم ریاست ہے۔ لیکن لوگ تنزلی کی زندگی جینے کو مجبور ہیں۔ جھارکھنڈ جیسی ریاستوں پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ لوگوں کو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کافی رقم کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں وزیر اعلی رگھور داس نے کہی۔ وہ 15ویں مالی کمیشن کی ٹیم کے ساتھ نشست میں بول رہے تھے۔

وزیر اعلی نے کہا کہ ملی کمیشن کو غیر ترقی یافتہ ریاستوں میں توجہ دینا چاہیے۔ پچھڑی ریاست ترقی یافتہ ہوں گے تبھی ہندستان بھی پوری طرح سے ترقی یافتہ ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم نریندر مودی کے نئے بھارت کا خواب بھی یہی ہے کہ ساری ریاست ترقی یافتہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کی لڑائی ہو یا الگ ریاست کا احتجاج ہمارے آدیواسی بھائیوں نے خوب خون پسینہ بہایا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ انکے زندگی میں تبدیلی آئے۔ گاؤں گاؤں تک اچھی سڑک، بجلی اور صاف پانی پہنچانے کا کام تیزی سے کیا جا رہا ہے۔ گاؤں میں انکے پہنچتے ہی لوگوں کی زندگی میں اچھی تبدیلی آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست کے سبھی گاؤں میں بجلی پہنچا دی گئی ہے۔ اب گھر گھر بجلی پہنچانے کی مہم چلائی جا رہی ہے۔ دسمبر 2018 تک ہم ریاست کے ہر گھر کو روشن کرنے کا ہدف لیکر کام کر رہے ہیں۔

داس نے کہا کہ مرکزی حکومت سال فلیگ شپ منصوبوں کو مستفدین تک پہنچایا جا رہا ہے۔ گرام سوراج مہم کے دوسرے مرحلے میں ریاست کے 6512 گاؤں تک ان منصوبوں کا فائدہ 15 اگست تک پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ریاست کے 1000 سے زیادہ شیڈول ٹرائب کے آبادی والے 3312 گاؤں تک بھی ان منصوبوں کو پہنچانے کا ہدف رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زراعت میں سب زیادہ روزگار ہے لیکن ہمارے یہاں آب پاشی کا مکمل انتظام نہیں ہونے کی وجہ سے کاشت کاری پوری طرح سے نہیں ہو پا رہی ہے۔ کانکنی حلقوں میں لوگ گندہ پانی پینے کو مجبور ہیں۔ اس کے کئی طرح کی بیماریوں سے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ اس کے بچاؤ کے لئے ہم لوگوں تک پائپ لائن کے ذریعہ سے صاف پانی پہنچانے کے لئے ہم نے ڈسٹرکٹ مائنگ فنڈ میں آئی رقم کا استعمال کر رہے ہیں۔

وزیر اعلی نے کہا کہ جھارکھنڈ میں سیاحت کے کافی امکان ہیں۔ یہاں عالمی سطح پر سیاحتی مقامات ہیں۔ سیاحت کی ترقی سے بڑی تعداد میں روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی غیر ملکی کرنسی بھی آئیگی۔ ہارے 24 میں سے 19 ضلعے اعلی ضلعوں کی فہرست میں شامل ہے۔ ریاست تعمیر کے چودہ سالوں کے بعد بھی ہمارے یہاں اسمبلی، ہائی کورٹ سکمیٹی دیگر اہم بلڈنگ نہیں تھے۔ ہماری حکومت نے انہیں بنوانے کا ذمہ لیا۔ یہ 2019 تک بن کر تیار ہو جائیں گے۔ اسی طرح ہم نیو کیپٹل کی تعمیر بھی کرا رہے ہیں۔ ان سبھی چیزوں کے لئے ہمیں کافی رقم کی ضرورت ہے۔ ان ضرورتوں کو پورا کر ہم جھارکھنڈ کو ترقی یافتہ ریاستوں کی فہرست میں شامل کر سکیں گے۔ پروگرام میں ریاستی حکومت کی جانب سے پرزینٹیشن پیش کیا گیا۔

نشست میں مالی کمیشن کے چیئرمین این کے سنگھ، خوراک سپلائی وزیر سریو رائے، صحت وزیر رام چندر چندر ونشی، وزیر تعلیم نیرا یادو، مزدور وزیر راج پالیوار، چیف سکریٹر سدھیر ترپاٹھی، ترقیاتی کمشنر ڈی کے تیواری، مالی محکمہ کے ایڈیشنل چیف سکریٹری سکھ دیو سنگھ، کمیشن کے ممبر شکتی کانت داس، ڈاکٹر رمشین، ڈاکٹر انوپ سنگھ، ڈاکٹر اشوک لہری سمیت ریاست حکومت کے سینئر افسران موجود تھے۔

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉची-834008

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम - प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

आयोग की अनुशंसा पर राज्य को कभी भी नहीं मिला केंद्रीय करों में पूरा हिस्सा

विशेष संवाददाता ▷ रांची

वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार को केंद्रीय करों में कभी उसका पूरा हिस्सा नहीं मिला. 15वें वित्त आयोग की बैठक में राज्य सरकार की ओर से इस बात की शिकायत की गयी. 14वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में राज्य ने फिर अपना पूरा हिस्सा नहीं मिलने की आशंका जतायी. साथ ही इससे संबंधित आंकड़े पेश किये.

राज्य सरकार की ओर से वित्त आयोग की अनुशंसाओं और उसकी हकीकत का उल्लेख करते हुए कहा गया कि 10वें वित्त आयोग की अवधि (1995-2000) के अंतिम साल नवंबर 2000 में राज्य का गठन हुआ. इसके बाद इस नवगठित राज्य को पहली बार 11वें वित्त आयोग से 13वें वित्त आयोग की अवधि में हिस्सेदारी देने की अनुशंसा बढ़ती गयी. पर हर वित्त आयोग की अवधि में राज्य को उसका हिस्सा नहीं मिलने का प्रतिशत बढ़ता रहा. 11वें वित्त आयोग की अनुशंसा के मुकाबले राज्य को 2.4 प्रतिशत हिस्सा कम मिला. जबकि 13वें वित्त आयोग की अवधि में यह बढ़ कर 3.8 हो गया. 11वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में 29.5 प्रतिशत हिस्सा देने की अनुशंसा की. हालांकि राज्य को केंद्रीय करों में सिर्फ 27.1 प्रतिशत हिस्सा हिस्सा ही मिला. 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में 30.5 प्रतिशत के बदले सिर्फ 26.3 प्रतिशत हिस्सा ही मिला. 13वें वित्त आयोग ने 32 प्रतिशत देने की अनुशंसा की. पर सिर्फ 28.2 प्रतिशत ही मिला. 14 वें वित्त आयोग ने राज्य को केंद्रीय करों में 42 प्रतिशत हिस्सा देने की अनुशंसा की. 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल अगले वित्तीय वर्ष समाप्त हो जायेगा. पर चालू वित्तीय वर्ष में अब तक सिर्फ 34.9 प्रतिशत हिस्सा ही मिल सका है. जो आयोग की अनुशंसा के मुकाबले फिलहाल 7.1 प्रतिशत कम है.

वित आयोग की अनुशंसा और हकीकत

वित आयोग	अनुशंसा	मिला	कमी
11वां वित आयोग	29.00%	27.4%	-1.6%
12वां वित आयोग	29.5%	27.1%	-2.4%
13वां वित आयोग	32.00%	28.2%	-3.8%
14वां वित आयोग	42.0%	39.9%	-7.1%

आदिवासी आबादी को केंद्रीय करों की हिस्सेदारी में महत्व देने की मांग

विशेष संवाददाता ▷ रांची

राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तय करने में आदिवासियों की आबादी को महत्व देने का मांग की है. साथ ही इसके लिए आयोग को फॉर्मूला के प्रारूप भी सौंपा है. राज्य सरकार ने 15 वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में हिस्सेदारी देने के लिए जारी फॉर्मूले में बदलाव का अनुरोध किया है. सरकार की ओर से कहा गया है कि विकास सूचकांक के अंतर को देखते हुए 50 प्रतिशत के महत्व को जारी रखना चाहिए. हालांकि इसमें 12 राज्यों के लिए निर्धारित दो प्रतिशत के फ्लोर में बदलाव करना चाहिए. आबादी के महत्व को 17.5 प्रतिशत से घटा कर 10 प्रतिशत करना चाहिए. साथ ही आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए उनकी आबादी को अलग से 10 प्रतिशत महत्व दिया जाना चाहिए. भौगोलिक स्थिति को 10 प्रतिशत महत्व देने के फॉर्मूले के समाप्त कर देना चाहिए. इसके बदल खनन और उत्खनन में ग्रास स्टेट वैल्यू एडिशन(जीएसवीए) को 10 प्रतिशत महत्व दिया जाना चाहिए. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए वन क्षेत्र को दिये जा रहे 7.5 प्रतिशत के महत्व को बढ़ा कर 10 प्रतिशत करना चाहिए.

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

आधारभूत संरचना के लिए मांगी गयी सबसे ज्यादा राशि

- राज्य सरकार ने अपनी मांगों के समर्थन में राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के साथ ही राजस्व और खर्च का दिया हवाला
- सरकार ने राज्य को विकास के मापदंड को पूरा करने और राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने के लिए आयोग से मांगा अनुदान
- सरकार द्वारा आयोग को सौंपे गये अनुदान मांग से संबंधित ज्ञापन में आधारभूत संरचना के विकास के लिए मांगीं गयी है सबसे ज्यादा राशि

राष्ट्रीय औसत के मुकाबले कई मामलों में झारखंड पीछे

विशेष संवाददाता ▷ रांची

राज्य सरकार ने वित्त आयोग की टीम के समक्ष विकास के मापदंड पर झारखंड की स्थिति का उल्लेख किया. इसके लिए सृजित सिंचाई क्षमता, स्वास्थ्य, साक्षरता और गरीबी के आंकड़ों को आधार बनाया गया. सरकार की ओर से विकास के इन मापदंडों का राज्य और राष्ट्रीय औसत का तुलनात्मक ब्योरा पेश किया गया. सरकार की ओर से आंकड़ों के हवाले से यह कहा गया कि झारखंड में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की एक बड़ी आबादी राष्ट्रीय औसत के मुकाबले गरीब है. राज्य में कुल 49.7 प्रतिशत एसटी और 40.4 प्रतिशत एससी गरीब हैं. जबकि एसटी की गरीबी का राष्ट्रीय औसत 40.6 प्रतिशत और एससी का 29.9 प्रतिशत है. वहीं, राज्य में बीपीएल आबादी का औसत राष्ट्रीय स्तर से ज्यादा बताया गया है. राष्ट्रीय स्तर पर बीपीएल आबादी का औसत 21.92, जबकि राज्य में बीपीएल आबादी का औसत 36.51 है

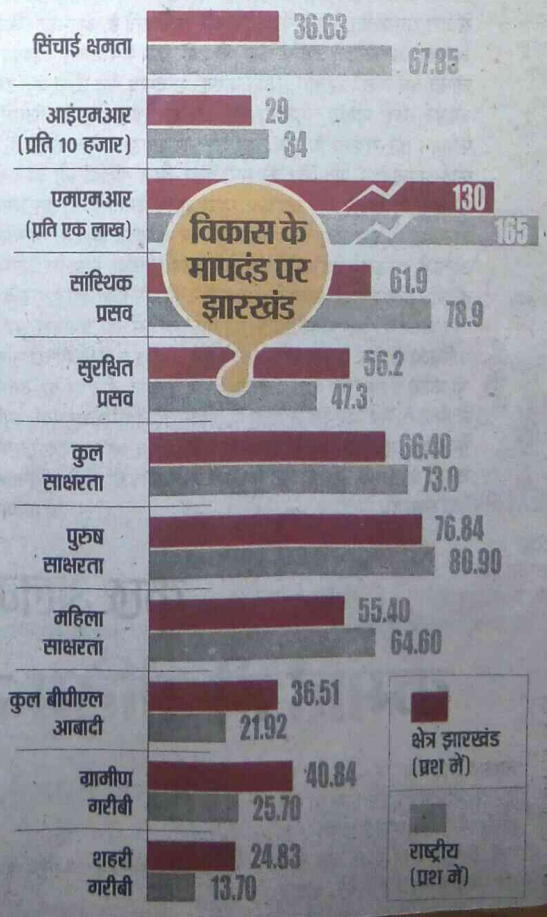

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची
***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर.के.मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - हिन्दुस्तान
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

विस्थापितों के लिए राज्य को विशेष पैकेज देने की हो अनुशंसा

भाजपा की मांग

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय वित्त आयोग से जल, जंगल और जमीन के एवज में झारखंड को विशेष रियायत देने की मांग की है। वित्त आयोग के साथ बैठक में भाजपा के प्रदेश महासचिव दीपक प्रकाश ने कहा कि झारखंड के वृहत उद्योग और खनिज का उपभोग तो पूरा देश करता है। लेकिन झारखंड की आधारभूत संरचना पर काफी दबाव पड़ता है। इससे काफी विस्थापन भी होता है। इनके पुनर्वास के लिए केंद्रीय वित्त आयोग को राज्य को विशेष पैकेज देने की अनुशंसा करनी चाहिए।

50 फीसदी मिले हिस्सेदारीः राजद :राजद के आबिद अली ने वित्त आयोग के सामने कहा, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, विस्थापन, पलायन को देखते हुए झारखंड को केंद्रीय करों में 50 फीसदी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए।

गुरुवार को रेडिसन ब्लू में आयोजित बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, भाजपा के दीपक प्रकाश व अन्य।

वित्त आयोग के पास आदिवासियों को बचाने का एजेंडा नहींः हेमंत

पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वित्त आयोग पर भाजपा के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग मोदी सरकार के स्लोगन न्यू इंडिया-2022 की बात कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आयोग अंपायर होकर भी केंद्र सरकार जैसे खिलाड़ी के हाथ में खेल रहा है। आदिवासियों को बचाने का कोई एजेंडा नहीं है। झारखंड जैसे राज्य में विकास का कौन सा रास्ता सही होगा, इसके बारे में विचार करने की जरूरत है। खान, खनिज के लिए लगातार उजड़ने वाले आदिवासियों को इससे क्या मिलता है। वित्त आयोग को अपनी अनुशंसाओं में इसे भी रेखांकित करने की जरूरत है।

कांग्रेस और झाविमो ने मांगा विशेष राज्य का दर्जा

कांग्रेस और झाविमो ने केंद्रीय वित्त आयोग से प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार और झाविमो विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि झारखंड स्पेशल स्टेटस का दर्जा प्राप्त करने की पांच में से चार शर्तों को पूरा करता है। यह पहाड़ी क्षेत्र भी है। बड़ा हिस्सा आदिवासी क्षेत्र भी है। आर्थिक पैमाने पर पिछड़ा है। आधारभूत संरचना कमजोर है। केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बड़ी नहीं है। इसके बाद भी झारखंड के विकास के लिए इसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा देने की जरूरत है। भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता ने भी इसी तरह की मांग की।

आदिवासी, दलित को मिले फंडः आजसू

आजसू के प्रवक्ता जयंत घोष ने कहा कि झारखंड की 80 फीसदी आबादी आदिवासी, दलित और पिछड़ों की है। ये लोग लंबे समय तक भेदभाव और उपेक्षा के शिकार हुए हैं। इसलिए इनके उत्थान के लिए अलग से फंड देने की जरूरत है। सकल घरेलू उत्पाद राज्य की सही तस्वीर नहीं पेश करता क्योंकि, यह राज्य में केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के कारण है। इनका समुचित लाभ राज्य को नहीं मिलता है।

झारखंड ने क्षमता का पूरा उपयोग नहीं कियाः एनके सिंह

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

भारत सरकार के 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा है कि झारखंड ने अपनी क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया। यहां की समस्याएं भी काफी अलग हैं। इसके समाधान के लिए अलग से पहल जरूरी है। एनके सिंह गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे।

सिंह ने झारखंड सरकार की भी तारीफ की। कहा- हाल में कई अच्छे कदम उठाए गए हैं। इससे बेहतरी की उम्मीद है। देश के आर्थिक विकास की रफ्तार से झारखंड को भी चलना है। इसके लिए कुछ जिलों में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर करना होगा। सरकार इन चुनौतियों के प्रति सचेत है। बजट प्रबंधन ठीक करना है।

राजस्व की अनिश्चितता बड़ी समस्याः एनके सिंह ने कहा कि झारखंड में राजस्व की अनिश्चितता बड़ी समस्या है। राजकोषीय घाटे पर काबू पाने की जरूरत है। उदय बांड्स के बाद भी बिजली निगमों की स्थिति नहीं सुधरी है। राज्य वित्त आयोग के गठन नहीं होने पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि यह संवैधानिक व्यवस्था से परे है।

➤ संबंधित खबरें पेज 04

रांची में गुरुवार को बैठक से पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह से मुलाकात करते मुख्यमंत्री रघुवर दास।

ये चुनौतियां गिनाईं

- 14 वें वित्त आयोग से मिली राशि का जिला परिषद तक नहीं जा सकी।
- झारखंड में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का लगभग आधा है। इसे ठीक करना होगा।
- जीएसटी से होने वाले सालाना 2500 करोड़ के नुकसान को देखने की जरूरत है।

“ झारखंड सरकार ने हाल के दिनों में कई अच्छे कदम उठाए हैं। इससे बेहतरी की उम्मीद है। शिशु मृत्यु दर में सुधार बड़ी उपलब्धि है। झारखंड को कुछ जिलों में व्याप्त आर्थिक विषमता दूर करनी होगी।

एनके सिंह, चेयरमैन, वित्त आयोग

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची–834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रांची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

कोयले के सेस को जीएसटी मुआवजा में मिलाने पर सरकार ने जतायी आपत्ति

विशेष संवाददाता ▷ रांची

राज्य सरकार ने कोयले पर मिलनेवाले सेस को जीएसटी में मिलाने के फैसले पर आपत्ति जतायी है. सरकार का मानना है कि इससे कोयला उत्पादन करनेवाले राज्यों को नुकसान होगा. इस मामले में झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान होगा. क्योंकि झारखंड कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है.

आयोग की बैठक में सरकार की ओर से कहा गया कि खनिज संपदा से भरे हुए राज्य पहले औद्योगिकीकरण की वजह से नुकसान उठा चुके हैं. इसके बाद फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के वजह से और ज्यादा नुकसान हुआ. थर्मल पावर प्लांट दूर के राज्यों में स्थापित हुआ, जो वहां के उद्योगों को शक्ति प्रदान कर रहे हैं. खनन कार्यों से पर्यावरण को होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए कोयले पर सेस लगाया गया था. हालांकि, इस मद में मिली राशि का एक बड़ा हिस्से का अब तक उपयोग नहीं किया जा सका है. वित्तीय वर्ष 2011-17 तक की अवधि में क्लीन एनर्जी सेस के रूप में 53967.23 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. इसमें से सिर्फ 28.69 प्रतिशत यानी 15483.21 करोड़ रुपये ही राज्यों को दिये गये हैं. शेष 71.31 प्रतिशत यानी 38484.02 करोड़ रुपये केंद्र सरकार के पास पड़ा हुआ है. अब इस राशि को जीएसटी से होनेवाले नुकसान बदले दिये जानेवाले मुआवजा राशि में मिलाने का फैसला किया गया है. इससे कोयला पर मिले सेसे की राशि का उपयोग वैसे राज्य भी करेंगे जो कोयले का उत्पादन नहीं करते हैं. यानी कोयले के खनन से पर्यावरण को होनेवाले नुकसान खनिजों वाले राज्य उठायेंगे. जबकि सेस से मिलनेवाली राशि का इस्तेमाल सभी राज्य करेंगे. इस नीति से झारखंड को सबसे ज्यादा नुकसान होगा.

जीएसटी से नुकसान की भरपाई के लिए 2022 के बाद भी मुआवजे की मांग

विशेष संवाददाता ▷ रांची

राज्य सरकार ने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विस टैक्स) लागू होने से होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे की अवधि समाप्त होने के बाद भी मुआवजा जारी रखने की मांग की है. आयोग के साथ हुई बैठक में राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया कि जीएसटी से राज्य को कुल 3492.73 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. राज्य सरकार की ओर से इस मुद्दे पर चर्चा करते हुए कहा गया कि जीएसटी से होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल तक ही मुआवजा देने का प्रावधान है. राज्य को होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा 2022 के बाद भी जारी रखना चाहिए. सरकार ने जीएसटी से होनेवाले नुकसान का उल्लेख करते हुए कहा कि कोयला, खानेवाला तेल, रेडीमेड कपड़ा, सिगरेट आदि पर वैट के मुकाबले जीएसटी में टैक्स दर कम होने से राज्य को नुकसान हो रहा है. टैक्स दर किये गये इस बदलाव से 723.67 करोड़ रुपये का नुकसान होगा. वैट की अवधि में राज्य को इनपुट टैक्स क्रेडिट मद में 1746 करोड़ रुपये की आमदनी होती थी. पर जीएसटी में राज्य को इसका नुकसान होगा. इसके अलावा सेंट्रल सेल्स टैक्स समाप्त करने की वजह से राज्य को 1023.06 करोड़ का नुकसान होगा. राज्य को होनेवाले इस नुकसान से बचाने के लिए 2022 के बाद भी मुआवजा मिलना चाहिए.

जीएसटी से होनेवाले नुकसान का ब्योरा (करोड़ में)

723.67
टैक्स दर में बदलाव से नुकसान

1746.00
इनपुट क्रेडिट टैक्स से नुकसान

1023.06
सीएसटी समाप्त करने से नुकसान

ई-पत्र / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.01.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

झारखंड को वित्त आयोग से उम्मीदें

भारतीय वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी. इसका उद्देश्य भारत सरकार एवं राज सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करना है. आयोग राज्यों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का आकलन करने और राज्यों की बात सुनने के बाद केंद्रीय करों में उसकी भागीदारी तय करने के लिए राष्ट्रपति को अनुशंसा करता है. संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत संचित निधि में से राज्यों को दिये जानेवाले अनुदान और सहायता की अनुशंसा करता है.

मिले ज्यादा पैसे, तो तेज होगा विकास

वित्त आयोग से डेढ़ लाख करोड़ अनुदान की मांग

विशेष संवाददाता ▷ रांची

राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग को ज्ञापन सौंप कर विकास के लिए कुल 150002.73 करोड़ रुपये अनुदान की मांग की है. सरकार की ओर से अपनी मांगों के समर्थन में राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के साथ ही राजस्व और खर्च का हवाला दिया गया. सरकार की ओर से राज्य को विकास के मापदंड को पूरा करने और राष्ट्रीय औसत के बराबर पहुंचने के लिए अनुदान के इस रकम की मांग की गयी. वित्त आयोग को सौंपे गये अनुदान मांग से संबंधित ज्ञापन में सबसे ज्यादा राशि की मांग आधारभूत संरचना के लिए की गयी है. इस मद में 88,199.66 करोड़ की मांग की गयी है. इसके बाद कृषि क्षेत्र के लिए 42,598.02 करोड़ रुपये की मांग की गयी है. सरकार ने सामाजिक क्षेत्र के लिए 17001.39 करोड़ रुपये की मांग की है. सरकार ने आयोग से अनुदान की राशि को खर्च करने के लिए लगायी जानेवाली कठोर शर्तों के कम करने की मांग की, ताकि अनुदान की राशि का पूरा पूरा इस्तेमाल किया जा सके.

कुल मांग **150002.73** करोड़

कृषि क्षेत्र **42598.02** करोड़

सामाजिक क्षेत्र **17001.39** करोड़

आधारभूत संरचना **88199.66** करोड़

राजस्व व सामान्य प्रशासन **2203** करोड़

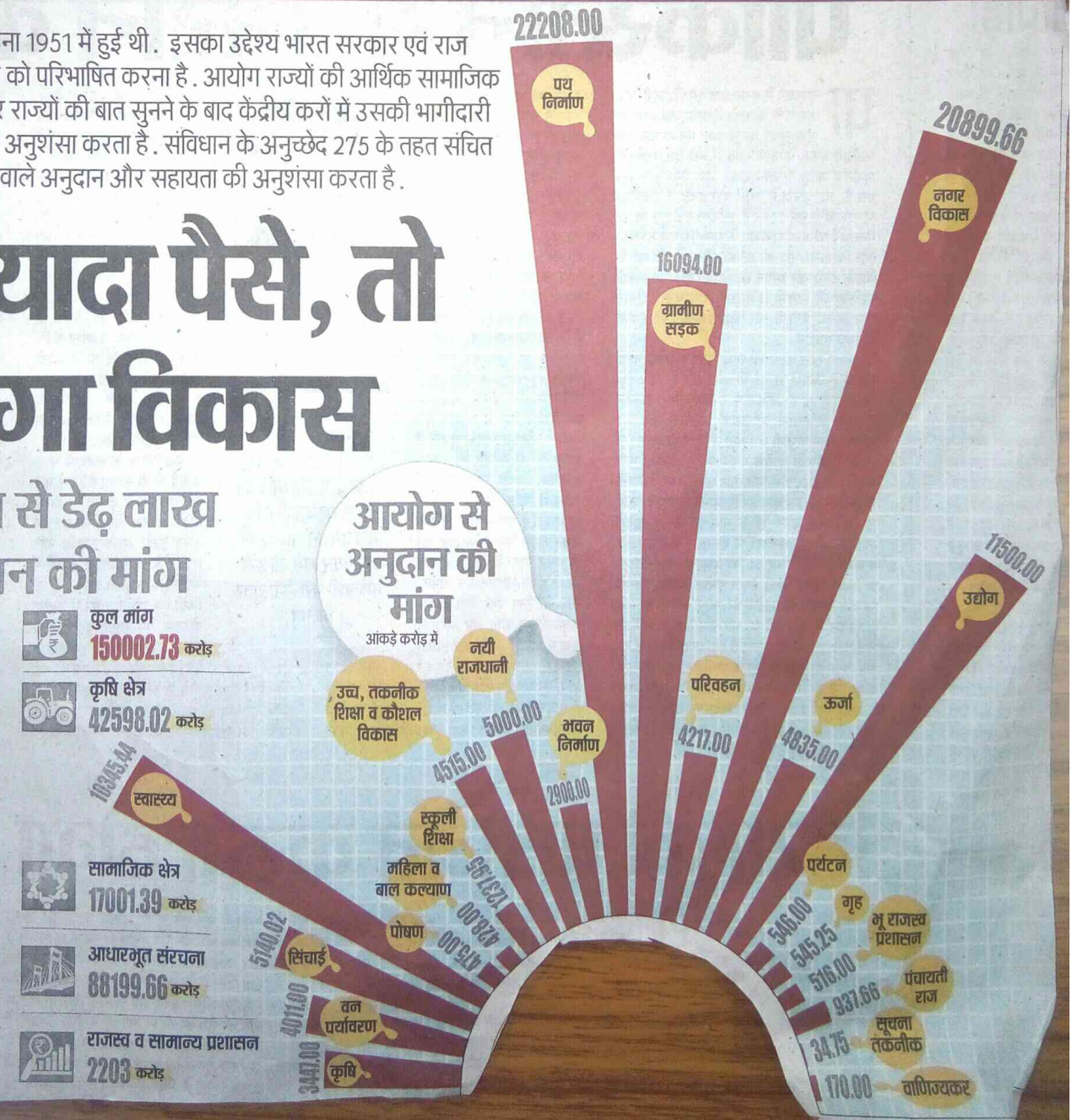

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

मंथन. वित्त आयोग ने राजनीतिक दलों के साथ की बैठक

सभी दलों ने राज्य के लिए मांगी आर्थिक मदद

- सिर्फ खनिज संपदा के दोहन पर ही नहीं, मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने पर भी जोर दिया जाये

वरीय संवाददाता ▷ रांची

वित्त आयोग के साथ राजनीतिक दलों की हुई बैठक में सभी ने राज्य को ज्यादा से ज्यादा आर्थिक मदद देने की मांग उठायी. हालांकि जहां सत्ता पक्ष ने सरकार के कार्यक्रमों की सराहना करते हुए आर्थिक मदद बढ़ाने की मांग की, वहीं विपक्षी दलों ने फिजूलखर्ची के लिए सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लेते हुए वित्त आयोग से राज्य हित में आर्थिक मदद बढ़ाने की मांग रखी.

वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में मौजूद राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि.

संसाधन और आदिवासी-विस्थापितों पर ध्यान देने की है जरूरत : भाजपा

15वें वित्त आयोग के समक्ष सत्ताधारी दल भाजपा की ओर से महामंत्री दीपक प्रकाश और उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने पार्टी का पक्ष रखा. पार्टी की ओर से 11 सूत्री मांग पत्र रखा गया. कहा गया कि झारखंड असीम संभावनाओं का राज्य है. इसकी रत्नगर्भा भूमि को प्रकृति ने मुक्तहस्त से सजाया और संवारा है. जिस प्रकार से देश के सर्वांगीण विकास एवं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यहां की खनिज संपदा का दोहन होता रहा है, उस अनुपात में राज्य में मूलभूत सुविधाओं के विकास का कार्य नहीं हो सका है.

वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद वर्ष 2014 तक राज्य में 9 सरकारें आयी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ. राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य की प्रगति अपेक्षाकृत कम हुई. वर्ष 2014 से राजनीतिक स्थिरता आयी है और हमारी प्रगति तेज हुई है. इसमें वित्त आयोग से सहयोग की जरूरत है, जिससे राज्य का और तेजी से विकास हो सके. भाजपा की ओर से दिये गये ज्ञापन में कहा गया है कि वित्त आयोग राज्य में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को सरल करते हुए विकास कार्यों के लिए भूमि की उपलब्धता पर समुचित ध्यान दे. राज्य में 27 प्रतिशत आबादी अनुसूचित जनजातियों की है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना आवश्यक है. खनिज की उपलब्धता के आधार पर यहां वृहत उद्योग एवं खनन कंपनियां कार्यरत हैं, लेकिन ये कंपनियां यहां के आधारभूत संरचना पर अत्यधिक दबाव तो डालती ही हैं. साथ ही जल, जंगल एवं जमीन का विस्थापन भी करती है. केंद्र सरकार को पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए. इन कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित हैं. इन सभी के कारण यहां की जनता गरीब एवं कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं. 70 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है. सिंचाई की बड़ी परियोजना को पूरा करने के लिए संसाधन दें. राज्य के 24 में से 19 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं. गत वर्षों में उग्रवादी घटनाओं को काफी नियंत्रित भी किया गया है, लेकिन राज्य की पुलिस प्रशासन को और चुस्त-दुरुस्त तथा तकनीकी रूप से सक्षम एवं साधन संपन्न बनाने के लिए भी संसाधन की आवश्यकता है. रेल नेटवर्क को बढ़ाने में सहयोग किया जाये.

सरकार की लोकलुभावनी योजनाओं पर कटौती करने की जरूरत : झामुमो

नेता प्रतिपक्ष सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि किसी भी क्षेत्र का विकास राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अन्य क्रियाओं से निर्धारित होता है. ऐसे में वित्त आयोग से अनुरोध है कि केंद्र राजस्व के बंटवारे के संबंध में कोई भी फार्मूला निकालने से पहले झारखंड के सामाजिक, आर्थिक सूचकांकों पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए. इसमें झारखंड की भौगोलिक का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए.

झारखंड में आदिवासी आबादी को मापदंड के रूप में अपनाते हुए संसाधन आवंटन पर विचार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि लोकलुभावन योजनाओं पर खर्च में कटौती करने वाले राज्यों को प्रोत्साहन देने का काम वित्त आयोग द्वारा किया जाना है. इसका अर्थ है कि जो सरकार लोकलुभावन योजनाओं पर कम राशि खर्च करेगी, उसे केंद्रीय राशि के आवंटन में प्रोत्साहन दिया जायेगा. यदि झारखंड के मुख्यमंत्री यह निर्णय लेते हैं कि मानसरोवर की यात्रा करने वाले झारखंडियों को एक लाख रुपये का अनुदान दिया जायेगा, तो यह कौन तय करेगा की यह योजना लोकलुभावन या लोकोपयोगी या कल्याणकारी योजना है. यदि सौ करोड़ की लागत से मोरहाबादी मैदान में टाइम स्क्वायर बनेगा, तो यह कौन तय करेगा कि यह योजना कौन सी है. आयोग का टोटल फर्टिलिटी रेट कहता कि जिन राज्यों को टीएफआर कम है. यानि 2:1 है या उससे कम है, वैसे राज्यों को केंद्रीय राजस्व आवंटन में प्रोत्साहन दिया जायेगा. टीएफआर वहीं ज्यादा है जहां गरीब ज्यादा हैं. जहां निरक्षरता, दलित, आदिवासी ज्यादा हैं. यहां टीएफआर घटाने को प्रोत्साहन राशि से जोड़ना विनाशकारी साबित होगा. श्री सोरेन ने कहा कि बदले हुए कर प्रणाली के आलोक में वित्त आयोग के स्वरूप में नयापन दिखना चाहिए था, जो नहीं दिखता है. सिर्फ झारखंड को जीएसटी के कारण जून 2018 तक लगभग 2500 करोड़ की कमी राजस्व में हुई है. इसमें लगभग 30 प्रतिशत का शॉर्टफाल हुआ है. वर्ष 2022 तक इस कमी की भरपाई केंद्र सरकार करेगी, लेकिन उसके बाद क्या होगा. एक अनुमान के अनुसार वर्ष 2025 तक राज्य सरकार के राजस्व में लगभग 1300 करोड़ का नुकसान होगा. श्री सोरेन ने आयोग के टीओआर में न्यू इंडिया-2022 पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह भाजपा का पॉलिटिकल स्लोगन है. इसके लिए धन कर्णांकित करना सही नहीं है.

झारखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा : कांग्रेस

15वें वित्त आयोग के समक्ष कांग्रेस ने झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देते हुए विशेष अनुदान देने की मांग की है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ अजय कुमार ने कांग्रेस भवन में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि झारखंड में बीपीएल परिवार 48 प्रतिशत है, जबकि देश में 29 प्रतिशत हैं. विशेष पैकेज के लिए पांच मापदंड होते हैं. इसमें झारखंड चार मापदंड को पूरा करता है. केवल एक मापदंड अंतरराष्ट्रीय सीमा को झारखंड पूरा नहीं करता. डॉ अजय ने कहा कि झारखंड में प्रति व्यक्ति आय को अधिक बताया जाता है, जबकि यहां काफी गरीबी है. प्रति व्यक्ति आय सेल, बीसीसीएल, टाटा स्टील जैसी कंपनियों की वजह से है न कि लोगों की आय से. आबादी के घनत्व मापदंड में झारखंड को अधिक बताया जाता है, जबकि यह गलत है. झारखंड की आबादी का घनत्व 441 बताया जाता है, जबकि देश में 380 है. आबादी घनत्व केवल रांची, जमशेदपुर और धनबाद में अधिक है. अन्य जिलों में यह काफी कम है. डॉ अजय ने कहा कि वित्त आयोग से पार्टी ने विशेष अनुदान की मांग की है, क्योंकि यहां शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सड़क, पेयजल आदि की स्थिति खराब है. 27 प्रतिशत की आबादी आदिवासियों की है, जो काफी पिछड़े हुए हैं. इसके लिए झारखंड को ज्यादा अनुदान की जरूरत है. डॉ अजय ने कहा कि बैठक में विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गयी, जब सत्ता में शामिल भाजपा की सहयोगी पार्टी आजसु ने कहा कि यहां भुखमरी से मौत हो रही है, जबकि सरकार यह बात नहीं मानती. आजसू ने कहा कि झारखंड सबसे पिछड़ा राज्य है, जबकि सबसे ज्यादा समय तक यहां भाजपा का ही शासन रहा है.

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - प्रभात खबर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

वित्त आयोग को राज्य के आर्थिक व सामाजिक स्थिति की दी गयी जानकारी

झारखंड ने केंद्रीय करों में 42 की जगह 50 फीसदी हिस्सेदारी मांगी

विशेष संवाददता ▷ रांची

राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी 42 फीसदी से बढ़ा कर 50 प्रतिशत करने की मांग की. केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के लिए निर्धारित फार्मूले में बदलाव और आदिवासियों की आबादी को भी 10 प्रतिशत महत्व देने का मांग रखी. साथ ही राज्य में कृषि, सामाजिक, राजस्व प्रशासन और आधारभूत संरचना के लिए आयोग से 1.5 लाख करोड़ रुपये अनुदान देने की मांग की. वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से राज्य के आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी दी. राज्य सरकार ने केंद्रीय करों में भागीदारी बढ़ाने की मांग के साथ ही 14 वें वित्त आयोग द्वारा हिस्सेदारी तय करने के लिए निर्धारित फार्मूले में बदलाव की मांग की. सरकार की ओर से पहली बार आदिवासियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का उल्लेख करते हुए केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के फार्मूले में उन्हें 10% महत्व देने की मांग की गयी.

● बाकी पेज 15 पर

केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के फार्मूले में आदिवासी आबादी को 10% महत्व देने की मांग

- राज्य में खनिज संपदाओं के खनन से पर्यावरण पर पड़नेवाले प्रभाव को देखते हुए वन क्षेत्र के महत्व को 7.5 प्रतिशत से बढ़ा कर 10 प्रतिशत करने की मांग की
- अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से झारखंड के आर्थिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी दी

अनुदान मांग का ब्योरा

कुल मांग (करोड़ में)	150002.73
कृषि क्षेत्र के लिए	42598.02
सामाजिक क्षेत्र के लिए	17001.39
आधारभूत संरचना	88199.66
राजस्व व सामान्य प्रशासन	2203

गरीबी और खनन से पर्यावरण पर पड़ रहा दुष्प्रभाव झारखंड की बड़ी समस्या

प्रेस कांफ्रेंस में वित्त आयोग के अध्यक्ष ने झारखंड के संबंध में खुल कर बात की

बरीय संवाददाता ▷ रांची

वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा है कि आदवासियों की गरीबी और खनिजों के खनन से पर्यावरण पर पड़नेवाला दुष्प्रभाव झारखंड की बड़ी समस्या है. 15वें वित्त आयोग से राज्य सरकार ने 27 फीसदी आदिवासी आबादी और खनिजों के दोहन से पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभाव के मद्देनजर अलग से व्यवस्था करने की मांग की है. आयोग इस पर विचार कर रहा है. उन्होंने बताया कि केंद्रीय करों में राज्यों की भागीदारी तय करने के क्रम में राज्य सरकार 2011 की जनगणना को आधार बनाने के पक्ष में है.

● बाकी पेज 15 पर

वित्त आयोग से मांग

- खनन के दौरान दुर्घटना, बिजली गिरने, हाथी सहित अन्य जानवरों द्वारा पहुंचाये जानेवाले नुकसान जैसी आपदाओं पर राज्य को मदद की जरूरत है. इस मद में 20% राशि देने की अनुशंसा करने की मांग
- कोयले की रॉयल्टी बढ़ा कर 20% करें, 2012 से रिवाइज नहीं हुआ है
- आयोग की अनुशंसा के आलोक में केंद्रीय करों का पूरा हिस्सा दें
- अनुदान की राशि खर्च करने के लिए तय शर्तों को कम किया जाये
- केंद्रीय करों में हिस्सेदारी तय करने के फार्मूले में बदलाव किया जाये
- कोयले पर मिलनेवाले सेस को जीएसटी के मुआवजे में नहीं मिलायें
- जीएसटी से होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा जारी रखें
- जुडिशियरी के लिए 2900 करोड़ रुपये की मांग की गयी

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – राष्ट्रीय खबर हमारी नज़र
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

बैठक

15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोले मुख्यमंत्री रघुवर दास

स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों में गति आयी

- 14 वर्ष के बाद तो काम में तेजी आयी
- अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान दे आयोग
- दिसंबर 2018 तक हर घर में बिजली

संवाददाता

रांची : 14 वर्ष राजनीतिक अस्थिरता होने के कारण झारखंड निर्माण का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। यही कारण है कि मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास ने कहीं। वे 15वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में बोल रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पिछड़े राज्य विकसित होंगे, तभी भारत भी पूरी तरह से विकसित होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नये भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आये। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाना का काम तेजी से किया जा रहा है। गांव में इनके पहुंचते ही लोगों के जीवन में गुणात्मक बदलाव आ जायेगा। श्री दास ने कहा कि राज्य के सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी गयी है। अब घर-घर बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया जा रहा है। दिसंबर 2018 तक हम राज्य के हर घर को रोशन करने का लक्ष्य लेकर काम कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैगशीप योजनाओं को लाभूकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समूचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। इसके कई तरह की बीमारियों से वे ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हम लोगों तक पाइप लाइन के माध्मय से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हमने डिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आयी राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की काफी संभावना है। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी आयेगी। हमारे 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्षों के बाद भी हमारे यहां विधान सभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। हमारी सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया, ये 2019 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। इसी तरह हम न्यू कैपिटल के निर्माण भी करा रहे हैं।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - राष्ट्रीय खबर हमारी नज़र
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद वित्त आयोग अध्यक्ष ने कहा

पंचायत को तीनों स्तरों पर पैसा देने पर बनेगी सहमति

संवाददाता

रांची : वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत समिति के दो स्तरों को पैसा देने की अनुशंसा नहीं की थी। बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में तीनों स्तरों को पैसा देने की मांग उठी। बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी आये। इन सभी सुझावों पर आम सहमति बनायी जायेगी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने शहरी स्थानीय निकायों व ग्रामीण स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बाद यह बात कही। पत्रकारों से बात करते हुए श्री सिंह ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय व ग्रामीण स्थानीय निकाय के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव आये।

ऐसे ही सुझाव अन्य राज्यों से भी आये हैं। ये सुझाव आयोग को आम सहमति बनाने में काफी सकारात्मक हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव पंचायत के तीनों स्तरों को धन देने का था।

14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर जिला परिषद व पंचायत समिति को अनुदान के रूप में कोई राशि नहीं मिल रही थी। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय के अनुरूप ही ग्रामीण निकायों को भी अनुदान देने की मांग की गयी। श्री सिंह ने कहा कि बैठक सकारात्मक रही। ग्रामीण निकायों के जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर अमल किया जायेगा।

उनका सुझाव काफी अच्छा है। इस पर पुनर्विचार किया जायेगा। इन्होंने सामूहिक रूप से एक ज्ञापन भी दिया है। इस पर विचार किया जायेगा। उन्होंने कहा कि आयोग इस पर राज्य सरकार से कल बात करेगी। नगर निकायों के जन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के बारे में उन्होंने कहा कि जल का अभाव, जल निकासी व जल की गुणवत्ता के बारे में जन प्रतिनिधियों ने बातें रखी है। खास कर गंदे पानी की निकासी के बारे में समस्या का हल हो, इसकी बहुत आवश्यकता है। इसकी राशि की जो आवश्यकता है, इस पर भी जन प्रतिनिधियो ने अपनी बातें रखी है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी,रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - राष्ट्रीय खबर हमारी नज़र
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

सुझाव झारखण्ड को मिले उसका हक, वैज्ञानिक और नीड बेस्ड हो फंडिंग पैटर्न : महेश पोद्दार

15वें वित्त आयोग को पत्र लिखकर राज्यसभा सांसद ने की मांग

संवाददाता

रांची : राज्यसभा सांसद श्री महेश पोद्दार ने 15वें वित्त आयोग को पत्र लिखकर झारखण्ड को अधिकाधिक आर्थिक संरक्षण और वाजिब हिस्सेदारी देने की मांग की है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को संबोधित अपने पत्र में श्री पोद्दार ने आवंटन की अबतक की प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों का जिक्र किया है और वैज्ञानिक व नीड बेस्ड आवंटन पद्धति अपनाने हेतु सुझाव भी दिए है।

श्री पोद्दार ने कहा कि वैसे खनिजों के उत्पादन को जिनका मूल्यवर्द्धन करनेवाले कारखाने अन्य राज्यों में हैं,राज्य की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिऐ खनिजों के उत्पादन को राज्य की जीडीपी में तभी जोड़ा जाये जब उनका मूल्यवर्द्धन और इस्तेमाल राज्य में ... कि आर्थिक लाभ किसी अन्य राज्य को मिल रहा है, झारखण्ड को केवल रॉयल्टी मिल रही है लेकिन राज्य की जीडीपी में वृद्धि का भ्रम उत्पन्न होता है।

श्री पोद्दार ने कहा कि खदानों की नीलामी से राज्य को प्राप्त राजस्व नकद के साथ साथ जनसेवाओं के रूप में भी हो इस प्रक्रिया के माध्यम से खनिज उत्पादक द्वारा ... मौलिक सुविधाओं का सृजन होगा जो अंततः देश की उत्पादकता बढ़ाने में सहायक होगो

उन्होंने कहा कि इसी प्रकार की समस्या औद्योगिक संयंत्रों और राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों के मामले में भी है। उदाहरणार्थ; दामोदर घाटी निगम के अधिकांश ताप विद्युत संयंत्र, अधिकांश जलागार, अधिकांश जल विद्युत संयंत्र ... मुख्यालय राज्य में नहीं होने की वजह से झारखण्ड अर्जित राजस्व के एक बड़े हिस्से से वंचित हो जाता है।

शहरी विकास योजनाओं के लिए निर्गत राशि राज्य सरकार को भेजे जाने की बजाय सीधे सम्बंधित नगर निकायों को भेजी जानी चाहिए। झारखण्ड में निर्वाचित नगर निकाय सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं और विकास प्रक्रिया में प्राथमिक स्तर के लोकतंत्र को मजबूत करने का यह प्रयास दूरगामी परिणाम देने में सक्षम होगा।

सब्जियों के उत्पादन में झारखण्ड अग्रणी है लेकिन उत्पादित सब्जियों को लम्बे समय तक सुरक्षित रखने का पर्याप्त इंतजाम नहीं होने की वजह से बहुधा कृषकों को इन्हें सड़क पर अथवा लागत मूल्य से भी कम कीमत पर बेचने को विवश होना पड़ता है। यदि कोल्ड चेन उपलब्ध कराकर कृषकों को उत्पादित सब्जियां लम्बे समय तक सुरक्षित रखने और बाजार में अच्छी कीमत मिलने पर बेचने की सुविधा दे दी जाय तो सब्जी उत्पादन झारखण्ड के किसानों का एक बड़ा आर्थिक आधार बन सकता है।

अगर वित्त आयोग का समर्थन मिले तो राज्य सरकार अनाजों की तरह ही सब्जियों के लिए भी उत्पादन लागत का डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर सब्जियां खरीद सकती है और वेजफेड के माध्यम से उसका विपणन कर सकती है।

झारखण्ड की कृषि योग्य भूमि एक फसली है, पैदावार भी कम होती ... उपलब्ध न होने की वजह से किसानों को कम कीमत पर फसल बेचनी पड़ती है। इससे कृषकों की अवस्था खराब हो रही है। बेहतर होगा कि इनके लिए कोई उत्कृष्ट फंडिंग पैटर्न अपनाया जाय ताकि वे कृषि से विमुख होने को विवश न हों।

महिलाओं को कम पारिश्रमिक वाले रोजगार की बजाय उच्च पारिश्रमिक वाले रोजगार से जोड़ना श्रेयस्कर हो सकता है। इसके लिए उन्हें स्वास्थ्य परिचारिका का प्रशिक्षण उपलब्ध कराना एक उत्कृष्ट जरिया होगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की 'आयुष्मान भारत'योजना स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर सृजित करने में सक्षम है और झारखण्ड की बालिकाओं/महिलाओं की इस-

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष - 0651-2551102
फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

राजभवन में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मिलते वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह, साथ हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास व अन्य • जागरण

राज्यपाल ने दिया रात्रि भोज

राज्य ब्यूरो, रांची : राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के सम्मान में गुरुवार को राजभवन में रात्रि भोज दिया। इस रात्रि भोज में मुख्यमंत्री रघुवर दास, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी व कई वरीय पदाधिकारी शामिल हुए।

सिटी ट्रांसपोर्ट पर कुछ नहीं हुआ

राब्यू, रांची : वित्त आयोग की टीम ने सिटी ट्रांसपोर्ट पर कुछ खास न किए जाने को संजीदगी से लिया। आयोग के एक सदस्य ने कहा कि सिटी ट्रांसपोर्ट को दुरुस्त करने की दिशा में जो कदम उठाए जाने चाहिए थे, वे नहीं उठाए गए। अन्य राज्य जहां मेट्रो चला रहे हैं वहीं, झारखंड में जरूरी ओवरब्रिज तक का निर्माण नहीं हो पा रहा है।

नुकसान सरकार ने जीएसटी के कर ढांचे की विसंगति का मामला उठाया

जीएसटी से 30 फीसद राजस्व की चपत

राज्य ब्यूरो, रांची : गत वित्तीय वर्ष से देश भर में प्रभावी नई कर व्यवस्था गुड्स एवं सर्विस टैक्स (जीएसटी) से झारखंड को भारी नुकसान हुआ है। गुरुवार को 15 वें वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुति में राज्य सरकार ने जीएसटी से हो रहे घाटे का जिक्र करते हुए इसके नुकसान की भरपाई का अनुरोध वित्त आयोग से किया।

वाणिज्यकर विभाग के अपर मुख्य सचिव केके खंडेलवाल ने अपनी प्रस्तुति में स्पष्ट किया कि जीएसटी लागू होने से झारखंड को 30 फीसद राजस्व की क्षति पहुंच रही है। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा महज 17 फीसद ही है। जाहिर है कि नई कर व्यवस्था का सीधा असर झारखंड पर पड़ा है। इसका मुख्य कारण जीएसटी के कर ढांचे में की गई व्यवस्था है। बताया गया कि जीएसटी में यह प्रावधान किया गया है कि उत्पाद की खपत जिस राज्य में होगी टैक्स उसी राज्य के खाते में जाएगा। झारखंड उत्पादक राज्य है, यहां के उत्पादों की खपत दूसरे राज्यों में होती है। ऐसे में बड़े टैक्स से राज्य को वंचित होना पड़ता है। इस विसंगति को सुधारने का अनुरोध वित्त आयोग से किया गया। यह भी कहा गया कि जीएसटी में पांच साल तक राज्यों के घाटे की भरपाई का प्रावधान किया गया है, यदि इसके बाद भी घाटा होता है तो इसकी भरपाई कौन करेगा।

> झारखंड उत्पादक राज्य है, खपत वाले राज्यों को हो रहा लाभ
> कहा- पांच साल बाद कौन करेगा घाटे की भरपाई

झारखंड के लिए अभिशाप बन रही खनिज संपदा

राज्य ब्यूरो, रांची : सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष जो रिपोर्ट पेश की है उसमें यह माना गया है कि राज्य के लिए खनिज संपदा धीरे-धीरे अभिशाप साबित होते जा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि की रिपोर्टों का हवाला देते हुए यह जानकारी दी गई कि किस प्रकार लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचने का अनुमान है और इससे जूझने के लिए सरकार को बड़े पैमाने पर राशि खर्च करनी होगी।

प्रदेश में कोयला और बॉक्साइट के खनन में पिछले दो वर्षों में बढ़त हुई है जबकि आयरन ओर से उत्पादकता मामूली तौर पर कुछ कम हुई है। इसके बावजूद यह सेक्टर रोजगार के लिहाज से कमजोर ही माना जाएगा। पूरे कार्यबल के हिसाब से महज 2.3 फीसद खनन क्षेत्र में कार्यरत हैं। सरकार का मानना है कि खनन से इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है। इसके अलावा जल, मिट्टी और वायु प्रदूषण का खतरा बना रहता है। सरकार ने इस कारण से खनिज संपदा पर रॉयल्टी बढ़ाकर 20 फीसद करने की मांग की है जो फिलहाल 14-15 प्रतिशत के आसपास है। यह भी बताया कि कोयला पर रॉयल्टी दर में बदलाव 2012 के बाद नहीं हुआ है।

आज जमशेदपुर जाएगी वित्त आयोग की टीम : वित्त आयोग की टीम शुक्रवार को जमशेदपुर जाएगी। टीम के अध्यक्ष और अन्य सदस्य एक्सएलआरआइ में उद्योग एवं व्यवसाय जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगी। बैठक के बाद टीम दिल्ली लौट जाएगी।

> खनन से इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र को व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचता है
>
>
>
> - विश्व बैंक ने अनुमान लगाया है कि वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी के कारण 3 बिलियन डॉलर राशि 50 शहरों के लगभग 11 करोड़ लोगों पर खर्च होगी। इनमें से कई शहर झारखंड में हैं।
> - विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2012 में 1.26 करोड़ लोग पूरे विश्व में प्रदूषित वातावरण के कारण काल के गाल में समा गए।
> - 2015 में मरनेवाले लोगों में से 16 फीसद की मौत प्रदूषण से हुई बीमारियों के कारण असमय हुई।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

वित्त आयोग रांची में : खनिज संपन्न प्रदेश होने का खामियाजा भुगत रहा झारखंड

झारखंड ने मांगे 1.50 लाख करोड़

राज्य ब्यूरो, रांची : झारखंड सरकार ने राज्य के विकास और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 15 वें वित्त आयोग से 1.50 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है। गुरुवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में राज्य सरकार की टीम ने वित्त आयोग के समक्ष अपनी प्रस्तुति में इन मांगों को तार्किक ढंग से उठाया और इस बाबत मेमोरंडम सौंपा। वित्त आयोग के अध्यक्ष एके सिंह राज्य सरकार द्वारा उठाई गई मांगों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने का भरोसा दिलाया। बता दें कि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर ही राज्यों को वर्ष 2020-25 के लिए राशि जारी की जाएगी।

राज्य सरकार ने आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ कृषि, वन एवं पर्यावरण, सिंचाई, पेयजल, स्वास्थ्य, स्कूली एवं उच्च शिक्षा, महिला विकास और राजस्व एवं सामान्य प्रशासन के ढांचे को सुधारने के लिए इन अनुदान मांगों को जरूरी बताया। राज्य सरकार की ओर वित्त आयोग को सौंपे गए मेमोरंडम में इन तमाम सेक्टर से जुड़ी बातों का विस्तार से जिक्र किया गया। यहां की माइनिंग से दूसरे राज्यों को हो रहे फायदे और झारखंड को हो रही परेशानियों का जिक्र भी किया। बताया गया कि झारखंड के लिए खनिज संपन्न प्रदेश होना ही अभिशाप हो गया है। जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए बड़ी आर्थिक मदद चाहिए। 26.21 फीसद आदिवासी और 36.51 प्रतिशत बीपीएल आबादी के विकास के लिए बड़ी राशि का तर्क दिया गया। गत वित्तीय वर्ष से प्रभावी हुई नई कर व्यवस्था जीएसटी से हो रहे नुकसान का भी जिक्र किया गया और इसकी भरपाई का मामला भी उठाया गया। बता दें कि 14 वें वित्त आयोग से राज्य सरकार ने 1.42 लाख करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की थी। बैठक में वित्त आयोग के चेयरमैन एनके सिंह, खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी, शिक्षा मंत्री नीरा यादव, श्रम मंत्री राज पलिवार, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डीके तिवारी, वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, आयोग के सदस्य शक्तिकांत दास, डॉ रमेश चंद्र, डॉ अनूप सिंह आदि मौजूद थे।

संबंधित सामग्री >>पेज 09

15 वें वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में सरकार ने रखी मांग

- आधारभूत संरचना, सामाजिक और कृषि क्षेत्र के विकास का दिया हवाला

इन क्षेत्रों के लिए रखी गई अनुदान की मांग

क्षेत्र	राशि (करोड़ रुपये में)
कृषि, वानिकी व पेयजल	42,598.02
सामाजिक सेक्टर	17,001.39
आधारभूत संरचना	88,199.66
राजस्व व सामान्य प्रशासन	2,203.66
कुल	1,50,002.73

झारखंड के 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य के निर्माण के 14 वर्ष बाद भी हमारे यहां विधानसभा, हाईकोर्ट समेत अन्य भवन नहीं थे। सरकार ने इन्हें बनाने का बीड़ा उठाया है। इसी तरह न्यू कैपिटल का निर्माण भी किया जा रहा है। इन सभी चीजों के लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा कर हम झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे।

रघुवर दास, मुख्यमंत्री, झारखंड

झारखंड को माइनिंग स्टेट होने का जितना लाभ मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है। पर्यावरण पर भी समुचित ध्यान देना होगा। यहां की 27% आबादी आदिवासियों की है। राज्य के पास प्रचुर खनिज संसाधन हैं। इस लिहाज से झारखंड के समक्ष कई चुनौतियां हैं।

एनके सिंह, अध्यक्ष, 15वां वित्त आयोग

राज्य सरकार के तर्क और वित्त आयोग से मांगें

- केंद्रीय करों में राज्य की भागीदारी को 42 फीसद से बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया जाए।
- अनुदान का आधार परफार्मेंस को न बनाया जाए।
- माइनिंग की रायल्टी दर को 14-15 फीसद से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया जाए।
- 2012 से कोयले की रायल्टी रिवाइज्ड नहीं की गई।
- झारखंड में बीपीएल आबादी 36.51 प्रतिशत जबकि राष्ट्रीय औसत 21.92 प्रतिशत का।
- झारखंड में जनजातीय आबादी 26 फीस से ज्यादा, इनके विकास के लिए चाहिए राशि।

प्राकृतिक आपदा में शामिल हो हाथियों से क्षति व खान दुर्घटना

रांची : राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग से वज्रपात, खान दुर्घटना तथा हाथियों से नुकसान को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की मांग की है। सरकार की ओर से कहा गया है कि भौगोलिक कारणों से झारखंड में इस तरह की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान हो रहा है। राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के तहत आपदा से निपटने के लिए फंड से मिलनेवाले वार्षिक अनुदान की राशि दस फीसद से बढ़ाकर बीस फीसद करने की भी मांग की है।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉंची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

दैनिक जागरण
शुक्रवार, 3 अगस्त 2018 : श्रावण कृष्ण 6, वि. 2075
इच्छा के वेग में विराम से ही संतोष धन प्राप्त हो सकता है

पिछड़े राज्य विक...

15वें वित्त आयोग की टीम से बोले मु...

...दिया जाए

राज्य ब्यूरो, रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 15 वें वित्त आयोग से झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया है। गुरुवार को वित्त आयोग की टीम के साथ बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में विकास के कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत पर जोर दिया। स्पष्ट कहा कि जब तक पिछड़े राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक भारत भी पूरी तरह से विकसित नहीं होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड की जनता की अपेक्षाओं और जरूरत को पूरा करने के लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। कहा, 2014 में राज्य में स्थिर सरकार के गठन के बाद विकास कार्यों ने गति पकड़ी। आज मूलभूत जरूरतों के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत का सपना भी यही है कि सारे राज्य विकसित हों। उन्होंने कहा कि हमारे 24 में से 19 जिले आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल हैं। राज्य निर्माण के 14 वर्षों के बाद भी हमारे यहां विधान सभा, हाईकोर्ट समेत अन्य प्रमुख भवन नहीं थे। हमारी सरकार ने इन्हें बनवाने का बीड़ा उठाया, ये 2019 तक बन कर तैयार हो जायेंगे। इसी तरह हम न्यू कैपिटल का निर्माण भी करा रहे हैं। इन सबके लिए हमें काफी राशि की जरूरत है। इन जरूरतों को पूरा कर हम झारखंड को विकसित राज्यों की श्रेणी में ला सकेंगे।

24 में से 19 आकांक्षी जि... की सूची में शामिल

15 अगस्त तक 6512 गांवों तक इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य

... विकास की काफी संभावना

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पर्यटन की काफी संभावनाएं हैं। यहां विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन के विकास से बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। इसके साथ ही विदेशी करेंसी भी आएगी।

सीएम ने कहा, लोगों की अपेक्षाओं और जरूरत को पूरा करने के लिए काफी राशि की आवश्यकता

रांची में 15वें वित्त आयोग की बैठक के दौरान मेमोरेंडम जारी करते वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह व सीएम रघुवर दास, साथ हैं मंत्री सरयू राय, रामचंद्र चंद्रवंशी, नीरा यादव व अन्य ● जागरण

आदिवासियों के जीवन में बदलाव लाना हमारा फर्ज

मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज का विशेष तौर पर जिक्र करते हुए कहा कि आजादी की लड़ाई हो या अलग राज्य का आंदोलन, हमारे आदिवासी भाईयों ने अपना खून-पसीना बहाया है। अब हमारा फर्ज है कि उनके जीवन में बदलाव आए। गांव-गांव तक अच्छी सड़क, बिजली और शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम किया जा रहा है। सीएम ने केंद्र सरकार की सात फ्लैगशिप योजनाओं के तहत किए जा रहे कार्यों का भी जिक्र किया। कहा, ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।

सिंचाई की व्यवस्था नहीं, खनन क्षेत्र में दूषित पानी पीने को मजबूर हैं लोग

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती का कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है। खनन क्षेत्रों में लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। वे कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इससे बचाव के लिए हम लोगों तक पाइप लाइन के माध्यम से शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए हमने डिस्ट्रीक माइनिंग फंड में आई राशि का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

'झारखंड को मिले विशेष राज्य का दर्जा'

राजनीतिक दलों ने जीएसटी से होनेवाले घाटे की भरपाई पर उठाए सवाल

राब्यू, रांची : 15वें वित्त आयोग की टीम ने गुरुवार को राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक की। इसमें अधिसंख्य राजनीतिक दलों ने झारखंड के पिछड़े होने का हवाला देते हुए विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की। इसके लिए सभी मानक पूरा करने की बात कही। यह भी कहा कि यहां के खनिज से देश का विकास हो रहा है, उस अनुपात में केंद्र से राज्य को अनुदान नहीं मिल रहा। इससे न केवल यहां के किसान-गरीब विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं, बल्कि विकास से भी वंचित हैं।

राजनीतिक दलों ने खनिज उत्खनन व परिवहन से प्रदूषण का स्तर बढ़ने तथा इससे गरीबों के कई बीमारियों से ग्रस्त होने का मामला भी उठाया। भाकपा के भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि झारखंड में सबसे अधिक खनिज होते हुए भी यहां के लोग पलायन कर रहे हैं। हजारों गांवों के आदिवासी नाले का पानी पीने को मजबूर हैं। वित्त आयोग इन सभी को ध्यान में रखकर राज्य को अनुदान दे। उन्होंने सवाल उठाया कि जीएसटी से प्रतिवर्ष 2500 करोड़ होनेवाले नुकसान की भरपाई 2022 तक केंद्र सरकार तो कर देगी, लेकिन इसके बाद क्या होगा यह स्पष्ट नहीं है। झामुमो ने भी इस मसले को उठाया। प्रदेश राजद ने भी विशेष राज्य का दर्जा तथा केंद्रीय करों में झारखंड को 50 फीसद हिस्सेदारी की मांग की। झाविमो के महासचिव प्रदीप यादव ने वित्त आयोग से राज्य के खनन क्षेत्रफल को भी शेयर ऑफ टैक्सेज के फैक्टर से जोड़ने की मांग की। कहा, खनिज रायल्टी ही नहीं, कंपनियों के मुनाफे में भी राज्य की हिस्सेदारी हो।

रांची में 15वें वित्त आयोग की बैठक में शामिल नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदीप यादव व अन्य ● जागरण

राजनीतिक अस्थिरता के कारण नहीं हुआ विकास : भाजपा

भाजपा के प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश व प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा ने कहा कि राज्य में 2014 तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण विकास अपेक्षाकृत विकास नहीं हुआ। इसके बाद राजनीतिक स्थिरता आने से विकास में तेजी आई। पार्टी ने वन संरक्षण कानूनों के प्रावधानों के सरलीकरण करने का सुझाव दिया। आदिवासी बहुल राज्य होने तथा खनिज उद्योगों के कारण विस्थापन होने का हवाला देते के कारण सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन राज्य को उपलब्ध कराने तथा लंबित सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आर्थिक सहयोग की मांग की। इसके अलावा पर्यटन, रेल संरचनाओं के विकास, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए भी आर्थिक सहायता की मांग की।

न्यू इंडिया-2022 भाजपा का राजनीतिक नारा : हेमंत

झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने वित्त आयोग के टर्म्स ऑफ रिफरेंसेज (टीओआर) में न्यू इंडिया-2022 का उल्लेख होने पर सवाल उठाया। कहा, यह भाजपा का राजनीतिक नारा है। इसके लिए धन आवंटित करना वित्त आयोग का काम नहीं है। उन्होंने वित्त आयोग द्वारा कुल प्रजनन दर कम करने, कुपोषण कम करने आदि मानकों पर केंद्रीय राजस्व अधिक देने पर सवाल उठाया कहा कि जिन राज्यों में अधिक गरीबी है वहां ही इनकी दर अधिक है। हेमंत के अनुसार, केंद्र ने वित्त आयोग की सीमाएं बांधने का काम किया है।

सबसे अधिक राजस्व झारखंड से लेकिन सुविधाएं नगण्य : आजसू

आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत ने वित्त आयोग से कहा कि रेलवे को सबसे अधिक रेवेन्यू झारखंड से मिलता है, लेकिन इस अनुपात में न तो यहां रेल की सेवा मिल रही है न ही यात्रियों को सुविधाएं। पार्टी ने दक्षिणी-पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता के बदले झारखंड में बनाने की अनुशंसा करने की मांग की। पार्टी ने पंचायती राज संस्थाओं व शहरी निकायों के अनुदान की राशि बढ़ाने की भी मांग की।

पांच में चार मापदंड राज्य के पक्ष में : कांग्रेस

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने वित्त आयोग से झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। कहा, पांच निर्धारित मापदंडों में से चार पर राज्य सटीक तौर पर बैठता है। कहा, झारखंड में कॉरपोरेट घरानों टांटा, सेल, बीसीसीएल आदि के कारण प्रति व्यक्ति आय बढ़ी हुई दिखती है लेकिन वास्तविकता यह है कि जहां देश में 38 फीसद आबादी गरीबी रेखा के नीचे बसर करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में झारखंड की स्थिति बहुत खराब है। आदिवासियों की संख्या घटती जा रही है। कृषि पर निर्भरता अधिक होने के कारण कांग्रेस ने लिफ्ट इरिगेशन में अधिक से अधिक राशि देने की मांग की है। राज्य में विस्थापित आयोग के गठन और इसके लिए आर्थिक प्रबंध की भी मांग की गई है।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

झारखंड में चुनौतियां ज्यादा, वित्तीय अनुशासन जरूरी : एनके सिंह

राज्य ब्यूरो, रांची : वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने स्वीकारा है कि झारखंड काफी चुनौतियों से जूझ रहा है। उन्होंने इन चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य सरकार को वित्तीय अनुशासन बरकरार रखने की नसीहत दी है। गुरुवार को मीडिया से बातचीत में एनके सिंह ने यह बातें कहीं।

सिंह ने कहा कि पिछले दो दिनों में नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों, सरकार और अन्य राजनीतिक दलों के साथ सार्थक मसलों पर चर्चा हुई है। आयोग बातचीत में आए सुझावों पर गंभीरता से विचार करेगा। एनके सिंह ने कहा कि पिछले तीन साल में राजकोषीय घाटा निर्धारित मानक को पार कर गया है। हालांकि ऐसा उदय बांड के कारण हुआ। उदय योजना के तहत राज्य को बिजली के क्षेत्र में घाटा शून्य करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। राज्य सरकार अभी भी रिसोर्स गैप के मद में बिजली क्षेत्र पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही है। जबकि घाटा खत्म करने के लिए बिजली के संचरण-वितरण घाटे पर काबू पाना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को बैलेंस ग्रोथ पर फोकस करना होगा। स्वीकारा कि झारखंड को माइनिंग स्टेट होने का जितना लाभ मिलना चाहिए था वह लाभ नहीं मिल पा रहा है। राज्य को पर्यावरण पर भी जितना ध्यान देना चाहिए वह भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड को एक यूनिक स्टेट बताते हुए उन्होंने कहा कि यहां की 27 फीसद आबादी आदिवासियों की है। राज्य के पास प्रचुर खनिज संसाधन हैं, कोयला इत्यादि है। इस लिहाज से यह एक बड़ी चुनौती भी है कि पारिस्थितिकी तंत्र, पर्यावरण और आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर ध्यान रखना होगा। कहा, राज्य सरकार ने विस्तृत प्रतिवेदन सौंपकर आग्रह किया है कि भार बढ़ाया जाए। उन्होंने विशेष तौर पर सेंट्रल शेयर को 42 फीसद से बढ़ाकर 50 फीसद करने की राज्य सरकार की मांग की चर्चा करते हुए स्वीकारा कि पूर्व की अपेक्षा इसमें परिवर्तन की भी आवश्यकता है। उन्होंने 14 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर किसी भी तरह की टिप्पणी से इन्कार किया। राज्य सरकार द्वारा खर्च की जाने वाली बजट की राशि के सवाल पर कहा कि राज्यों को केंद्र से मिलने वाली राशि का सदुपयोग करना चाहिए। जीएसटी से होने वाले नुकसान पर कहा कि अभी आयोग ने इसका विश्लेषण नहीं किया है। इसलिए किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचाना जल्दबाजी होगी।

पत्रकार वार्ता में जानकारी देते एनके सिंह ● जागरण

- बोले आयोग के अध्यक्ष झारखंड में सरकार व अन्य दलों के साथ सार्थक विमर्श हुआ
- कहा, राज्य सरकार रिसोर्स गैप के मद में बिजली क्षेत्र पर बहुत ज्यादा खर्च कर रही
- स्वीकारा, झारखंड को माइनिंग स्टेट होने का जितना लाभ मिलना चाहिए वह नहीं मिला

राज्य सरकार ने नहीं की विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग

झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर एनके सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने अपने प्रतिवेदन में इस तरह की कोई डिमांड नहीं की है। हां, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधिमंडल ने इसकी चर्चा अवश्य की थी। स्पष्ट किया कि आयोग विशेष राज्य का दर्जा देने की सिफारिश नहीं करता।

पटना दौरा रद होने का कोई राजनीतिक कारण नहीं

एनके सिंह ने कहा कि पटना दौरा रद करने के पीछे कोई राजनीतिक वजह कतई नहीं है। दौरे के वक्त मुख्यमंत्री से चर्चा होती इसलिए उनका समय नहीं मिल पाने के कारण ऐसा हुआ। राज्य सरकार और वित्त आयोग की तरफ से पूरी तैयारी थी। वित्त आयोग ने अब तक सात राज्यों का दौरा किया है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - दैनिक जागरण
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - राँची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

आर्थिक संरक्षण व वाजिब हिस्सेदारी मिले

राब्यू, रांची : राज्यसभा सदस्य महेश पोद्दार ने 15वें वित्त आयोग को पत्र लिखकर झारखंड को अधिकाधिक आर्थिक संरक्षण और वाजिब हिस्सेदारी देने की मांग की है। पत्र में पोद्दार ने आवंटन की अबतक की प्रणाली में व्याप्त विसंगतियों का जिक्र किया है और वैज्ञानिक व नीड बेस्ड आवंटन पद्धति अपनाने का सुझाव दिया है।

उन्होंने कहा कि वैसे खनिजों के उत्पादन को जिनका मूल्यवर्धन करनेवाले कारखाने अन्य राज्यों में हैं, राज्य की जीडीपी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। खनिजों के उत्पादन को राज्य की जीडीपी में तभी जोड़ा जाए जब उनका मूल्यवर्धन और इस्तेमाल राज्य में ही हो रहा हो। इससे आर्थिक लाभ किसी अन्य राज्य को मिल रहा है, झारखंड को केवल रॉयल्टी मिल रही है। पोद्दार ने कहा

कि खदानों की नीलामी से राज्य को प्राप्त राजस्व नकद के साथ-साथ जनसेवाओं के रूप में भी हो। उन्होंने कहा कि दामोदर घाटी निगम का मुख्यालय राज्य में नहीं होने की वजह से झारखंड अर्जित राजस्व के एक बड़े हिस्से से वंचित हो जाता है। शहरी विकास योजनाओं के लिए निर्गत राशि राज्य सरकार को भेजे जाने की बजाय सीधे संबंधित नगर निकायों को भेजी जानी चाहिए। अगर वित्त आयोग का समर्थन मिले तो राज्य सरकार अनाजों की तरह ही सब्जियों के लिए भी उत्पादन लागत का डेढ़ गुणा न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर सब्जियां खरीद सकती है और वेजफेड के माध्यम से उसका विपणन कर सकती है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - दैनिक भास्कर
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

15 वें वित्त आयोग ने झारखंड के डिमांड मेमोरंडम और प्रेजेंटेशन की प्रशंसा की, कहा सबसे बेहतर झारखंड का

राज्य सरकार ने कोर कैपिटल सिटी के लिए मांगा 5000 करोड़ रु. का अनुदान

झारखंड ने कोयला सेस पर उठाया सवाल- कोल बेयरिंग राज्यों को मिलनेवाला का 38500 करोड़ दूसरे राज्यों को जीएसटी कंपेन्शेसन में दिया गया

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

राज्य सरकार ने 15 वें वित्त आयोग से झारखंड के हितों की रक्षा के लिए राशि देने का फार्मूला बनाने के साथ साथ अनुदान देने पर जोर दिया। राज्य सरकार ने वर्ष 2020 से 2025 के दौरान 1,50,002 करोड़ रुपए बतौर अनुदान की मांग की । कोर कैपिटल सिटी के लिए 5000 करोड़ रुपए का मांग पत्र दिया है। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर के लिए अनुदान को आधार बनाया है। कहा कि राज्य के विकास के लिए यह जरूरी है। आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने सवाल उठाया कि राज्य बनने के 18 साल बाद ये मांग क्यों हुई है। 13 वे और 14 वें वित्त आयोग के समक्ष ये मांग क्यों नहीं रखी गई। सीएम ने कहा कि पहले स्थाई सरकार नहीं थी। वर्ष 2014 में स्थाई सरकार बनी है। विकास का काम हो रहा है। इसलिए ये मांग की गई है। होटल रेडिशन ब्लू में आयोजित बैठक में अपर मुख्य सचिव (योजना व वित्त) सुखदेव सिंह ने राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए मेमोरंडम की उल्लेख करते हुए जीएसटी से हो रहे नुकसान का ब्योरा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक ही केंद्र सरकार जीएसटी से हो रहे हानि की भरपाई करेगा। आगे भी बड़ी हानि की स्थिति है। इसलिए 15 वें वित्त आयोग वर्ष 2022 के बाद भी केंद्र द्वारा जीएसटी की भरपाई करने की अनुशंसा करे। उन्होंने कोल सेस पर झारखंड और अन्य कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों का हक जताया ।

उन्होंने आयोग बताया कि वर्ष 2010-11 से 2016-17 के बीच 54 हजार करोड़ कोल शेष क्लीन इनर्जी के लिए वसूला गया। इसमें से कोयला उत्पादन करनेवाले राज्यों को 15,500 करोड़ ही मिले। 38,500 करोड जो बचे उसे जीएसटी कंपेन्शेसन के रूप में देश भर के राज्यों को बांट दिया गया। मंत्री सरयू राय ने कहा कि जीएसटी के कारण हो रहे नुकसान पर भी 15 वें वित्त आयोग को गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि झारखंड आदिवासी बाहुल्य राज्य है। इसलिए झारखंड के लिए जीडीपी को आधार नहीं बनाना चाहिए।

कोर कैपिटल में विधानसभा और हाईकोर्ट भवन के लिए मुख्यमंत्री ने आयोग से मांगी राशि

वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को मेमोरेंडम देते मुख्यमंत्री रघुवर दास। साथ में सरयू राय, नीरा यादव, चंद्रवंशी व अन्य।

किस सेक्टर में कितना डिमांड (करोड़ रुपए)

विभाग	डिमांड		
कृषि	3447	सड़क	22208
वन एवं पर्यावरण	4011	ग्रामीण पथ	16094
सिंचाई	30000	परिवहन	4217
पेयजल	5140.02	शहरी विकास	20899.66
स्वास्थ्य	10345.44	ऊर्जा	4835
न्यूट्रीशन	475	उद्योग	11500
महिला एवं शिशु विकास	428	टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर	546
स्कूली शिक्षा	1237.95	गृह सुरक्षा	545.25
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	4515	भू-राजस्व प्रबंधन	516
प्लानिंग, डिजाइन ऑफ		पंचायती राज	937.66
कोर कैपिटल सिटी	5000	आईटी	34.75
बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन	2900	वाणिज्यकर प्रबंधन	170
		कुल	150002.73

झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, बहुत काम बाकी : रघुवर

15 वें वित्त आयोग की टीम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2014 में राज्य में स्थिर सरकार आने के बाद से विकास कार्यों ने गति पकड़ी। राज्य के विकास के लिए सामर्थ्य, संसाधन और संयोग आज तीनों चीजें हैं। प्राकृतिक संसाधन हो या मानव बल झारखंड एक समृद्ध राज्य है। लेकिन लोग अभाव की जिंदगी जीने को मजबूर थे। विकास कार्य हुए हैं, लेकिन पिछड़ा राज्य होने के कारण अभी भी यहां काफी कुछ किया जाना बाकी है। झारखंड जैसे राज्यों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी राशि की जरूरत है। वित्त आयोग को अविकसित राज्यों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की सात फ्लैग शीप योजनाओं को लाभुकों तक पहुंचाया जा रहा है। ग्राम स्वराज अभियान के दूसरे चरण में राज्य के 6512 गांवों तक इन योजनाओं का लाभ 15 अगस्त तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा राज्य के 1000 से ज्यादा अनुसूचित जनजाति की आबादी वाले 3312 गांवों तक भी इन योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि कृषि में सबसे ज्यादा रोजगार है, लेकिन हमारे यहां सिंचाई की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण खेती कार्य पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है।

विशेष पैकेज वित्त आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं : एनके सिंह

रांची| 15 वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने राज्य सरकार ने स्पेशल पैकेज की मांग नहीं की है। राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की है। लेकिन स्पेशल पैकेज पर विचार करना आयोग के क्षेत्राधिकार में नहीं है। हां उन्होंने यह जरूर स्वीकार किया कि कल लोकल और अर्बन बॉडी के जनप्रतिनिधियों द्वारा सौंपा गया ज्वाइंट रिप्रजेंटेंशन सराहनीय है। इस तरह का रिप्रजेंटेंशन किसी दूसरे राज्य ने नहीं दिया। उसमें यह गया है कि 14 वें वित्त आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत ऊपर और नीचे की इकाइयों पर ध्यान दिया, लेकिन मध्य क्रम में आनेवाले जिला परिषदों पर ध्यान नहीं दिया। जिला परिषदों के मामले में यह आयोग जरूर ध्यान देगा। वह गुरुवार को कतिपय बैठकों के बाद संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। बिहार नहीं जाने के सवाल पर सिंह ने कहा कि इसके पीछे कोई राजनीतिक कारण नहीं है। मुख्यमंत्री अस्वस्थ थे। आयोग को 29 राज्यों का दौरा करना है, अभी तो सात ही राज्यों का दौरा हुआ है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – दैनिक भास्कर
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – राँची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

भास्कर खास | **15वें वित्त आयोग ने मुख्यमंत्री, राज्य के आला अफसरों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की**

सरकार : माइनिंग का लाभ देश को, नुकसान झारखंड को ही क्यों | वित्त आयोग : हम पैसों के बंटवारे में इसका ध्यान रखेंगे

पॉलिटिकल रिपोर्टर | रांची

राज्य सरकार ने 15वें वित्त आयोग के सामने सवाल उठाया कि झारखंड की माइनिंग का लाभ पूरा देश उठा रहा है। जबकि नुकसान केवल झारखंड को सहना पड़ रहा है। खेत-खलिहान, सड़क और पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। हम लाल, पीला और काला पानी पी रहे हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस के चक्कर में योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही हैं। इसलिए जीएसडीपी में माइनिंग शेयर को शामिल करते हुए फॉर्मूला तैयार किया जाना चाहिए।

इस पर आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह ने कहा कि पहले केंद्रीय करों से प्राप्त राशि के बंटवारे में विकास को केंद्र में रखा गया था। पर्यावरण प्रबंधन पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब आयोग झारखंड को पर्यावरण से हो रहे नुकसान, वन क्षेत्र और आदिवासी बहुल राज्य होने के कारण यहां की यूनिक समस्याओं को देखते हुए फॉर्मूला बनाएगा। पैसों के बंटवारे में इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह जरूर कह सकते हैं कि -राज्य को जितना लाभ मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। गुरुवार को मुख्यमंत्री, राज्य के आला अधिकारियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद अध्यक्ष पत्रकारों से बात कर रहे थे।

झारखंड ने मांगे 1.5 लाख करोड़

राज्य सरकार ने आयोग से 1.5 लाख करोड़ रुपए की मांग की। सरकार ने कहा कि दक्षिण के राज्यों की तरह 1971 की जनगणना के आधार पर राशि के वितरण की जगह 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाना चाहिए। केंद्र ने जीएसडीपी के विरुद्ध 60 फीसदी ऋण लेने का फैसला लिया है। इसमें 40 फीसदी केंद्र ही ऋण लेता है। राज्यों के हिस्से 20 फीसदी ही बचता है। यह आंकड़ा 30:30 करना चाहिए। करों में राज्यों के शेयर को 42% से बढ़ाकर 50% की जानी चाहिए।

झारखंड में शिक्षा व प्रति व्यक्ति आय में सुधार

आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वितीय वर्ष 2010-11 में जो वितीय घाटा था, उसमें सुधार नहीं आया है। इसके पीछे उदय योजना के तहत लिया गया ऋण प्रमुख कारक है। राज्य बनने से पूर्व झारखंड की इकोनॉमी का रियलाइजेशन नहीं हो पाया। यहां गरीबी 27% है। हालांकि ह्यूमन रिसोर्स, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय में सुधार हुआ है। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का भी लाभ मिला है।

राज्य सरकार ने कोर कैपिटल सिटी के लिए मांगा 5000 करोड़ का अनुदान | पेज 4

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन,
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, रॉंची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आज
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

15वें वित्त आयोग से डेढ़ लाख करोड़ रुपये ग्रांट की मांग

झारखंड सरकार की ओर से आयोग को सौंपा गया विस्तृत प्रतिवेदन

रांची। पंद्रहवें वित्त आयोग से झारखंड सरकार ने लगभग डेढ़ लाख करोड़ रुपये के ग्रांट की मांग की है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आज रांची में इससे संबंधित एक मेमोरेंडम वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह को सौंपा। एन.के. सिंह आयोग के सदस्यों के साथ झारखंड के तीन दिवसीय दौरे पर हैं।

मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जो मेमोरेंडम आयोग को सौंपा है उसमें चौदहवें वित्त आयोग के कई बिंदुओं पर बदलाव करने का सुझाव दिया है ताकि झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों को फायदा हो। झारखंड सरकार की ओर से 42598करोड़ रुपये का ग्रांट कृषि, वनिकी व सिंचाई के लिए मांगी गयी है, जिसमें से 3447 करोड़ रुपये कृषि, 4011 वन एवं पर्यावरण, 30000 सिंचाई और 5140करोड़ रुपये पेयजल के लिए उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। वहीं सामाजिक क्षेत्र के विकास के लिए 17001 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मांग की गयी, इस राशि से 10345करोड़ रुपये स्वास्थ्य और 1237 करोड़ रुपये महिला एवं बाल विकास पर खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

राज्य सरकार की ओर सेआधारभूत संरचना के विकास के लिए सबसे अधिक 88199करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है, इनमें कोर कैपिटल एरिया के प्लानिंग व डिजाइन के लिए 5000करोड़, भवन निर्माण के लिए 2900करोड़, सड़क के लिए 22208करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 16094करोड़, परिवहन के लिए 4217करोड़, नगरीय विकास के लिए 20899करोड़, उर्जा के लिए 4835करोड़, उद्योग के लिए 11500करोड़, पर्यटन विकास के लिए 546करोड़ रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा राजस्व व सामान्य प्रशासन के लिए 2203 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की मांग की गयी है, जिसमें सुरक्षा पर 545करोड़, भूमि एवं राजस्व प्रशासन के लिए 516करोड़,पंचायती राज के लिए 937 करोड़, आईटी के लिए 34.74करोड़ और वाणिज्य कर प्राशासन के लिए 170 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। वित्त आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि झारखंड सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिवेदन आयोग के समक्ष बेहतरीन तरीके से रखा गया। उन्होंने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों, शहरी निकायों, जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार की तरफ से रखे गए बिंदुओं पर आयोग सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा।

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची

***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी,रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आज
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.02.18
4. प्रकाशन शहर – रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

कांग्रेस ने 15वें वित्त आयोग से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की

रांची। प्रदेश कांग्रेस ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह को ज्ञापन सौंप कर झारखंड को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। वित्त आयोग की बैठक में भाग लेने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. अजय कुमार ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े भ्रामक हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा अलग–अलग होने से राज्य की स्थिति का पता चल जायेगा।

उन्होंने बताया कि संदर्भ के शर्तों से ज्ञात हुआ है कि आयोग को यह समीक्षा करना है कि राज्यों को दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान चालू रखा जाए या अब बन्द कर दिया जाए। पार्टी की ओर सेक हा गया कि पिछले (14वें) वित्त आयोग द्वारा राज्यों को मिलने वाली टैक्स हिस्सेदारी में की गयी भारी बढ़ोत्तरी (32प्रतिशत से 42प्रतिशत) की भी समीक्षा करेगा। इस संदर्भ की इस शर्त से भी यह आशंका जन्म लेती है कि कहीं राज्यों को दिये गये हिस्सेदारी के प्रतिशत में कटौती न कर दी जाए। अगर कटौती की जाती है तो यह संघीयसहकार की भावना को आहत करेगा और राज्यों की नीतिनिर्धारण की स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा, क्योंकि कर हस्तांतरण से राज्यों को मिलने वाली राशि सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुरुप खर्च करने के लिए स्वतंत्र होती है। उन्होंने कहा कि चौथी चिंताजनक और सर्वाधिक कोलाहलपूर्ण संदर्भ की शर्त यह है जिसमें कहा गया है कि राजस्व हिस्सेदारी तय करने में आयोग 2011 की जनगणना को आधार वर्ष मानेगा। जबकि इसके पहले तक 1971 की जनगणना को आधार वर्ष माना जाता रहा है। सिर्फ 14वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना को आशिंक महत्व (10 प्रतिशत का भारांक) दिया था। उन्होंने कहा कि विशेष राज्य के दर्जा की मांग लंबे समय से चली आ रही है और यह हमारा अधिकार है क्योंकि देश के खनिज संपदा की हिस्सेदारी 40प्रतिशत हमारी है। इस देश की विकास में सबसे बड़ा योगदान झारखंड का रहा है। इसलिए झारखंड को उसक हक मिलना ही चाहिए। खनिज संपदा हमारे लिए वरदान है तो उसका अभिषाप भी झारखंडियों को विस्थापन एवं पलायन के रुप में झेलना पड़ता है।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉंची

***

दूरभाप :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉंची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - आज
2. समाचार पत्र की भाषा - हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - रॉंची
5. प्रकाशन की अवधि - दैनिक

भाजपा ने वित्त आयोग का ध्यान सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा की ओर कराया

रांची। झारखंड दौरे पर आये 15 वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष एन के सिंह से भाजपा की ओर से प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप वर्मा व प्रदेश महामंत्री दीपक प्रकाश ने मुलाकात की और उनका सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य,चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास में सहयोग के साथ-साथ 11 बिन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ठ कराया। भाजपा ने वित्त आयोग के अध्यक्ष को इस बात से अवगत कराया कि वर्ष 2000 में राज्य गठन के बाद वर्ष 2014 तक राज्य में 9 सरकारें आयी और 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। राजनीति अस्थिरता के कारण राज्य की प्रगति अपेक्षाकृत कम हुई। वर्ष 2014 से राजनीतिक स्थिरता आयी है और हमारी प्रगति तेज हुई है। इसमें वित्त आयोग से सहयोग की जरूरत है ताकि राज्य का और तेजी से विकास हो सके। भाजपा की ओर कहा गया कि राज्य में 30 प्रतिशत से अधिक वन भूमि है और देश के पर्यावरण संतुलन में राज्य की महती भूमिका है। वित्त आयोग से राज्य में वन संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को सरल करते हुए विकास कार्यो हेतु भूमि की उपलब्धता पर समुचित ध्यान देने का आग्रह किया गया। इस क्रम में कहा गया कि राज्य में 27 प्रतिशत अनुस. चित, जनजातियों की है, जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर करना आवश्यक है। वित्त आयोग को राज्य की इस विशेष स्थिति पर ध्यान देते हुए सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त संसाधन राज्य को उपलब्ध कराने के संबंध में निर्णय लेना चाहिए। राज्य प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण है तथा यहां के खनिज का उपयोग पूरा करता है। खनिज की उपलब्धता के आधार पर यहां वृहत उधोग एवं खनन कंपनियों कार्यरत है, परंतु ये कंपनियां यहां की आधारभूत संरचना पर अत्यधिक दवाब तो डालती ही है, साथ ही जल, जंगल एवं जमीन का विस्थापन भी करती है। केन्द्र सरकार को पुनर्वास के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए। कोयला , लोहा एवं अन्य खनिज के उत्खनन एवं परिवहन के कारण प्रदूषण का स्तर बहुत उंचा है, जिससे गरीब लोगों को तरह-तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इन कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी सीमित है। इन सभी के कारण वहां की जनता गरीब एवं कठिन जीवन जीने को मजबूर है। वित्त आयोग का आम जनता के प्रति अधिक जवाबदेही निभाने की जरूरत है ताकि उनका जीवन स्तर सुधारा जा सके। राज्य के 24 में से 19 जिला उग्रवाद प्रभावित है। गत वर्ष उग्रवादी घटनाओं को काफी नियंत्रित भी किया गया है। परंतु राज्य की पुलिस प्रशासन की और चुस्त -दुरूस्त तथा तकनीशियन रूप से सक्षम एवं साधन संपन्न बनाने के लिए भी संसाधन की आवश. कता है।

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – आज़
2. समाचार पत्र की भाषा – हिन्दी
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – रॉची
5. प्रकाशन की अवधि – दैनिक

कुछ अच्छे काम हुए, पर झारखंड की कुछ यूनिक समस्या : एनके सिंह

कई चुनौतियां, आदिवासियों के विकास पर विशेष ध्यान देने की जरुरत

रांची। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने कहा है कि झारखंड में हाल के कुछ वर्षों में मानव संसाधन के विकास समेत अन्य क्षेत्रों में बेहतर काम किया है, लेकिन अब भी झारखंड जैसे राज्यों के समक्ष कई चुनौतियां है, इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाये जाने की जरुरत है।

वित्त आयोग के अध्यक्ष ने गुरुवार को मुख्यमंत्री, मंत्रियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करने और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद प्रेस वार्ता में झारखंड के विकास के प्रिप्रेक्ष्य में कई यूनिक समस्याओं का जिक्र करते हुए कहा कि यहां खनन से वाले पर्यावरणीय क्षति, बड़ी संख्या में जनजातीय आबादी और उनका अब तक समुचित विकास नहीं हो पाना, खनिज से मिलने वाली रॉयल्टी समेत कई मुद्दे सामने आये है। इसके अलावा झारखंड के विभिन्न जिले कई मापदंड में पिछड़े है, इन विषयों को लेकर सरकार की ओर से विस्तृत प्रतिवेदन आयोग के समक्ष बेहतरीन तरीके से रखा गया। उन्होंने बताया कि हाल के कुछ वर्षों में शिशु मृत्यु दर, शिक्षा, मानव संसाधन के विकास और खर्चकरने की स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई चुनौतियां अब भी बरकरार है। उन्होंने कहा कि बैठक में जीएसटी लागू होने के बाद मिलने वाले राजस्व को लेकर विस्तृत चर्चा हुई, लेकिन अभी इन आंकड़ों के अध्ययन की जरुरत है। आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि अब तक जनआकांक्षाएं पूरी नहीं हुई है, तीन वर्ष में कई प्रयास किये गये, लेकिन एक बड़ी चुनौती यहां रहने वाली करीब 27 प्रतिशत जनजातीय आबादी का विकास भी है।

उससे विकास दर को एक नया

एक प्रश्न के उत्तर में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग नहीं की गयी है, हालांकि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा इसकी मांग की गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार को वर्ष 2011 की जनगणना को टर्म ऑफ रेफरेंस बनाये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने यह भी साफ किया कि आयोग पूरी तरह से स्वतंत्र और संवैधानिक दर्जा प्राप्त संस्था है, इसलिए संस्था के कामकाज पर कोई राजनीतिक दबाव नहीं होता।

एन.के. सिंह ने कहा कि झारखंड के इकॉलोजी और खनन से पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, रॉयल्टी आदि समेत अन्य विषय आये है, इस पर विचार करने की जरुरत है। उन्होंनेकहा कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने बैठक में यह स्वीकार किया कि कई पंचायतों को जितनी राशि उपलब्ध करायी गयी, वह मानव संसाधन की कमी के कारण खर्च नहीं हो सकी, इसलिए मानव संसाधन क्षमता में वृद्धि की जरुरत है।

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम - The Telegraph
2. समाचार पत्र की भाषा - English
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि - Daily

State calls for special attention

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

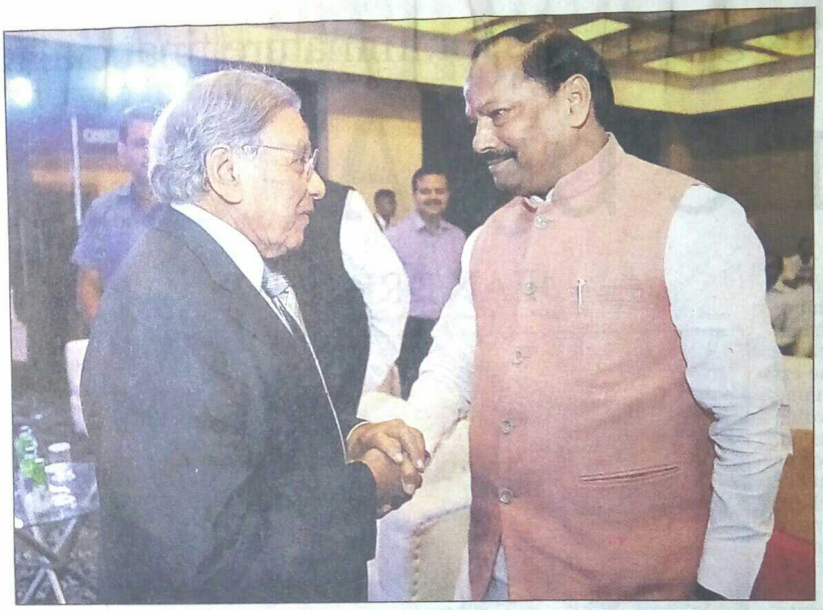

Chairman of the 15th finance commission NK Singh with chief minister Raghubar Das in Ranchi on Thursday; leader of the Opposition Hemant Soren (right) at the meeting.
Picture by Prashant Mitra

Ranchi: Jharkhand demanded Rs 1.50 lakh crore from the 15th finance commission during daylong deliberations with visiting members on Thursday, explaining that it was grappling with severe challenges to improve infrastructure and social indices for which the Centre needed to pay special attention.

"The state is still struggling for basics like proper irrigation facilities, clean drinking water in remote areas, education, health and so on," chief minister Raghubar Das said during a meeting with commission members where officials from various departments made presentations.

"We are working on this through several central as well as state schemes, but there much that needs to be done," he added.

A team of commission members has been in Jharkhand since Wednesday. After their meeting with the chief minister and senior officials, the team met all Opposition parties to discuss their demands and priorities for the state.

According to an official present at Thursday's deliberations, Jharkhand sought funds are various sectors. "Under agriculture, forestry, irrigation and water, we demanded around Rs 42,000 crore, under social sectors covering health, education etc, we sought Rs 17,000 crore, and for infrastructure etc, we sought Rs 88,000 crore," he said.

Commission chairperson N.K. told the media that they had had meaningful discussions and would consider paying special attention to Jharkhand.

"It is clear that since the state was formed, it has not been able to achieve its full economic potential for various reasons. The poverty rate still continues to be higher, and in some districts, the problem is more. Though, in the last few years, significant improvements have happened, it's good that the government is clear about its challenges ahead," he said, adding that sympathetic treatment was required to reorganise funds.

Later, additional chief secretary, finance, Sukhdev Singh said the main concern for Jharkhand was rising debt (gross state domestic product) though it was still less than other states.

"But we are now cautious about reversing it. In 2014-15 fiscal year, the debt ratio was 20 per cent, which got increased to 24 per cent in 2015-16. In 2016-17, it was 26 per cent. The 14th finance commission has set a limit of the debt ratio at 25.16 per cent. So we are borderline, but need to re-prioritise things faster," he told **The Telegraph**, adding that Uttar Pradesh, Punjab, West Bengal and a few other states had a much higher debt ratio.

Singh said one of the reasons why Jharkhand's debt was increasing was UDAY (Ujwal Discom Assurance Yojna), launched by Centre three years back to revive the ailing power sector. Under this, states needed to take over three-fourths of the debt of respective discoms. Discoms were given time till 2017-19 to become self-sufficient by improving transmission, curbing thefts among other measures.

"This led to huge investments, though we are on path of reviving our discoms here," he said. Another reason, he said, was that funds remaining unspent in PL accounts were adjudged as debt.

Singh said they suggested a formula for devolution of funds. "For example, we have 26 per cent tribal population. So, funds should be given keeping their social, economical status in mind. Similarly, we demanded that at least 10 per cent devolution of funds on the basis of mining/quarrying done keeping in mind the social and ecological costs," he explained.

Opposition leader Hemant Soren told the commission to ensure the focus of funds devolution was based on genuine needs rather than Centre's populist measures. "In the terms of reference of the 15th finance commission, there is a clause in para-4, sub-para-6, wherein Centre advises the commission that its (Centre's purse) is already under pressure due to suggestions of 14th finance commission and GOI's plans for New India-2022. And therefore, 15th commission should take these into consideration before making its recommendations. Can Centre bind Commission with such rules?," he asked.

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष :– 0651–2551102

फैक्स :– 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – hindustan times
2. समाचार पत्र की भाषा – English
3. प्रकाशित दिनांक – 03·08·18
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

Hemant meets finance commission, objects to using 'New India-2022'

Vishal Kant
Vishal.kant@hindustantimes.com

RANCHI: Leader of opposition and working president of Jharkhand Mukti Morcha (JMM), Hemant Soren, on Thursday objected to inclusion of the phrase 'New India-2022' in the terms of references of the 15th finance commission that met the representatives of the political parties on the second day of its three-day visit to the state.

In his address at the meeting, the former chief minister said, "Why has New India-2022 been included in the terms of references? It's a political slogan of the Bharatiya Janata Party. Allocating funds for it should not be the agenda of the finance commission. Politicisation of constitutional bodies is not correct."

The junior Soren said the Centre and states were players while the finance commission's role was of an umpire.

On the issue of finance commission planning to reward states that curtail expenditure on populist schemes, the former chief minister, referring to some of the schemes and developments projects of the Raghubar Das government, said the biggest challenge would be in defining which schemes were populist and which were not.

"Who will ascertain whether any scheme is populist or for people's welfare. Will the finance commission define it? If the Jharkhand chief minister decides to give a grant of Rs 1 lakh to pilgrims going on Mansarovar Yatra, who would decide that the scheme is populist or not," the former chief minister said.

The JMM president also referred to the ongoing 'Times Square' project at Morabadi ground to buttress his point.

Leader of opposition Hemant Soren at the meeting of 15th Finance Commission in Ranchi on Thursday. HT PHOTO

With the Indian tax system having shifted to Goods and Service Tax (GST) regime, the former chief minister suggested that a representative of the GST Council should also be there in the finance commission.

On the issue of the finance commission planning to incentivise states, in terms of enhanced fund allocation, which have total fertility rate (TFR) less than 2.1, the JMM leader objected to the proposal arguing that prevalence of high TFR is directly related to poverty and concentration of higher population of tribals, Dalits, illiterate and poor.

"States such as Madhya Pradesh, Bihar, Utter Pradesh, Chhattisgarh and Jharkhand fall in that category. In fact, such states need more resource for reducing TFR. It would prove disastrous in states like Jharkhand where decline in population of the tribals and aborigines is a cause for concern," Soren said.

He said tribal population in any state should be included in the parameters for devolution of funds.

CONGRESS POINTS OUT PER CAPITA INCOME ANOMALY

Vishal Kant
vishal.kant@hindustantimes.com

RANCHI: Jharkhand Congress chief Ajoy Kumar said here on Thursday that his party had requested the 15th finance commission to put in place a mechanism that gave separate figures of Jharkhand's per capita income for the urban and rural areas, as the current system did not reflect the correct status of the citizen's income due to presence of several big public and private companies.

"There are several companies like Coal India, SAIL and Tata Steel. So the per capita income of the state is lopsided and it does not reflect the true picture of people's condition. Around 48% of Jharkhand's population is below the poverty line against the national figure of 29%. Therefore, we have demanded separate per capita income figures for the urban and rural areas," Kumar told reporters here at the state party headquarters.

Ajoy Kumar

Kumar on Thursday led a delegation of the party workers at the meeting of the 15th finance commission with the representatives of all political parties. The 15th finance commission team is on a three-day visit to Jharkhand.

Kumar said he had demanded a special package for the state owing to the prevailing condition of education and health sector in the state.

"The state fulfills four of the five parameters for grant of a special status. Around 27% of the state population is tribal which itself is a ground for special package," he added.

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

दूरभाष - 0651-2551102

फैक्स - 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम - hindustantimes
2. समाचार पत्र की भाषा - English
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि - Daily

J'khand places Rs 1.5 lakh cr demand to finance panel

Gautam Mazumdar
gautam.mazumdar@livehindustan.com

RANCHI: The Jharkhand government on Thursday placed Rs 1,50,002.73 crore demand to the 15th finance commission, an increase of Rs 8,000 crore it had made before the 14th finance commission.

Chief minister Raghubar Das put the demand during the meeting with the visiting team of the 15th finance commission led by chairman NK Singh.

Das pleaded the commission to pay special attention towards the undeveloped states like Jharkhand and expressed hope that it will consider Jharkhand's wishes with an open heart.

The 14th finance commission had allotted Rs 4,778.50 crore to Jharkhand out of which Rs 4,279.8 crore has been released.

While making the state presentation, it was brought before the commission's notice that Jharkhand has 26.20% ST population, 36.51% BPL population and 75.95% rural population.

Chief secretary Sudhir Tripathi, and additional chief secretary holding the finance department Sukhdev Singh along with other officials were present.

The commission admitted that the problems of Jharkhand were both generic and unique and said the commission would go through the suggestions and demands thoroughly before making recommendations.

Out of the total 1.5 lakh crore demand, agriculture, forestry, irrigation and drinking water constitutes Rs 42,598.02 crore, social sector (health, nutrition, women & child development and education) mentions of Rs 17,001.39 crore, infrastructure, that include core capital city in Ranchi consists of Rs 88,199.66 crore. Besides, Rs 2,203.66 crore has been demanded for revenue and general administration.

Chief minister Raghubar Das handing over a memorandum of the state government to the 15th Finance Commission chairman NK Singh, in Ranchi on Thursday. DIWAKAR PRASAD/HT PHOTO

Appreciating the government's presentation and initiatives commission chairman NK Singh said he was happy with the presentations during the two day deliberations with the state government, local bodies and political parties.

He, however, suggested the state to pay attention on fiscal deficit and debt to equities besides efficient and optimum use and management of its resources. He also stressed on increasing the per capita expenditure.

Finance secretary Singh admitted that the fiscal deficit limit of Jharkhand was 26% of the GSDP in 2016-17 and mentioned that it should not be more than 25.16%.

However, going through the presentation the commission chairman mentioned that it is alarming though it is well below other states.

The state admitted that there was a fall of 7.7% in GSDP in the past three years. It also expressed concern over improper utilization of Central loan under UDAY bond taken in 2015 to rescue the ailing state power distribution utilities and bring down transmission and distribution losses.

The state had taken Rs 5,553 crore loan under UDAY scheme but utilized the money mostly to pay DVC and CCL dues.

Singh expressed concern over prevailing poverty and the laxity in the state's realisation despite having economic potentials. The government is aware of the economic challenges and closer to national economic index, he said.

Being mineral rich state with sizeable tribal population Jharkhand should stress on environmental management and balanced growth in all districts, he said.

On GST the state mentioned that during August 2017 to June 2018, the average GST revenue was Rs 498 crore (an average monthly shortfall of almost 31%). It feared that in the post compensation period (2022-23) Jharkhand's revenue is likely to decline by Rs 1,295 crore adding that due to structural and other changes, Jharkhand has suffered a huge loss of Rs 3,492.73 crore.

Singh said GST is a major concern of all the states and the commission would look into the matter.

He said the presentations and demands of the local bodies were impressive and very useful. He appreciated the joint memorandum of the panchayat bodies saying it "unique".

The commission had met them on Wednesday.

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102
फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – The Times of India
2. समाचार पत्र की भाषा – English
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

Finance Commission worried about failure in adhering to FRBM Act

Jaideep.Deogharia
@timesgroup.com

Ranchi: The Finance Commission on Thursday expressed its concern about the frequent incidents of poverty, wide inter-district disparities and recent failure in adhering to the Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act in the state. The 15th Finance Commission team under the chairmanship of N K Singh is on a three-day visit to the state for consultation with various stakeholders to decide its recommendations.

While holding the meeting with chief minister Raghubar Das and a team of bureaucrats from his government on Thursday, the chairman noted that despite some significant improvement with respect to key indices of human resource development, infant mortality rate, education index and composition of expenditure like capital vs revenue expenditure, Jharkhand is far behind in addressing the issue of poverty. He said, "Expectations with which the state was created, for it to achieve a fast growth and rapidly catch up with India's fast growing economy remains an unfulfilled dream."

Mahadeo Sen

CM Raghubar Das hands over a memorandum of the state government to N K Singh, chairman of the 15th Finance Commission

He added that till 2010-11 there has been a broad adherence to the FRBM Act. "However, in the last three years there has been deterioration in both fiscal deficit as well as debt-to-GDP ratio," Singh said, while admitting that this was mainly because of government's effort to address the challenges of economy.

The commission also recognised that Jharkhand requires sympathetic treatment and reward for efficient use of resources while addressing the endemic issues of backwardness. Singh said the special characteristics of the state should also be given due consideration. "It has a high tribal population and is seeking to counter the challenges of ecological and environmental degradation while sustaining growth momentum," he added.

Das, on the other hand, reminded the commission about the peculiarities associated with the tribal population and its culture, which needs a customised approach for their development.

"The negative externalities borne by the mining states should be taken into account so as to provide them with adequate compensation. The benefit of access accrues largely to those States that use minerals as input for their industrial activities," he said while answering the commissions concerns about Jharkhand not being able to reap benefits of GST as was evident in other states.

Representatives of different political parties also extended suggestions to the commission. Congress state president Ajoy Kumar spoke about the need for special status to the state while AJSU representative spoke about inclusion of environment protection and pollution as one of the components that requires special attention.

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची
***

ई-मेल / स्पीडपो

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन
नियर- आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, राँची-834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम - The pioneer
2. समाचार पत्र की भाषा - English
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि - Daily

CM seeks FC attention to 'poor' Jharkhand

PNS ■ RANCHI

Stressing over the need of more resources for under-developed States like Jharkhand, Chief Minister Raghubar Das has urged the 15th Finance Commission to pay proper attention to it.

The CM during his meeting with the touring Commission members headed by its Chairman NK Singh on Thursday said that pulling the lagging States up was equally essential for a developed India. "The Finance Commission should focus more on under-developed States such as Jharkhand. Only if such States are developed the country can develop which is the dream of Prime Minister Narendra Modi," said the CM.

Talking about the strengths of the State Raghubar Das underlined scope in tourism sector, which besides being different from mining sector can produce more number of jobs.

"We have world class tourist spots in the State that can generate good number of jobs. This would also bring in foreign currency. At the same time we have certain challenges like 19 out of 24 districts are into aspirational district bracket. We are building new capital along with High Court building, Assembly and many others. The State needs

Continued on Page 2

Chief Mininster Raghubar Das alongwith Chairman Finance Commission Nand Kishore Singh releases a report of 15th Finance Commission of Jharkhand during a meeting in Ranchi on Thursday. Food and Public Distribution Minister Saryu Roy, Health Minister Ramchandra Chandravanshi alongwith members of 15th Finance Commission are also seen in the picture Ratan Lal

CM seeks FC attention to 'poor' Jharkhand

From Page 1

substantial amount of fund for all that," said the CM. Sources present said that more than Rs one lakh crore in the next five years has been sought from the Finance Commission.

The CM at the same time outlined 14 years of instability in the State for its shaky development record. "Tribal and poor people of the State have put in their lives for a separate State but their dream could not be fulfilled due to prolonged political instability at the top. There is no dearth of natural resources which is now put in together for ensure speedy growth.

We need to do lot more to pull people out of deprivation and for that more fund is required," explained the CM.

He on the occasion also outlined some of the performances under his regime like taking power to all the villages of the State which is now being taken to every household by 2018. The CM also talked about the seven flagship schemes of the Center under which 6512 villages under gram swaraj are being benefited.

"Farm sector has more jobs but due to lack of irrigation facility we are unable to perform well. Similarly we have worries on the front of mining where large numbers of people are compelled to drink polluted water and catch diseases of different kind. We are utilising DMF to provide piped drinking water to them," said the CM.

Earlier the team of the Commission was shown detailed presentation from different Departments which placed their specific track records along with demands. Besides the CM, his Cabinet colleagues Ramchandra Chandravansi, Neera Yadav, Saryu Roy, Raj Paliwar, Chief Secretary Sudhir Tripathi, Development Commissioner DK Tiwari, Additional CS Sukhdeo Singh, members of the Commission Shaktikant Das, Ramesh Chandra, Anup Singh, Ashok Lahiri and heads of all the Departments with the State Government were present in the meeting.

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम - The pioneer
2. समाचार पत्र की भाषा - English
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि - Daily

Opposition questions Finance Commission's terms of reference

PNS ■ RANCHI

JMM executive president Hemant Soren, JPCC chief Ajoy Kumar alongwith other party leaders at an all-party meeting with Finance Commission members at a city hotel in Ranchi on Thursday PNS

Parties in the Opposition came united in criticising the terms of reference (TOR) of the 15th Finance Commission. Parties right from the main Opposition JMM to Congress and JVM questioned the freedom given to the Commission by the Union Government in deciding funds and resources to any State, including Jharkhand.

JMM executive president and Leader of the Opposition Hemant Soren in his meeting with Chairman NK Singh and other members of the Commission on Thursday pulled up the TOR set by the Center which suggests the criteria to decide the references given to any particular State.

"I would like to call the attention of the Commission towards the limitation put in place through the TOR for the Commission in deciding funds. It says that due to the recommendations of the 14th Finance Commission and the schemes taken under the New India-2022 resources with the Center are limited and thus the Commission should take that into consideration. This is akin to limiting the Commission and its autonomy. Then the TOR says about populist schemes and for avoiding such measure taken by any State. Who would decide which scheme is populist or otherwise," said Hemant Soren citing example of 'Times Squre' like structure coming up at Morhabadi of Ranchi.

The LoP went on denouncing the idea to pay less to the States with higher Total Fertility Rate and argued that poor and developing States like Jharkhand have this problem as legacy. "The TOR says that the States with lower TFR i.e. less than 2.1 should be encouraged and given more fund. This is ironical that poor States like Jharkhand due to their limitations and higher number of SC, ST living there, record higher TFR. It would bizarre to deprive the needy States even further with resources," added the JMM leader. He then pointed out the reduction done into fund allocation from the Center to Jharkhand following the GST regime while calculating the loss in the tune of Rs 2500 crore in terms of revenue generation to the State. "The 15th Finance Commission should have shown flexibility in the changed tax regime which is not there.

GST Council is more democratic setup at present. Power of States to levy taxes has gone and they are dependent on the GST Council.

In this scenario a representation of GST Council should also have been in the Finance Commission. Jharkhand would face shortfall of 30 per cent in tax collection which would be borne by the Center till 2022 but what after that.

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी, रॉची–834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम – Reporter Post
2. समाचार पत्र की भाषा – English
3. प्रकाशित दिनांक – 03.03.18
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

Finance Commission to have sympathetic approach towards unique problems of Jharkhand: N K Singh

By Our Correspondent

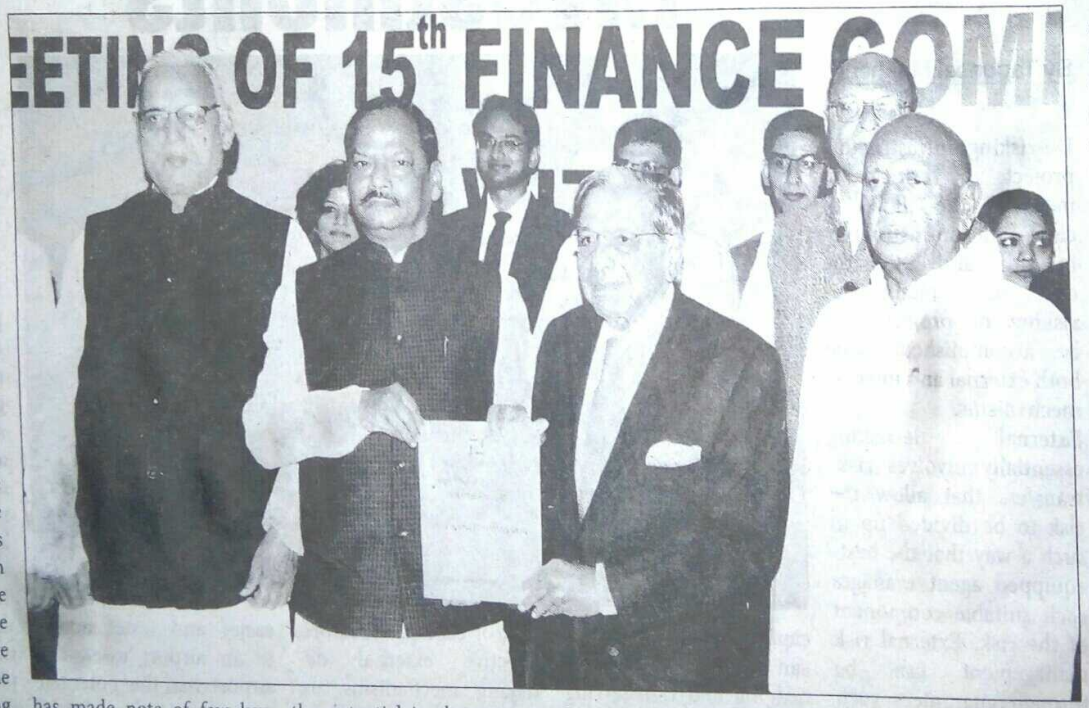

Ranchi : Chairman of the 15th finance commission N K Singh said that the body will have a sympathetic approach towards the unique problems of the state keeping in mind the huge tribal population and the slow start of progress.

Addressing a press conference here after meeting with the Chief Minister and his cabinet colleague which was followed by a meeting with the political parties of the state he said that some problems of Jharkhand were common with other states while some others were unique. "These unique problems will require sympathetic approach of the commission," he said adding that specific attention will be provided to the state keeping in mind the huge tribal population and the slow start of progress in the state. He said that the commission has made note of few key observations during its interaction here with the first being that the full potential of the economy of the state is yet to be realized. He said that it was expected that with the potential in the state it was expected to grow much faster and stand among the developed states of the nation however that has remained un-utilised. Mr Singh said that the commission was also alarmed with the rising poverty in the state and also pointed to high disparity with some of the districts having a large number of poor population. He also pointed that containment of the fiscal deficit was an issue for the state, however he pointed that the state government has made some significant improvement in key indices of health and human development index. When asked the suggestions which the commission had given to the state government he said that there was a need to look at sustainable development indicators in few of the districts while fiscal deficit also needed to brought down by following a moderate considerable path. Moreover the state also needed to look at the issue of Uday bonds and improve its transmission and distribution network etc. He said that the state government has made a genuine case of increasing the vertical devolution and has presented a detailed well articulated list of demands through which it has demanded that the state share be increased to 50 per cent and has also advocated for the need to relook at the horizontal devolution distribution formula. However to a query he said that the state government has demanded for any special status state category.

ई–मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, रॉची
***

दूरभाष – 0651–2551102

फैक्स – 0651–2551103

शिव भवन लेन
नियर– आर के मिशन आश्रम
मोराबादी रॉची–834008

विषय : कतरनें का प्रेषण।

दिनांक

1. समाचार पत्र का नाम – REPORTER POST
2. समाचार पत्र की भाषा – English
3. प्रकाशित दिनांक – 03.08.18
4. प्रकाशन शहर – Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि – Daily

Raghubar asks finance commission to accord special focus towards Jharkhand

CM urges for more funds to fulfill the needs of people

By Our Correspondent

Ranchi : Jharkhand Chief Minister Raghubar Das said that due to 14 years of political instability Jharkhand could not achieve the goal behind formation of a separate state however after the state government has been formed development has gathered pace in the state and urged the commission to accord special focus towards state like Jharkhand and demanded for more funds to fulfill the needs of the people In a meeting with the team of the 15 finance commission he said that state now posses all favourbale ingredients for development due to which rapid work was being done in the area basic infrastructure. He said that Jharkhand also posses abundance of natural wealth and a trained man power but people were forced to live a life of poverty. He said that despite the rapid progress there are still many areas which needed to be addressed. He asked the commission to accord more focus on un-developed states and said that when the backward states will be developed than only the nation can be fully developed and pointed that even Prime Minister Narendra Modi shared the dream of development of all the nations. The Chief Minister pointed that whether it was the war of Independence or the movement for a separate state of Jharkhand the tribals have played a very vital role and now time has come that changes are also brought in their lives, and they too can get access of good roads, water and power as when these things will reach in the village than a quality change would be brought in their lives. Mr Das said that all the villages of the state have been electrified and now in every home power will be provided as the state government was working with the target to illuminate all the homes by December 2018. He said that the advantage of the seven flagship schemes of the state government are being reached to the people and in the second phase of the gram swaraj abhiyaan these schemes will be completely implemented at 6512 villages apart from that in 3312 villages were the population of the tribals was more than 1000 they would be also covered under the scheme.

ई-मेल / स्पीडपोस्ट

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार, राँची

***

दूरभाष :- 0651-2551102

फैक्स :- 0651-2551103

शिव भवन लेन,
नियर- आर के मिशन आश्रम,
मोराबादी, राँची-834008

दिनांक

विषय : कतरनें का प्रेषण।

1. समाचार पत्र का नाम - Reporter Post
2. समाचार पत्र की भाषा - English
3. प्रकाशित दिनांक - 03.08.18
4. प्रकाशन शहर - Ranchi
5. प्रकाशन की अवधि - Daily

Opposition parties demand special status from planning commission

By Our Correspondent

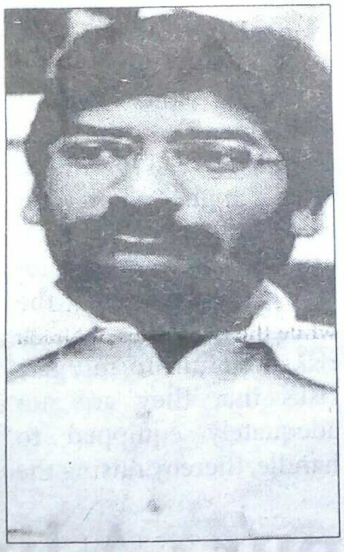

Ranchi : In an interaction with the team of the 15th finance commission the majority of opposition political parties of the state sought a special category status pointing out the backwardness of Jharkhand and highlighted the fact that the state was also got getting the due share of its mineral royalty due to which the farmers and poor were battling displacement and poverty. Leader of the opposition and JMM acting president Hemant Soren raised questions over the mention of New India-2022 in transfer or resources and said that it was a political slogan of the BJP and the commission has no right to allocate funds for this. He also raised questions over awarding of more funds to such states which have performed better to reduce the infant mortality rate and malnutrition. He alleged that as part of a hidden agenda the central government was planning something big in the disguise of the commission as the right of imposing the taxes has been given to the GST council instead of the parliament. He said that it appears that slowly the states would be denied many schemes and their benefits. Congress state president Dr Ajay Kumar said that Jharkhand should be given the status of a special state as it fulfills the four out of the five criteria's which are needed for any state to be awarded the status of special state. He pointed that due to corporate houses the per capita income in Jharkhand appears to be high but in reality 38 pc population here live below the poverty line and performance of the state in the area of health and education was very poor. JVM(P) MLA Pradeep Yadav said that not only in the reality but the state should also have a share in the profit of the companies. He also called for providing special state status and raised questions over increasing the state's share in various schemes. On the other hand Bhuvneshwar Mehta of the CPI despite having abundance of resources the people are forced to migrate and tribals are forced to drink impure water therefore the commission should pay attention towards these and grant aid to the state. On the other hand AJSU party which is a junior ally in the state government said that Jharkhand generates maximum revenue for the railways but compared to that train and facilities for the people were not worth mentioning. Party's central spokesperson Devsharan Bhagat demanded that headquarters of the SE Railways be shifted to Jharkhand from Kolkata and also demanded to increase the grants of the panchayats and urban local bodies. On the other hand the state general secretary of the BJP Deepak Prakash said that due to political instability the state could not develop much but things have changed after 2014 and suggested for simplification of forest conservation laws. He also demanded grants for completing pending irrigation projects, tourism, rail infrastructure development, police modernization etc.